चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 29 नवंबर–05 दिसंबर 2010

मूल्य 5 रुपये

अब भी न चेते तो कुछ न बचेगा

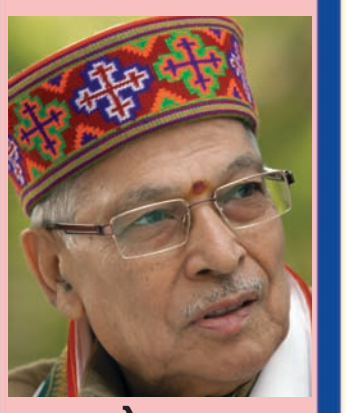

पेज-3

एक और अयोध्या

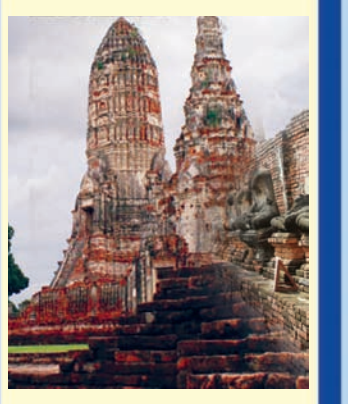

पेज-7

ओबामा का भारत प्रेम सिर्फ़ एक दिखावा है

पेज-11

साई की महिमा

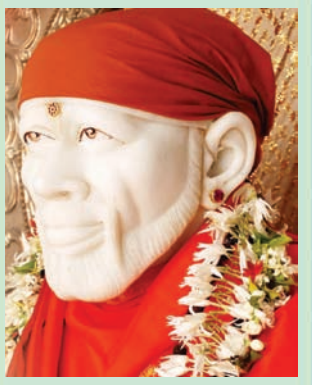

पेज-12

प्रधानमंत्री जी इस्तीफ़ा मत दीजिए

देश में आम चर्चा है कि ऐसी सरकार का नेतृत्व मनमोहन सिंह कब तक करेंगे. राजनैतिक क्षेत्रों में माना जा रहा है कि वह त्यागपत्र की पेशकश सोनिया गांधी के सामने कर चुके हैं. हमने एक संक्षिप्त और त्वरित सर्वे कराया, जिसमें बहुमत ने कहा, प्रधानमंत्री जी, अभी इस्तीफ़ा मत दीजिए.

पहले आईपीएल घोटाला, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, फिर आदर्श सोसाइटी घोटाला और फिर 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला. ऐसा लग रहा है, मानों प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल गई है. भारत में प्रजातंत्र के 60 साल के बाद देश के लोगों को लगने लगा है कि हमारे सरकारी तंत्र का हाल यह है कि नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो या फिर कोई और, जिसे जहां भी कुछ अधिकार प्राप्त है, वह लूटने में लगा है. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में विपक्ष ने जेपीसी की मांग की तो सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया. संसद की कार्रवाई ठप्प रही. फिर डीएमके नेता मारन की चिट्ठी मीडिया में आई तो प्रधानमंत्री ख़ुद निशाने पर आ गए. इस दौरान टेलीफोन पर हुई बातचीत का टेप सार्वजनिक हुआ तो मामले को नया स्वरूप मिल गया. दिल्ली की सरगर्मियों के बीच कर्नाटक से एक और ज़मीन घोटाला उजागर होने से भाजपा भी कठघरे में आ गई. चौथी दुनिया ने देश के कई सैन्य क्षेत्रों में ज़मीन घोटाले का पर्दाफ़ाश करके पूरे तंत्र के चेहरे पर कालिख पोत दी. लगता है घोटाले की, घोटाले के द्वारा और घोटाले के लिए हमारे देश में सरकारें चल रही है.

पहली बार सरकार चलाने की मजबूरी और प्रधानमंत्री द्वारा वक्त पर सही निर्णय न लेने की वजह से सौ करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क पर सवालिया निशान लग गया है. आज़ाद भारत में पहली बार राजनीतिक सत्ता को शर्मसार होना पड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री से एफीडेविट मांगा. एफीडेविट का मतलब शपथ पत्र होता है. अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से वैसे भी जानकारी मांग सकता था. शपथ पत्र मांगने का मतलब तो यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई झूठा जवाब भी मिल सकता है. तभी तो एफीडेविट मांगा गया है. यह सचमुच एक शर्मनाक़ स्थिति है. प्रधानमंत्री कार्यालय कितना चुस्त-दुरुस्त है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी की एक साधारण सी चिट्ठी का जवाब देने में उसे पंद्रह महीने से ज़्यादा वक़्त लग गया. सुब्रमण्यम स्वामी सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं. प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है. अगर पूर्व सांसद एवं मंत्री की चिट्ठी का जवाब मिलने में इतनी लापरवाही हुई है तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीएमओ आम जनता से कितनी दूर है. वैसे यह कोई अजूबा नहीं है. ऐसे कई सांसद हैं, जो यह शिकायत करते हैं कि पीएमओ की यह आदत सी बन गई है. किसी सांसद या मंत्री की चिट्ठी का जवाब देना तो दूर, वह उसकी पावती तक नहीं भेजता है. पीएमओ के बारे में हम यह इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि वह सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, सत्ता का न्यूक्लियस है. अगर वह चिट्ठी जैसा सामान्य काम भी नहीं कर सकता है तो देश कैसे चलाएगा या फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि पीएमओ में काम करने वाले लोग ही क़ाबिल नहीं हैं.

2-जी स्पेक्ट्रम का जो मामला है, वह 1.7 लाख करोड़ रुपये का घोटाला है. इतनी तो दुनिया के दो तिहाई देशों की जीडीपी भी नहीं है. इस बीच डीएमके नेता दयानिधि मारन जो पिछली यूपीए सरकार में दूरसंचार मंत्री थे, की चिट्ठी आ गई, जिससे यह पता चला कि किस तरह एक मंत्री ने प्रधानमंत्री को यह सलाह देने का दुस्साहस किया कि वह 2-जी स्पेक्ट्रम से दूर रहें. चुनाव के बाद फिर से यूपीए सरकार बनी, जिसमें ए राजा को मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग हुई. यह बड़े पत्रकारों, मंत्रियों, उद्योगपतियों एवं आईएएस अधिकारियों के बीच के गठजोड़ का साफ़-साफ़ खुलासा है. पत्रकारों के संगठन या पत्रकार इस कुख्यात गठजोड़ के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं.

इस खेल में एक तीसरा पहलू भी है. वह पहलू अधिकारियों का है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है. सवाल यह है कि देश में इतना बड़ा घोटाला अधिकारियों की साठगांठ के बिना कैसे संभव है. यह पता लगाना भी ज़रूरी है कि वह कौन आईएएस अधिकारी है, जिसने इस पूरे घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई है. समझने की बात यह है कि हमारे देश में सरकार चलाने का जो तौर तरीक़ा है, उसमें बिना अधिकारी से साठगांठ किए किसी भी घोटाले को अंजाम देना असंभव है. देखा यह जाता है कि घोटाले के सामने आने के बाद राजनीतिक अधिकारियों और मंत्रियों पर तो गाज गिर जाती है, लेकिन समस्या यह है कि हर बार घोटाले के असली किरदार यानी आईएएस अधिकारी बिना किसी सज़ा के छूट जाते हैं. इस घोटाले में भी ऐसा होगा. लेकिन प्रधानमंत्री ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए यह उम्मीद है कि इस बार वह भ्रष्टाचार के इस महाकेंद्र को साफ़ करने की पहल करेंगे, अगर वह सचमुच भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं तो.

भ्रष्टाचार को लेकर संसद में हंगामा होता रहा. सांसदों ने कोई भी कार्रवाई नहीं चलने दी, लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे सांसद हैं, अपने दायित्व के प्रति इनका यह कैसा रवैया है. ये साल भर कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं. ये तभी जागते हैं, जब परिस्थितियों का दबाव आता है. जब कोई मामला मीडिया में उठता है, तब इनकी नींद टूटती है और ये लोकसभा में हंगामा करते हैं. समस्या यह है कि आज के सांसद ख़ुद अध्ययन नहीं करते हैं, जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं. देश में कहां गड़बड़ी हो रही है, इन्हें इसकी भनक तक नहीं रहती. ऐसे में हमें भूपेश गुप्ता, हिरेन मुखर्जी, नाथ पाई, एच वी कामत, पीलू मोदी, राज नारायण और चंद्रशेखर की याद आती है, जो संसद में हमेशा पूरी तैयारी और पूरा अध्ययन करके देश के बुनियादी सवालों, जनता से जुड़ी समस्याओं और सरकार की नाकामी पर बयान देते थे, जिससे सत्ता पक्ष का कलेजा दहल जाया करता था. मीडिया वाले इन सांसदों से मिलकर जानकारी लेते थे, ख़बरें लिखते थे. आज के सांसद ही उस स्तर के नहीं हैं. अब गंगा उल्टी बह रही है. नींद में सो रहे सांसद तभी जागते हैं, जब मीडिया में कोई रिपोर्ट आती है. आज के सांसदों की जानकारी का एकमात्र ज़रिया मीडिया में छपी रिपोर्ट होती है. यही वजह है कि सरकार चलाने वाले मंत्री या अधिकारी या फिर दलाल क़िस्म के लोग दुस्साहसी हो गए हैं.

मीडिया में एक आडियो टेप के सार्वजनिक होने से हंगामा मच गया, जबकि यह मामला पुराना है. इस टेप से यह साबित होता है कि देश में किस तरह नेताओं, आईएएस अधिकारियों, उद्योगपतियों और दलालों ने पूरे तंत्र में अपना मायाजाल फैला रखा है, जो बड़े से बड़े घोटाले को अंजाम देने में महारथ हासिल कर चुका है. इस टेप से यह भी पता चलता है कि देश के तंत्र पर दलालों की पकड़ इतनी मज़बूत हो गई है कि कैबिनेट मंत्री कौन बनेगा या कौन नहीं, वे इसे तय करने का दुस्साहस करने लगे हैं. चौथी दुनिया ने क़रीब पांच महीने पहले दलालों की इस टोली का पर्दाफ़ाश किया था. हमने दलाली के इस खेल में नीरा राडिया, मशहूर टीवी एंकर एवं एनडीटीवी की मैनेजिंग एडिटर बरखा दत्त और हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक वीर सांघवी की करतूत को उजागर किया था. अब इन लोगों के बीच हुई बातचीत का टेप सार्वजनिक हुआ है. इस टेप से यह पता चलता है कि ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनाने के पीछे का राज़ क्या है. क्यों दलालों की यह टोली ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी और डीएमके के बीच मध्यस्थता कर रही थी. क्यों बड़े-बड़े नेता इस डील में शामिल थे और वे कौन लोग हैं, जिन्होंने राजा को मंत्री बनाने के लिए दलालों की टोली से यह काम कराया. दरअसल, 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला न सिर्फ़ बड़ा है, बल्कि यह देश के सरकारी तंत्र में मौजूद भ्रष्टाचार के कोढ़ का आईना है.

जितने अंतर्विरोध और दबाव बढ़ रहे हैं, उनसे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि मनमोहन सिंह इस्तीफ़ा दे दें. प्रधानमंत्री का अपना दोष है या फिर उन्होंने दबाव की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की. आख़िर कोई तो वजह ज़रूर रही होगी कि न सिर्फ़ सहयोगी दलों के मंत्रियों को, बल्कि अपनी पार्टी के मंत्रियों को भी कुछ भी करने की खुली छूट दे दी गई है. प्रधानमंत्री के नजदीकी सहयोगियों का कहना है कि मनमोहन सिंह ने दो बार सोनिया गांधी से अपने इस्तीफे की पेशकश की, पर उच्च पदों पर विराजमान लोगों के भ्रष्टाचार से लड़ने का समाधान त्यागपत्र नहीं होता. प्रधानमंत्री जी, यह वक्त निर्णायक और सार्थक क़दम उठाने का है.

विशेष संवाददाता

feedback@chauthiduniya.com

यह राजनीतिज्ञों,सांसदों,पत्रकारों और सत्ता के दलालों की मिलीभगत की ऐसी कहानी है जो भारतीय राजनीति की असलियत बयां करती है. *चौथी दुनिया* ने इसका ख़ुलासा पांच महीने पहले ही किया था. पेश हैं उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के कुछ अंश...

ये बड़े पत्रकार हैं या बड़े दलाल

बरखा दत्त और वीर सांघवी. दो ऐसे नाम, जिन्होंने अंग्रेज़ी पत्रकारिता की दुनिया पर सालों से मठाधीशों की तरह क़ब्ज़ा कर रखा है. आज वे दोनों सत्ता के दलालों के तौर पर भी जाने जा रहे हैं. बरखा दत्त और वीर सांघवी की कारगुज़ारियों के ज़रिए पत्रकारिता, सत्ता, नौकरशाह एवं कॉरपोरेट जगत का एक ख़तरनाक और घिनौना गठजोड़ सामने आया है. देश की जनता हैरान है कि एनडीटीवी की ग्रुप एडिटर एवं एंकर बरखा दत्त और हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक, मौज़ूदा संपादकीय सलाहकार एवं स्तंभकार वीर सांघवी ने पत्रकार होने के अपने रुतबे और साख़ को दौलत की अंधी चमक से कलंकित कर दिया. एक सवाल और भी है, जो लोगों को परेशान कर रहा है कि दलाली में इतने बड़े दो नाम एक साथ भला कैसे हो सकते हैं. वैसे मीडिया के लोगों को कमोबेश इस बात की जानकारी है कि वीर सांघवी और बरखा दत्त

(शेष पृष्ठ 2 पर)

नेता, अधिकारी, दलाल और सरकार

त्रिदीब रमण

लोकसभा में झारखंड के गोड्डा के एक युवा सांसद निशिकांत दुबे ने आम बजट परिचर्चा में भाग लेते हुए सरकार की ओर ज्वलंत सवालों के कई गोले दनादन एक साथ दाग़ दिए तो एकबारगी पूरा सत्तापक्ष भी सन्न रह गया था. भाजपा के इस युवा सांसद ने सरकार से पूछा कि एक टेप आया है, एक पीआर एजेंसी के बारे में. इस टेप में देश के बड़े उद्योगपतियों से लेकर सरकार तक का ज़िक्र है कि केंद्र सरकार में मंत्री कौन हो, यह प्रधानमंत्री नहीं, अपितु बाहर के लॉबिस्ट तय कर रहे हैं. दुबे स्पष्ट करते हैं कि इसी टेप को आधार बनाकर जब डायरेक्टर इंवेस्टीगेशन दिल्ली को गोपनीय काग़ज़ात भेजे जाते हैं तो वे लीक हो जाते हैं और आनन-फानन में सरकार डायरेक्टर इंवेस्टीगेशन को बदल देती है तथा यह तय करती है कि अब इस

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लिए भी नए प्रमुखों के नामों को आख़िरी रूप देने में लगी है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बदलाव की बयार

देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) आजकल काफ़ी व्यस्त है. हाल के दिनों में जिस तरह एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, सीबीआई के अधिकारी जांच कार्यों में बुरी तरह उलझे हुए हैं. लेकिन इसके साथ–साथ सीबीआई के अंदर एक और चीज की गहमागहमी है. इस संस्था के मौजूदा निदेशक अश्विनी कुमार नवंबर महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं और नए निदेशक की तलाश का काम जोरों पर है. रोचक तथ्य यह भी है कि सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लिए भी नए प्रमुखों के नामों को आखिरी रूप देने में लगी है, क्योंकि इन दोनों संस्थाओं के मौजूदा प्रमुख राजीव माथुर और के सी वर्मा भी सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं. हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अश्विनी कुमार का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इस पद को पाने के लिए जोड़–तोड़ में लगे हैं, उन्हें सेवा विस्तार की संभावना कम ही दिखती है. सीबीआई के निदेशक पद की दौड़ में 1975 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी एवं नेशनल इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी के मुखिया एस सी सिन्हा, 1974 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक आर के भाटिया, बिहार कैडर के रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक रंजीत सिन्हा और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एस के राउत जैसे अधिकारी शामिल हैं. हालांकि यूपीए सरकार के शासनकाल में वरिष्ठ नौकरशाहों को सेवा विस्तार देने की एक परंपरा सी चल पड़ी है, लेकिन इस बाबत सारे फ़ैसले प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ही लिए जाते हैं और पृथ्वीराज चव्हाण की विदाई के बाद अब आगे क्या होगा, यह बताना मुश्किल है.

दबाव में नौकरशाह

आदर्श सोसाइटी घोटाले ने एक मुख्यमंत्री की बलि ले ली, लेकिन सोसाइटी को ग्रीन सिग्नल देने वाले नौकरशाह बेदाग़ बच निकलने में कामयाब रहे. फिर भी इस मुद्दे को लेकर जितना शोरशराबा मचा है, उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि सरकार इसमें शामिल अधिकारियों को इतनी आसानी से छोड़ देगी. मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही पृथ्वीराज चव्हाण ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में इसे स्पष्ट कर दिया. राज्य के नौकरशाहों के लिए उनका एक ही संदेश था, काम करो या दफा हो जाओ. लोग इसे चव्हाण की तात्कालिक प्रतिक्रिया या गीदड़ भभकी का नाम दे सकते हैं, लेकिन उनके काम करने का जो रवैया है, उससे तो यही लगता है कि महाराष्ट्र में दागदार अधिकारियों के खराब दिन शुरू होने वाले हैं. दिल्ली में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने भी अपने एक बयान में कहा कि आदर्श सोसाइटी घोटाले में शामिल नौकरशाहों के ख़िलाफ़ राज्य सरकार के साथ–साथ केंद्र सरकार भी कार्रवाई कर सकती है. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त रामानंद तिवारी और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुभाष लाला के नाम भी आदर्श सोसाइटी में फ्लैट हैं. लेकिन इस मामले में जिस तरह जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आदर्श सोसाइटी को ग्रीन सिग्नल देने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है. अब देखना यह है कि चव्हाण अपने संदेश के मुताबिक़ काम करते हैं या नहीं.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

68 आईएएस बनेंगे जेएस

लंबे इंतज़ार के बाद आख़िरकार 1991 बैच के 52 आईएएस अधिकारी भारत सरकार में संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष पद के लिए सूचीबद्ध कर लिए गए हैं. इनमें एल पी रेड्डी, अरविंद कुमार, अजय जैन, हरप्रीत सिंह, जी एस प्रसाद, सुमिता डावरा, जी अशोक कुमार, प्रत्यय अमृत एवं रंजीत पुनहानी आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं. इसी प्रकार 1988 बैच और हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार खुल्लर भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग का हिस्सा बन सकते हैं. खुल्लर को यहां संयुक्त सचिव बनाया जा सकता है. वह गोविंद मोहन की जगह लेंगे, जिनकी केंद्रीय प्रभार की सेवा अगले साल जनवरी में समाप्त हो जाएगी. वहीं 1984 बैच के 15 आईएएस अधिकारी भारत सरकार में शामिल होंगे. इन अधिकारियों को भी संयुक्त सचिव या समकक्ष पदों पर नियुक्त किया जाएगा.

निलांजन को पदोन्नति

आईएएस अधिकारी एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं जन वितरण विभाग के संयुक्त सचिव निलांजन सान्याल को जल्द ही अतिरिक्त सचिव के रूप में पदोन्नति दी जा सकती है. उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक़, उन्हें जल्द ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाकर भेजा जा सकता है. मंत्रालय में यह पद हाल में सृजित किया गया है.

हलदर को एक साल और

1970 बैच और बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी पी सी हलदर को सेवा विस्तार दिया गया है. उत्तर–पूर्वी शांति वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल हलदर की सेवा एक साल के लिए बढ़ाई गई है. हलदर इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं.

ये बड़े पत्रकार हैं या बड़े दलाल

पृष्ठ 1 का शेष

के बीच क्या कनेक्शन है, पर आम लोगों को शायद ही पता हो कि वीर और बरखा दोनों बेहद घनिष्ठ मित्र हैं. जब वीर सांघवी को न्यूज़ एक्स से इस्तीफ़ा देना पड़ा था, तब कहा गया था कि इसकी वज़ह भी बरखा ही बनी थीं. शायद इसलिए दलाली में भी दोनों ने साथ ही हाथ काले किए.

जनवरी 2006 में जब ए राजा पर्यावरण मंत्री थे, तब होटल ताज मानसिंह में बरखा दत्त, वीर सांघवी और नीरा राडिया की एक लंबी मुलाकात हुई थी. नीरा की राजा से यह पहली मुलाकात थी. यह कमरा नीरा राडिया के नाम से बुक था. इसके बाद उनके मिलने का सिलसिला चल निकला. सीबीआई सूत्र बताते हैं कि बात भले ही चार कंपनियों की जा रही है, पर कंपनियों की कुल संख्या नौ है. कुल तीन सौ दिनों तक नीरा की बातें टेप की गई हैं. जो बातें निकल कर सामने आई हैं, उनकी बिना पर कल यह ख़ुलासा भी हो सकता है कि इन नौ कंपनियों में बरखा और वीर की भी हिस्सेदारी हो.

पिछले दिनों एक कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस गजेंद्र नारायण रे ने टिप्पणी की थी कि आज की पत्रकारिता वेश्यावृत्ति में बदल गई है. बरखा दत्त और वीर सांघवी ने अपने कुकृत्य से उनकी बात पर मुहर भी लगा दी है. पत्रकारिता के पेशे की आड़ में काली कमाई कर रहे इन दोनों नामचीन पत्रकारों के नाम आयकर विभाग और सीबीआई की सूची में बतौर दलाल दर्ज हो चुके हैं. आयकर विभाग और सीबीआई के पास इन दोनों के ख़िलाफ़ सबूतों की लंबी फेहरिस्त है. सीबीआई और आयकर महानिदेशालय के पास मौज़ूद टेपों में इन दोनों दिग्गज पत्रकारों को दलाली की भाषा बोलते हुए साफ़ सुना जा सकता है. सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा ने जब टेलीकॉम घोटाले केसिलसिले में नीरा राडिया के ख़िलाफ़ 21 अक्टूबर 2009 को मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की, तब पाया कि नीरा राडिया अपनी चार कंपनियों के ज़रिए टेलीकॉम, एविएशन, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कॉरपोरेट सेक्टरों के फ़ायदे के लिए बिचौलिए का काम करती हैं. नीरा अपने काम को पूरा कराने के लिए देश के नामचीन पत्रकारों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जिसकी भरपूर क़ीमत भी नीरा इन पत्रकारों को देती हैं. सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो के डीआईजी विनीत अग्रवाल को जब इस बात के प्रमाण मिले तो उन्होंने आयकर महानिदेशालय के इंवेस्टीगेशन आईआरएस मिलाप जैन से नीरा राडिया से जुड़ी जानकारी मांगी. आयकर महानिदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर आशीष एबराल द्वारा सीबीआई को भेजे गए सरकारी पत्र में जवाब आया कि नीरा राडिया पहले से ही संदिग्ध हैं और इस बिना पर गृह सचिव से अनुमति लेकर नीरा और उनके सहयोगियों के फोन टेप किए जा रहे थे. इस दरम्यान ही यह कड़वी हक़ीक़त सामने आई कि वैष्णवी कॉरपोरेट कंसल्टेंट, नोएसिस कंसल्टिंग, विटकॉम और न्यूकॉम कंसल्टिंग कंपनियों के माध्यम से टाटा, अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने की ख़ातिर नीरा राडिया बरखा दत्त और वीर सांघवी जैसे रसूखदार पत्रकारों का इस्तेमाल करती हैं. बरखा और वीर सांघवी नीरा राडिया जैसी बिचौलिया के ज़रख़रीद बन सियासी गलियारों में तोल–मोल का खेल रचते हैं. पत्रकारिता के बूते बने अपने संपर्कों का उपयोग वे मंत्रिमंडलीय जोड़–तोड़ में करते हैं. अपने मतलब के कॉरपोरेट घरानों की सहूलियत के मुताबिक़ मंत्रियों को विभाग दिलवाते हैं और बदले में भारी–भरकम दलाली खाते हैं. सबूत कहते हैं कि दलालीगिरी का खेल ये दोनों बहुत पहले से करते आ रहे हैं, पर इनका भांडा फूटा ए राजा को संचार मंत्री बनवाने के बाद. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी नहीं चाहते थे कि आरोपों से घिरे ए राजा को संचार मंत्री बनाया जाए. मनमोहन सिंह ने ए राजा के नाम पर ग़ौर करने तक से मना कर दिया था. मनमोहन सिंह चाहते थे कि देश को अत्याधुनिक सूचना क्रांति से जोड़ कर समाज को समृद्ध बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाने वाला संचार मंत्रालय ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए, जो कॉरपोरेट घरानों की कठपुतली न हो, उसकी छवि बेदाग़ हो. पर नीरा राडिया के हाथों बिक चुके बरखा दत्त और वीर सांघवी ने कांग्रेस के पावर कॉरिडोर में ऐसी ज़बरदस्त घेराबंदी की कि प्रधानमंत्री तो बेबस हो ही गए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी एक न चली. सीबीआई और आयकर विभाग की फाइलों और टेलीफोन टेपों में बरखा और वीर सांघवी के ख़िलाफ़ दर्ज़ साक्ष्य उनकी दलाली की हौलनाक कहानी कहते हैं कि देश के नामचीन पत्रकार होने का इन दोनों ने किस क़दर ओछा लाभ उठाया. नीरा राडिया के हाथों की कठपुतली बनकर दोनों ने ही टाटा और अंबानी जैसे देश के टॉप कॉरपोरेट घरानों को व्यवसायिक फ़ायदा पहुंचाने की गरज़ से लगातार पैरवी कर सरकार के कई नीतिगत फ़ैसलों को बदलवाया. एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल के ज़बरदस्त विरोध के बावज़ूद दयानिधि मारन के बजाय ए राजा संचार मंत्री बने तो इसी कारण कि बरखा दत्त और वीर सांघवी जैसे सफ़ेदपोश बड़े पत्रकार राजा की पैरवी कर रहे थे. जांच से यह बात भी सामने आई है कि नीरा राडिया, बरखा दत्त और वीर सांघवी की तिकड़ी पुरानी है. नीरा राडिया की चारों कंपनियों में बतौर अधिकारी तमाम रिटायर्ड नौकरशाहों की भरमार है. इन सभी को वीर सांघवी और बरखा द्वारा तैयार की गई सूची के आधार पर ही रखा गया हैं. ये वे अधिकारी हैं, जिन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में ऊंचे पदों पर काम किया है और जिन्हें मंत्रालयों के अंदरूनी कामकाज की बख़ूबी जानकारी है. इन्हें पता है कि मुनाफ़े के फेर में किस तरह सरकार को करोड़ों–अरबों का चूना लगाया जा सकता है. किस तरह विदेशी पूंजी निवेश क़ानून की धज्जियां उड़ाकर अरबों के वारे–न्यारे किए जाते हैं.

वि.सं.
feedback@chauthiduniya.com

नेता, अधिकारी, दलाल और सरकार

पृष्ठ 1 का शेष

मामले को एसेसमेंट अफसर नहीं, अपितु सेटलमेंट कमीशन तय करेगा. और, सबको मालूम है कि सेटलमेंट कमीशन में सरकार के कृपापात्र सेवानिवृत्त अफसरों की बहाली होती है. दरअसल यह पूरा मसला देश में पीआर और लॉबिंग की सिरमौर नीरा राडिया से जुड़ा है. यह वही राडिया हैं, जब एनडीए शासनकाल में अनंत कुमार शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे तो मैडम राडिया उनकी सबसे करीबियों में शुमार होती थीं. बाद में नीरा राडिया एक एयरलाइंस शुरू करना चाहती थीं, पर चूंकि फंड की पारदर्शिता नहीं थी, समझा जाता है कि शायद इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें अपनी एयरलाइंस शुरू करने की इजाज़त नहीं दी.

बाद के दिनों में राडिया मुकेश अंबानी और रतन टाटा सरीखे देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ जुड़ गईं. जब मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो रतन टाटा झारखंड सरकार के साथ अपने खनन लीज अनुबंध को आगे बढ़ाना चाहते थे और इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने राडिया का चुनाव किया. और, समझा जाता है कि टाटा ने राडिया के मार्फ़त मधु कोड़ा को तब 180 करोड़ रुपये का भुगतान किया और इस पूरे कार्य में राडिया की फीस क्या थी, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है. पर हां, टाटा ने इस कार्य में जुटी राडिया की पीआर कंपनी से जुड़े सहकर्मियों को एक करोड़ रुपये का पारितोषिक ज़रूर दिया था. आईबी ने ऐसा इस टेप को आधार बनाकर खुलासा किया, पर इस मामले में कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम सामने आने पर केंद्र सरकार मधु कोड़ा को बचाने में जुट गई. सूत्रों के अनुसार, भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने गृह मंत्रालय की इजाज़त पर नीरा राडिया और उनके सहकर्मियों की टेलीफोन लाइनों पर लगातार नज़र रखी. ज़ाहिरा तौर पर नीरा राडिया देश के कई बड़े उद्योगपतियों का राजनैतिक प्रबंधन देखती हैं. राडिया अपने कॉरपोरेट क्लाइंट्स के व्यवसायिक हितों के लिए सरकारी महकमों में उच्च स्तर पर नीतियों में मनमाफिक फेरबदल कराने के साथ–साथ मंत्रियों की नियुक्तियों में भी हस्तक्षेप करती हैं. नीरा अपना साम्राज्य सुनियोजित तरीके से अपनी चार कंसल्टिंग कंपनियों द्वारा चलाती हैं.

वैष्णवी कॉरपोरेट मुख्यत: टाटा समूह, यूनिटेक एवं स्टार टीवी केसाथ–साथ अन्य उद्योगपतियों के मीडिया और सरकारी महकमों से जुड़े कामकाज देखती है. नीरा ने नियोकॉम कंसल्टिंग की शुरुआत नवंबर 2008 में मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह का राजनैतिक प्रबंधन देखने के लिए की, जबकि नियोसिस की शुरुआत का उद्देश्य आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त नौकरशाहों द्वारा टेलीकॉम, ऊर्जा, उड्डयन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य देखना बताया जाता है. नियोसिस पर भी पूरा नियंत्रण मैडम राडिया का ही है. तथ्यों के अनुसार, टाटा समूह का सिंगूर प्रोजेक्ट जब फेल हो गया था तो नीरा और उनके सहकर्मियों ने नैनो प्रोजेक्ट को अपने तंत्र की मदद से गुजरात में स्थानांतरित कराया था. इसके लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण माकपा नेताओं को मैनेज किया था. कहा जाता है कि नीरा के लेफ्ट और सीटू के कई नेताओं से बेहद घनिष्ठ संबंध हैं. एक प्रमुख उद्योगपति घराने को एक न्यूज़ चैनल पर पूर्ण नियंत्रण पाना था. इसके लिए नीरा राडिया और जहांगीर पोचा ने एक दैनिक हिंदी अखबार नई दुनिया के मालिक अभय छजलानी से बातचीत की और इस काम को पूरा किया गया. मीडिया प्रबंधन में नीरा और उनके सहकर्मियों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है. वे पत्रकारों को खुश करने के लिए उन्हें सपरिवार विदेश घुमाते हैं, महंगे उपहार देते हैं. इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि एक अंग्रेज़ी दैनिक के पूर्व संपादक और एक अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल की वरिष्ठ पत्रकार को महंगी कारें भेंट की गईं. बातचीत से उजागर हुए तथ्यों के अनुसार, मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के व्यवसायिक विवादों खासकर केजी बेसिन झगड़े में श्रीमती राडिया मुकेश की ओर से ज़ोरदार लॉबिंग कर रही थीं.

खुफिया सूत्रों के अनुसार, मुकेश अंबानी के सहयोगी मनोज मोदी और परिमल नैथाणी द्वारा नीरा के सहकर्मियों के साथ हुई बातचीत में यह उजागर हुआ कि कुछ एनजीओ द्वारा दायर की गई पीआईएल को वापस लेने के लिए स्टिंग ऑपरेशन भी करा कर दबाव डाला गया. मुकेश अंबानी हल्दिया पैट्रो केमिकल्स को अपने प्रभुत्व में लेना चाहते थे. हल्दिया पेट्रोकैम के चेयरमैन एवं सरकार द्वारा मनोनीत तत्कालीन फिक्की चीफ तरुण दास से नीरा राडिया ने संपर्क किया. सूत्र बताते हैं कि इसके लिए तरुण दास ने माकपा नेता निरूपम सेन को राजी किया तथा निरूपम ने प्रकाश करात से राडिया की मुलाकात भी कराई. प्रकाश करात और निरूपम सेन यह पूरा प्रोजेक्ट मुकेश अंबानी को दिलाने के लिए तत्पर थे, पर उन्हें भय था कि माकपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता इसमें उलझनें पैदा कर सकते हैं. सो इस नेता को मैनेज करने की जिम्मेदारी मुकेश अंबानी पर छोड़ी गई. सेवानिवृत्त नौकरशाह प्रदीप बैजल, जो नीरा के लिए काम करते हैं, ने पाइप लाइन रेगुलेटरी एजेंसी और रिलायंस के बीच मध्यस्थता की. तथ्यों के अनुसार, वित्त मंत्रालय के साथ लॉबिंग हुई कि रिलायंस गैस को खनिज तेल के अनुसंधान के रूप में सात वर्ष तक करमुक्त किया जाए. इसके अलावा रिलायंस ने वी के सिब्बल जो हाइड्रोकार्बंस के महानिदेशक हैं, को आलीशान घर खरीद कर दिया. आर कॉम केचार अफसरों के खिलाफ़ सीवीसी द्वारा जांच चल रही है. जांच 53,000 करोड़ रुपये के घपले से जुड़ी है. एक अन्य प्रकरण में नीरा राडिया द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के उच्चाधिकारियों को रिलायंस को बैंक गारंटी देने के लिए मैनेज किया गया. यह गारंटी रिजर्व बैंक द्वारा उक्त सूचना के खिलाफ़ दी गई, जिसमें कंपनी की वित्तीय गड़बड़ियों का ज़िक्र था. भारती एयरटेल कंपनी के मालिक सुनील मित्तल ने भी नीरा की सेवाएं अपनी कंपनी के लिए अनौपचारिक तौर पर लीं. मित्तल ने नीरा की सेवाएं टेलीकॉम में तीन कारणों से लीं. पहला टेलीकॉम मंत्रालय के स्पेक्ट्रम मामले में सीडीएमए लॉबी के प्रति रुझान देखते हुए जीएसएम लॉबी के लिए लॉबिंग कराना. दूसरा, मित्तल ने नीरा द्वारा दयानिधि मारन को मंत्री बनवाने के लिए लॉबिंग कराई. सूत्रों के अनुसार, सुनील मित्तल को नीरा से सुहेल सेठ ने मिलवाया था. नीरा राडिया ने मित्तल को अपनी सेवाएं देते समय इस बात का ध्यान रखा कि उनके इस कार्य से कहीं भी टाटा के व्यवसायिक हितों का अहित न हो. नीरा एवं रतन टाटा के बीच टेप हुई बातचीत में एक तथ्य और उजागर हुआ कि टाटा दयानिधि मारन को टेलीकॉम मंत्री किसी भी हालत में बनने देने के पक्ष में नहीं थे. सूत्रों के अनुसार, नीरा के संबंध ए राजा से काफी नज़दीकी हैं. और, अपने इन्हीं संबंधों के कारण नीरा ने टेलीकॉम मंत्री द्वारा अपने क्लाइंट्स स्वान टेलीकॉम, एयरसेल, यूनिटेक वायरलेस और डाटाकॉम को लाइसेंस दिलवाए. ग़ौरतलब है कि डाटाकॉम में रिलायंस समूह के कर्मचारी मनोज मोदी का पैसा लगा है. राजनैतिक प्रबंधन के साथ–साथ श्रीमती राडिया विदेशों से भी धन उगाहने के काम में लिप्त हैं. उन्होंने अपने क्लाइंट यूनिटेक के मुंबई प्रोजेक्ट में लेहमैन ब्रदर्स से तीन क़िस्तों में पैसा निवेश कराया था. पहली क़िस्त लगभग 740 करोड़ रुपये की, शिवालिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जो यूनिटेक की होल्डिंग है और रोहन डेवलपर्स मुंबई को दी गई. शिवालिक में यूनीटेक के पचास फीसदी शेयर हैं. बकाया राशि दो क़िस्तों में लगभग 550 मिलियन डॉलर के रूप में दी गई. आईबी की इस रिपोर्ट में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे हैं, पर नीरा के ऊंचे सियासी रसूख को देखते हुए लगता है कि ऐसे मामलों से उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हो पाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 38
दिल्ली, 29 नवंबर–05 दिसंबर 2010
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही हों या फिर रमापति राम त्रिपाठी, सभी केंद्रीय नेतृत्व के थोपे हुए चेहरे हैं. इन्हें कार्यकर्ता अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं.

उत्तर प्रदेश में भाजपा

अब भी न चेते तो कुछ न बचेगा

विजय यादव

बात 1991 की है, उत्तर प्रदेश में भगवा लहर चल रही थी और सूबे के चुनावी इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई. सभी नेता खुश थे, कार्यकर्ता प्रफुल्लित थे, कहीं कोई गुटबाजी नहीं. मतभेद थे, लेकिन मनभेद नहीं. समय चक्र के साथ भाजपाइयों पर सत्ता का नशा चढ़ा, सोनिया–राहुल को कोसते–कोसते कांग्रेसी संस्कृति हावी हुई. आज भाजपा उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है. कारण और भी हैं, लेकिन केंद्रीय एवं राज्य नेतृत्व की हालत पर काबू पाने की दिलचस्पी कहीं नहीं दिखती है. समाचारपत्रों में बयानबाजी जारी रहे, इसके लिए भाजपा की प्रदेश इकाई में प्रवक्ताओं की फौज बना दी गई है. सबके लिए एक–एक दिन निर्धारित कर दिया गया है. पार्टी पदाधिकारी अखबारों में अपनी खबरें देखकर खुश हो लेते हैं. नतीजतन, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में भाजपा की जमीन लगातार खिसकती जा रही है.

इसका सबसे ताजा उदाहरण पंचायत चुनाव हैं. इन चुनावों में पार्टी की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, जिसे वह प्रचारित कर सके. पार्टी के विधायक तक अपने निकट के रिश्तेदारों को जिता नहीं सके. महराजगंज के विधायक महंत दुबे की अनुज वधू प्रीति रानी और पत्नी पूनम दोनों ही बीडीसी का चुनाव हार गईं. वहीं फर्रुखाबाद में भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉ. भूदेव सिंह प्रधानी का चुनाव हार गए. वह 15 वर्षों से प्रधानी कर रहे थे, लेकिन इस बार पराजय का सामना करना पड़ गया. पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी को गांव–गांव जाकर संगठन मजबूत करने की याद जरूर आई है. अब इसका कितना फायदा 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी. पंचायत चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर संगठन के अपने तर्क हैं. उसका कहना है कि भाजपा की शहरी मतदाताओं में गहरी पैठ है. पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हुए, सभी दलों ने इससे ख़ुद को अलग रखा. ऐसे में कोई दावा करने की स्थिति में नहीं है. बात सही भी है, लेकिन शहर में भी भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है. उल्टे जो कमाई थी, उसे भी गवां ही रही है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ का उदाहरण सबके सामने है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा से पहले तक लखनऊ संसदीय क्षेत्र के शहरी इलाके की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का क़ब्ज़ा होता था. अटल जी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, उनके प्रतिनिधि के तौर पर लाल जी टंडन जनता की अदालत में आए. लखनऊ के लोगों ने टंडन को जिताकर संसद तो पहुंचा दिया, लेकिन भाजपा की परंपरागत लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट कांग्रेस को सौंप दी. इस क्षेत्र से लाल जी टंडन लगातार कई बार चुनाव जीतते रहे, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी अमित पुरी को विधानसभा नहीं भेज सके. पार्टी इसकी वजह चाहे जो भी बताए, लेकिन कार्यकर्ता साफ़ तौर पर कहते हैं कि इस सीट से टंडन अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे. पार्टी ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की. नतीजतन टंडन समर्थकों ने चुनाव में अमित पुरी के साथ भितरघात करके उन्हें हरा दिया.

भितरघात की प्रवृत्ति ने ही लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में कहीं का न रखा. जिस उत्तर प्रदेश के सहारे लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उसे उन्हीं के सिपहसलारों ने पूरा नहीं होने दिया. लोकसभा चुनाव के बाद भितरघात करने के आरोप में 26 नेताओं को नोटिस भी जारी की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं. नोटिस को किसी ने नोटिस में नहीं लिया. मजेदार बात यह है कि भाजपा के तत्कालीन प्रदेश महामंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भितरघातियों को नोटिस जारी किया और इसके कुछ दिनों बाद ही जालौन लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे भानु प्रताप वर्मा ने संगठन की एक बैठक में उन्हीं पर भितरघात का आरोप लगा दिया. बरेली से लगातार छह बार संसद पहुंचने वाले संतोष गंगवार ने भी अपनी हार के लिए पार्टी के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल को जिम्मेदार ठहराया था. वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए हुए चुनाव से भी भाजपा के इन गुटबाज नेताओं ने कोई सबक नहीं लिया था. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा महज 51 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि इसके पहले सदन में उसके 93 विधायक हुआ करते थे. पार्टी कार्यकर्ता इस स्थिति के लिए नेतृत्व को ही जिम्मेदार मानते हैं. कार्यकर्ताओं की मानें तो नेतृत्व के पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, जिससे वह मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सके. भाजपा की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस खुद को मजबूत करने में लगी है. भगवा झंडे का परंपरागत मतदाता पंजे को मजबूत करने में अब ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है. कार्यकर्ताओं की बात गलत नहीं है. लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने जिस तरह उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, उसने भाजपा को चौथे स्थान पर पहुंचा दिया. जाहिर है कि भाजपा का जनाधार कांग्रेस की ओर खिसका है. इन हालात में सबसे चिंताजनक यह है कि केंद्रीय नेतृत्व संगठन को मजबूत और गतिशील करने के प्रति गंभीर नहीं दिखता. दिखावे के लिए संगठन के चुनाव होते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्षों तक का मनोनयन किया जाता है. नतीजतन भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र और सामूहिक नेतृत्व लफ्फाजी की बातें बनकर रह गया है.

भितरघात की प्रवृत्ति ने ही लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में कहीं का न रखा. जिस उत्तर प्रदेश के सहारे लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उसे उन्हीं के सिपहसलारों ने पूरा नहीं होने दिया.

भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही हों या फिर रमापति राम त्रिपाठी, सभी केंद्रीय नेतृत्व के थोपे हुए चेहरे हैं. इन्हें कार्यकर्ता अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं. तभी जंबो जेट प्रदेश कमेटी बनाने के बाद भी प्रदेश भाजपा संगठन में असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है. आम दिनों में पार्टी कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहता है. कोई केंद्रीय नेता लखनऊ आया तो उसके स्वागत की रस्म अदायगी के लिए क्षेत्रीय क्षत्रप प्रदेश मुख्यालय आते हैं और फिर ग़ायब हो जाते हैं. ऐसे में कार्यकर्ता इन नेताओं को कहां तलाश करें. कार्यकर्ता आज भी उस घड़ी को कोसते हैं, जब वर्ष 1999 में कल्याण सिंह को पैदल करने के लिए भाजपा में गुटबाजी का दीमक लगा और वह पूरे संगठन को ही चट कर गया. कल्याण सिंह के पार्टी छोड़ने से भाजपा में अगड़ों और पिछड़ों का सामंजस्य गड़बड़ाया, जिसे भाजपा नेतृत्व ने महसूस किया. कल्याण सिंह को दोबारा भाजपा में लाया गया. वर्ष 2007 का विधानसभा चुनाव कल्याण सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा गया, लेकिन भाजपा का कल्याण नहीं हो सका. कार्यकर्ता कहते हैं कि कल्याण सिंह को भाजपा में दोबारा लाया गया, लेकिन राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र और लाल जी टंडन उन्हें सहन नहीं कर पा रहे थे. जनता में भी कल्याण सिंह का जादू नहीं चल सका. फिर वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव से ऐन पहले वह भाजपा छोड़कर मुलायम सिंह यादव से हाथ मिला बैठे. उत्तर प्रदेश के वर्तमान सियासी एवं जातीय समीकरणों पर यदि गौर करें तो भाजपा के सवर्ण मतदाताओं का एक बड़ा तबका बसपा के साथ है. बहुजन के स्थान पर सर्वजन का नारा देकर मायावती ने दलित और ब्राह्मण मतदाताओं का जो समीकरण बैठाया है, उसकी काट बसपा के विरोधी राजनीतिक दल अभी तक नहीं तलाश पाए हैं. कांग्रेस ज़रूर इस मामले में कुछ सफ़ल होती दिख रही है, लेकिन भाजपा इसे मानने को तैयार नहीं है. पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधान परिषद सदस्य हृदय नारायण दीक्षित कहते हैं कि मायावती के शासनकाल में मची लूट, भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था एवं बेरोजगारी से त्रस्त जनता भाजपा को ही विकल्प के रूप में देख रही है. वह पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से भी साफ़ इंकार करते हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही भी पार्टी संगठन के एकजुट होने का दावा करते हैं. इन नेताओं के दावों में कितनी सच्चाई है, यह पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और अब पंचायत चुनाव के नतीजों से साफ़ हो चला है.

feedback@chauthiduniya.com

मुंह में राम, बगल में कल्याण

उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने भगवान राम के साथ अब पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम का इस्तेमाल करने की राजनीतिक मजबूरी आ गई है. भाजपा अब मायावती और मुलायम के साथ अपने मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की तुलना करने जा रही है. यह तुलनात्मक पत्रक हर विधानसभा क्षेत्र में बांटे जाएंगे. कल्याण सिंह भाजपा से तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं. ऐसे में मजबूरी में ही सही, पार्टी के लिए उनकी छाया से ख़ुद को मुक्त कर पाना मुमकिन नहीं होगा. इन सबके बीच एक सवाल यह भी है कि कहीं यह कल्याण सिंह को भाजपा में लाने की एक सोची–समझी रणनीति तो नहीं है. ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमजोर स्थिति और नेताओं के आपस में ही सिर फुटौव्वल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी वाकिफ नहीं हैं. विस्फोटक होते हालात से वह भी परिचित हैं और इन विकट स्थितियों में भी वह मिशन 2012 को सफलता के साथ पूरा करने का संदेश कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, लेकिन पार्टी की केंद्रीय राजनीति में हावी मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, विनय कटियार, कलराज मिश्र, मुख्तार अब्बास नकवी एवं अन्य नेताओं के सामने उनकी सारी रणनीति फेल हो रही है.

उत्तर प्रदेश के उक्त केंद्रीय नेता अपने–अपने क्षेत्रों के जनाधार वाले नेताओं को किनारे लगाने में ही अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं. यही वजह रही कि जो नेता रमापति राम त्रिपाठी के नेतृत्व वाली कमेटी में उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसे पदों पर थे, उन्हें सूर्य प्रताप शाही ने क्षेत्रीय कमेटियों का अध्यक्ष बनाकर हैसियत में रहने का संकेत दे दिया. अयोध्या से विधायक लल्लू सिंह को ही लें, रमापति राम ने उन्हें अपनी कमेटी में उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन इस बार वह अवध क्षेत्र के अध्यक्ष बना दिए गए. गुस्साए लल्लू सिंह ने पद ग्रहण नहीं किया तो दो माह बाद उनकी जगह सुभाष त्रिपाठी को अवध क्षेत्र का नया अध्यक्ष बना दिया गया. इस तरह जय प्रकाश को काशी क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उन्होंने भी कार्यभार संभालने से इंकार कर दिया. भाजपा में कितना अंतर्विरोध है, यह पार्टी के वरिष्ठ नेता केशरीनाथ त्रिपाठी की एक बात से साफ़ हो जाता है. उनसे जब संगठन और मिशन 2012 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में लखनऊ में बैठे लोगों से बात कीजिए, मैं तो इलाहाबाद में बैठा हूं.

नई कमेटी में क्षेत्रीय असंतुलन और पार्टी के प्रति वफादारी की अनदेखी होना भी मुद्दा बना, लेकिन इसे दबा दिया गया. डैमेज कंट्रोल के लिए विजय बहादुर पाठक और राजीव तिवारी को सह प्रवक्ता से प्रोन्नत करके प्रवक्ता बना दिया गया तो प्रवक्ताओं की टीम में एक नया नाम हरिद्वार दुबे शामिल किया गया. अब प्रदेश भाजपा में प्रवक्ताओं की भरमार हो गई है. नई कमेटी में पूर्वांचल को काफी अहमियत दी गई है, दस उपाध्यक्षों में पांच पूर्वांचल के हैं. ऐसे में बाकी क्षेत्र खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. भाजपाइयों की इस आपसी मारकाट के बीच ही अयोध्या मुद्दे पर हाईकोर्ट का फैसला आना पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकता है, लेकिन ऐसे समय में कल्याण सिंह सरीखे नेता की कमी महसूस की जा रही है. इस माहौल में पार्टी संगठन के स्तर पर कुछ संजीदा हुई है. भाजपा अब गांव–गांव जाकर जनता की नब्ज टटोलने का काम करेगी. केंद्रीय और प्रदेश स्तर के नेता गांवों में रात्रि विश्राम करेंगे. इससे जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित होगा. कहने की जरूरत नहीं रह जाती है कि अयोध्या पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जब मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का तुलनात्मक पत्रक बंटेगा तो उसमें कल्याण सिंह की उपलब्धियों का जिक्र भी होगा. ऐसे में भाजपा के लिए अपरोक्ष रूप से ही सही, कल्याण सिंह का इस्तेमाल करने की मजबूरी रहेगी. अब यह सभी जानते हैं कि कल्याण सिंह भाजपा से तीन बार मुख्यमंत्री रहे. राम प्रकाश गुप्ता एवं राजनाथ सिंह भी भाजपा से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सरकार की हनक और धमक की चर्चा तो केवल कल्याण सिंह के जमाने की ही होती है.

नौकरशाही के सहयोग के अभाव के चलते देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की प्रक्रिया पटरी से उतर गई. असम में पहले से ही कई जनजातीय और ग़ैर जनजातीय सामाजिक संस्थाओं का वजूद रहा है.

सुदर्शन का साइड इफेक्ट

राजीव रंजन तिवारी

विदेशी मूल से लेकर पति–सास की हत्या में संलिप्तता के आरोपों से घिरा सोनिया गांधी का कथित लांछनीय सियासी सफर हर दृष्टिकोण से सफल रहा है. यद्यपि उनके विरोधियों ने उक्त आरोपों के सहारे उनके सियासी क़दम को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका साइड इफेक्ट सोनिया गांधी के अनुकूल रहा. कह सकते हैं कि जब–जब उन पर निशाने साधे गए, तब–तब उनकी राजनीतिक ताक़त बढ़ी. सोनिया एंटोनिया मायनो यानी सोनिया गांधी का इस देश से रिश्ता एक रोमांस से शुरू हुआ था. आज यह रिश्ता पूरी तरह राजनीतिक थ्रिलर में तब्दील हो चुका है. 2004 के आम चुनावों में कांग्रेस का अस्तित्व दांव पर लगा था. देश ने कांग्रेस को चुना और कांग्रेस ने सोनिया को और सोनिया ने उस शख्स को चुना, जो सियासतदां कम था, वफादार ज़्यादा. तमाम झंझावातों के बीच यह सोनिया गांधी की बढ़ती ताक़त का ही परिचायक था. सोनिया गांधी पर लिखी गई स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो की एक किताब, द रेड साड़ी में कहा गया है कि 24 मई 1991 को राजीव गांधी का पार्थिव शरीर तीन मूर्ति हाउस के बड़े हॉल में रखा था. सोनिया ने राजीव के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान सोनिया ने लोगों को जैक्वेलीन केनेडी की याद दिला दी. राजीव की मौत से टूट चुकी सोनिया वापस इटली जाने की सोचने लगीं. हालांकि किताब के लेखक मोरो का यह भी कहना है कि उनकी किताब सोनिया की ज़िंदगी पर आधारित ज़रूर है, लेकिन कहानी पक्की काल्पनिक है. मोरो का दावा है कि अब तक उनकी किताब की क़रीब ढाई लाख प्रतियां बिक चुकी हैं. ज़ाहिर है, सोनिया की ज़िंदगी अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर का दर्जा पा चुकी है. पुस्तक के अनुसार, बचपन में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली सोनिया ने पढ़ाई उतनी ही की, जितनी ज़रूरत थी. यानी वह अच्छी स्टूडेंट नहीं थीं, लेकिन हंसमुख और दूसरों की मदद करने वाली थीं. ख़ैर, सोनिया के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक लेखन के लिए मोरो को कांग्रेस ने नोटिस थमा दिया है. इसके अलावा हाल में प्रकाश झा की फिल्म राजनीति पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए फिल्म के कुछ दृश्य हटवाए थे. इससे पहले भारतीय मूल के ब्रिटिश फिल्म निर्माता जगमोहन मूंदड़ा को भी सोनिया गांधी की ज़िंदगी पर फिल्म बनाने का इरादा छोड़ना पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस सेंसर बोर्ड ने इसकी इजाज़त नहीं दी. भले ही इसे सृजनात्मक आज़ादी के हनन का नाम दिया जाए, लेकिन कांग्रेस सोनिया गांधी के नाम पर कोई जोखिम लेना नहीं चाहती. आख़िरकार सोनिया ने ही कांग्रेस को नया जीवनदान दिया है. कांग्रेस नहीं चाहती कि सोनिया को लेकर कोई विवाद खड़ा हो.

पति राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस केवरिष्ठ नेताओं ने सोनिया से पूछे बिना उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, जिसे उन्होंने यह कहते हुए अस्वीकार किया कि मैं अपने बच्चों को भीख मांगते देख लूंगी, परंतु राजनीति में क़दम नहीं रखूंगी. सीताराम केसरी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते पार्टी का समर्थन कम होता जा रहा था, जिससे कांग्रेस के नेताओं ने फिर से नेहरू–गांधी परिवार के किसी सदस्य की आवश्यकता महसूस की. उनके दबाव में सोनिया गांधी ने 1998 में कोलकाता के प्लेनरी सेशन में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ली और उसके 62 दिनों के अंदर ही वह अध्यक्ष चुनी गईं. राजनीति में क़दम रखते ही उनके विदेशी मूल और उनकी कमज़ोर हिंदी का मुद्दा उठा. उन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगे, लेकिन कांग्रेसी इन मुद्दों को नकारते हुए चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे. सोनिया गांधी अक्टूबर 1999 में बेल्लारी (कर्नाटक) और अमेठी (उत्तर प्रदेश) से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ीं और भारी बहुमत से विजयी हुईं. 1999 में ही 13वीं लोकसभा में वह विपक्ष की नेता बनीं. 2004 के चुनाव से पूर्व आम राय यह बनी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, पर सोनिया ने देश भर में घूमकर ख़ूब प्रचार किया और सबको चौंका देने वाले नतीजों में यूपीए को अनापेक्षित 200 से ज़्यादा सीटें मिलीं. सोनिया स्वयं रायबरेली (उत्तर प्रदेश) से सांसद चुनी गईं. वामपंथी दलों ने भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस और सहयोगी दलों की सरकार का समर्थन करने का निर्णय किया. 16 मई 2004 को सोनिया गांधी 16 दलीय गठबंधन की नेता चुनी गईं. यानी वामपंथी दलों के सहयोग से बनने वाली इस सरकार की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ही बनतीं. सबको उम्मीद थी कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी और सबने उनका समर्थन किया. इसी बीच फिर से एनडीए के नेताओं ने उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठाया. सुषमा स्वराज एवं उमा भारती ने तो इतना तक कह दिया कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनीं तो वे अपना सिर मुंडवा लेंगी और भूमि पर ही सोएंगी. तब 18 मई को उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया. पार्टी से उनका समर्थन करने का अनुरोध करते हुए सोनिया ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री न बनने की घोषणा की. सोनिया के इस फ़ैसले का कांग्रेसियों ने विरोध किया इस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना उनका लक्ष्य नहीं है. ख़ैर, सभी ने मनमोहन सिंह का समर्थन किया. यह उस नेता की कामयाबी थी, जिसे 1999 में सियासत का नौसिखिया कहा जाता था. राष्ट्रपति चुनाव, लाभ के पद के संकट और न्यूक्लियर क़रार पर तकरार जैसे जोखिमों से गुजर कर सोनिया सत्ता में भागीदारी की कला अच्छी तरह जान गई थीं. एक सर्वशक्तिमान नेता और एक आज्ञाकारी प्रधानमंत्री के गठबंधन ने सत्ता में भागीदारी की नई परंपरा को जन्म दिया. सोनिया पार्टी के लिए ज़िम्मेदार थीं तो मनमोहन सिंह सरकार के लिए.

ख़ैर, राष्ट्रीय सुझाव समिति का अध्यक्ष होने के कारण सोनिया गांधी पर लाभ के पद पर होने के साथ लोकसभा सदस्य होने का आरोप लगा. फलस्वरूप 23 मार्च 2006 को उन्होंने राष्ट्रीय सुझाव समिति के अध्यक्ष पद और लोकसभा की सदस्यता दोनों से इस्तीफ़ा दे दिया. मई 2006 में वह रायबरेली (उत्तर प्रदेश) से फिर सांसद चुनी गईं. 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर यूपीए के लिए देश की जनता से वोट मांगा. एक बार फिर यूपीए ने जीत हासिल की और सोनिया यूपीए की अध्यक्ष चुनी गईं. इससे अलग जब सभी ने यह मान लिया था कि अब कांग्रेस का पुनर्जन्म मुश्किल है, तब सोनिया ने तमाम झंझावातों के बीच कांग्रेस में न सिर्फ़ जान फूंकी, बल्कि आज बुलंदी से पार्टी का संचालन कर रही हैं. सोनिया के हिंदुस्तान की ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शुरुआती क़दम बेहद मुश्किल भरे रहे. देश के संभ्रांत सियासी परिवार के बतौर उन्हें सत्ता के विशेषाधिकार से ज़रूर नवाजा गया, लेकिन निजी तौर पर वह हमेशा किसी न किसी पारिवारिक ट्रैजडी से ही दो–चार होती रहीं. उनके पास कुछ नहीं था, न भाषा और न जनाधार. था तो बस सरनेम गांधी का ताबीज और घर के दरवाजे पर बढ़ती घोर निराशा की लहर. 11 साल बाद अब यह तूफान थम गया है. 2009 के लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही सोनिया ने सीधे दुश्मन के कैंप पर हमला बोला. यह हमला था भाजपा के प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग पर. हमला भी वहां, जहां दुश्मन को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचती है. कंधार मामले पर उन्होंने आडवाणी को घेरा. वैसे उनका फोकस इस देश का आम आदमी रहा. यूपीए सरकार का पांच साल का रिपोर्ट कार्ड और उससे पहले एनडीए का शासन. वह इस दौर में आक्रामक रहीं. सोनिया ने इस बार अपना अतीत याद दिलाने और परिवार की विरासत सामने रखने का फ़ैसला लिया. वर्ष 2004 में भाजपा ने सोनिया की ताक़त को अनदेखा किया था, तब उसके सामने ही सोनिया एक खास अंदाज़ में अपने लिए लिखे भाषण पढ़कर उस भारत तक पहुंच रही थीं, जो उतना चमकदार नहीं था, जितना दावा किया जा रहा था. सोनिया की लगातार एक ही कोशिश थी कि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सहयोगी मिल जाएं. पुराने दुश्मन अब दोस्त बन चुके थे. कुछ जातियों और समुदायों में सोनिया ने भी अपनी पैठ बना ली थी. अचानक सोनिया करुणानिधि, वाइको, लालू और पासवान जैसे नेताओं की भी पसंद बन गई थीं. उस वक़्त सोनिया के पास जो था, वह सिर्फ़ उनकी ईमानदारी थी.

सोनिया के हिंदुस्तान की ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शुरुआती क़दम बेहद मुश्किल भरे रहे. देश के संभ्रांत सियासी परिवार के बतौर उन्हें सत्ता के विशेषाधिकार से ज़रूर नवाजा गया, लेकिन निजी तौर पर वह हमेशा किसी न किसी पारिवारिक ट्रैजडी से ही दो–चार होती रहीं. उनके पास कुछ नहीं था, न भाषा और न जनाधार. था तो बस सरनेम गांधी का ताबीज और घर के दरवाजे पर बढ़ती घोर निराशा की लहर. 11 साल बाद अब यह तूफान थम गया है.

ताजा प्रकरण में पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रमुख के एस सुदर्शन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया. उन्होंने सोनिया को सीआईए (अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी) की एजेंट और अवैध संतान भी कह दिया. सुदर्शन द्वारा लगाए गए उक्त आरोप अप्रत्याशित नहीं थे. सुदर्शन का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री दीपक कुमार कहते हैं कि सोनिया गांधी निर्विवाद नेता हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा कर साबित कर दिया कि वह सत्ता के पीछे नहीं भागती हैं. सोनिया उस नेहरू–गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई और फिर देश के विकास के लिए अनेक बलिदान किए. दीपक ने सुदर्शन से जानना चाहा कि उनका और उनके संगठन का देश की आज़ादी में क्या योगदान है. बहरहाल, सोनिया गांधी पर इस तरह के आरोप उसी समय से लगते रहे हैं, जबसे भारतीय राजनीति में उनकी शक्ति का विस्तार हुआ है. कह सकते हैं कि जब–जब सोनिया गांधी पर लांछन लगाए गए, तब–तब उनकी सियासी हैसियत बढ़ती गई.

feedback@chauthiduniya.com

ख़ुद को मसीहा समझते हैं जन प्रतिनिधि

दिनकर कुमार

असम में विधायकों के निवास पर ग्रामीणों की भीड़ सहज ही देखी जा सकती है. पार्टी के कैडर प्रत्येक आगंतुक की वफ़ादारी की जांच करते हैं, फिर उसके आवेदन को आगे बढ़ाने की सिफ़ारिश करते हैं. यह ग्रामीण असम का चिर परिचित मंजर है. आम जनता का कोई भी काम तभी होता है, जब विधायक उसके लिए अनुशंसा करते हैं. विधायकों को अपने क्षेत्र के निवासियों या क्षेत्र के भूगोल की कोई जानकारी भले न हो, मगर सरकार की मौजूदा नीतियों ने उन्हें अपने–अपने क्षेत्र का मसीहा बना दिया है. इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में लोग जन प्रतिनिधियों से काफी अपेक्षाएं रखते हैं, मगर इसका अर्थ सामंतवादी व्यवस्था हरगिज नहीं हो सकता. दुर्भाग्य की बात है कि असम के जन प्रतिनिधि और उनके कैडर सामंतवादी शैली में ही जनता के दु:ख–दर्द का निपटारा करते नज़र आते हैं. इसी वजह से राज्य में पंचायत प्रणाली हाशिए पर दिखाई देती है.

राज्य में पंचायत प्रणाली रुग्णावस्था में है. इसके साथ राजनेता लगातार खिलवाड़ करते रहे हैं. तरुण गोगोई सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण में बिल्कुल विश्वास नहीं करती और सत्ता का रिमोट कंट्रोल हमेशा मंत्रियों एवं विधायकों के घर में ही रहता है. सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि लोगों को वर्तमान में किसी तरह का विकल्प भी दिखाई नहीं दे रहा है. राज्य में पंचायत व्यवस्था कार्य नहीं कर रही है. स्थानीय प्रशासन के समूचे तंत्र पर दिसपुर के राजनीतिक नेतृत्व ने क़ब्ज़ा कर रखा है. इसके चलते पार्टी के कैडरों को बिचौलिए की भूमिका निभाने का मौक़ा मिल गया है और उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मिलने लगी है. सत्ताधारी कांग्रेस ने हाल में निर्देश जारी किया है कि जब विधायक अपने क्षेत्रों में अनुपस्थित रहेंगे तो स्थानीय प्रशासन की निगरानी की ज़िम्मेदारी पार्टी के कैडरों की होगी. इस अंदाज़ में कांग्रेस असम में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रही है.

संभवत: यह सिर्फ़ असम की समस्या नहीं है. संविधान में किए गए 73वें और 74वें संशोधन से ग्रामीण भारत में उम्मीद की किरण नज़र आई थी, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और नौकरशाही के सहयोग के अभाव के चलते देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की प्रक्रिया पटरी से उतर गई. असम में पहले से ही कई जनजातीय और ग़ैर जनजातीय सामाजिक संस्थाओं का वजूद रहा है. असम में आहोम शासकों के समय गांवों में शासन की जो प्रणाली प्रचलित थी, उसी के आधार पर पंचायत व्यवस्था लागू की गई. स्वतंत्रता के बाद पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला असम एक अग्रणी राज्य था, जिसने असम पंचायत राज अधिनियम 1948 बनाकर पंचायत व्यवस्था लागू की. इस अधिनियम के ज़रिए गांवों को जोड़कर पंचायत बनाने का प्रावधान किया गया, मगर ताजा आंकड़ों से असम में पंचायत व्यवस्था की निराशाजनक तस्वीर उभर कर सामने आती है. पंचायत राज क्रियान्वयन के राष्ट्रीय सूचकांक में असम का स्थान 21वां है, जो केवल अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ऊपर है.

वर्ष 2001–02 में दस वर्षों के अंतराल पर जब असम में पंचायत चुनाव कराए गए, तब ग्रामीणों में काफी उत्साह नज़र आया. पहले असम की पंचायतों को विकास योजनाएं लागू करने के मामले में कुछ अधिकार भी मिले हुए थे. उस दौरान सड़कों एवं इंदिरा आवासों का निर्माण और खाद, रसोई गैस, अनाज एवं रिक्शा– तिपहिया वाहनों का वितरण जैसे कार्य भी हुए. पिछले पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घोषणा की थी कि ग्रामीण विकास से जुड़े 29 महत्वपूर्ण विभागों का संचालन पंचायतों के ज़रिए किया जाएगा. उस समय सत्ताधारी कांग्रेस ने जनता के द्वार–जनता की सरकार का नारा ज़ोर–शोर से उछाला था, लेकिन आज तक किसी भी विभाग की योजनाओं को पंचायत के ज़रिए लागू करना ज़रूरी नहीं समझा गया. प्रखंड स्तर पर ग्रामीण विकास की तमाम योजनाएं लागू करने का अधिकार सिर्फ़ नौकरशाही को है, जो भ्रष्टाचार के लिए पहचानी जाती है. पंचायत का सदस्य किसी को नागरिकता का प्रमाणपत्र तक जारी नहीं कर सकता. यह अधिकार भी नौकरशाही को मिला हुआ है. सरकार ने घोषणा के बावजूद पंचायत सदस्यों को कोई वेतन नहीं दिया.

दिसपुर में बैठे सत्ताधीश विकास मद की राशि स्थानीय निकायों को देना नहीं चाहते. ज़िला परिषदों और विकास योजनाओं से संबंधित शहरी संस्थाओं के बीच किसी तरह का तालमेल दिखाई नहीं देता. ज़िला योजना समिति का गठन अनिवार्य होने के बावजूद सरकार ने ऐसा करना ज़रूरी नहीं समझा. असम की जनता को पंचायत राज का झुनझुना भले ही थमा दिया गया हो, मगर विकास के लिए केंद्र से आने वाले अरबों रुपये राजधानी दिसपुर में ही लूटने–खाने की व्यवस्था कर दी गई है.

feedback@chauthiduniya.com

चिंता की बात केवल ये आंकड़े ही नहीं हैं. लखनऊ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मुताबिक़, बच्चों द्वारा अंजाम दिए जा रहे अपराधों में सेक्स संबंधी अपराधों की संख्या में सबसे तेजी से वृद्धि हो रही है.

अपराध की भेंट चढ़ता देश का बचपन

आदित्य पूजन

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नवीनतम आंकड़े देश के भविष्य की ख़ौफ़नाक तस्वीर पेश करते हैं. उनके मुताबिक़ पूरे देश में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि बाल अपराधों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है. पिछले दस वर्षों यानी 1998–2008 के बीच बच्चों द्वारा किए गए अपराधों में ढाई गुना इज़ाफ़ा हुआ है और कुल अपराधों की तुलना में बाल अपराधों का अनुपात भी दोगुने से ज़्यादा हो चुका है. ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, साल 1998 में बाल अपराधों की कुल संख्या 9352 थी, जो 2008 में बढ़कर 24,535 हो गई. देश भर में दर्ज किए गए कुल आपराधिक मामलों के प्रतिशत के लिहाज़ से देखें तो 1998 में बाल अपराधों का प्रतिशत केवल 0.5 था, जो 2008 में 1.2 प्रतिशत के आंकड़े को छू चुका है. यदि लगातार दो वर्षों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2007 में बच्चों द्वारा किए गए कुल अपराधों की संख्या 22,865 थी, जो 2008 में बढ़कर 24,535 हो गई. यानी एक साल के अंदर बाल अपराधों की संख्या में तक़रीबन 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हो गई. इससे पहले वर्ष 2007 में 2006 के मुक़ाबले बाल अपराधों की संख्या में 8.4 प्रतिशत का इज़ाफ़ा दर्ज किया गया था. ये तो केवल वे आंकड़े हैं, जो पुलिस थानों में दर्ज किए गए हैं. यह बात किसी से छुपी नहीं है कि अपराध के लगभग आधे मामले पुलिस के पास नहीं पहुंच पाते या पहुंचते भी हैं तो उन्हें दर्ज नहीं किया जाता. इस तथ्य को ध्यान में रखकर यदि इन आंकड़ों पर ग़ौर करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि देश का बचपन लगातार अपराध की आगोश में समाता जा रहा है.

चिंता की बात केवल ये आंकड़े ही नहीं हैं. लखनऊ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मुताबिक़, बच्चों द्वारा अंजाम दिए जा रहे अपराधों में सेक्स संबंधी अपराधों की संख्या में सबसे तेजी से वृद्धि हो रही है. कुछ साल पहले तक अधिकांश बाल अपराध चोरी, लूटपाट, छीनाझपटी आदि की श्रेणी में आते थे और वे आम तौर पर भूख एवं ग़रीबी के शिकार कम आय वर्ग वाले परिवारों के बच्चों द्वारा अंजाम दिए जाते थे, लेकिन पिछले तीन सालों के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. इन आंकड़ों के मुताबिक़, बच्चे बड़ी संख्या में बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों की ओर मुड़ रहे हैं और इन अपराधों को अंजाम देने वाले अधिकतर बच्चे समाज के उस वर्ग से संबंधित हैं, जिन्हें समृद्ध कहा जाता है. लखनऊ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास वर्ष 2009 में बाल अपराध के 346 मामले आए, जिनमें अकेले बलात्कार के 35 मामले थे, जबकि हत्या के 20. वर्ष 2010 में अब तक दर्ज कुल 140 आपराधिक मामलों में 36 मामले बलात्कार और हत्या के हैं.

बाल अपराधों की बढ़ती संख्या के लिए मीडिया की भूमिका से भी इंकार नहीं किया जा सकता. फिल्में हों या टेलीविज़न चैनल, इनमें हिंसा और अपराध के दृश्यों की भरमार होती है. यहां तक कि अख़बारों में भी अपराध की ख़बरों को ही ज़्यादा जगह मिलती है.

बच्चे ही किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और आने वाले समय में देश की बागडोर उनके ही हाथों में होती है, लेकिन बाल अपराध के उक्त आंकड़े भारत की नई पीढ़ी में बढ़ती निराशा और हिंसक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं. आख़िर इसकी वजह क्या है? इसका कारण है सामाजिक नैतिकता का अवमूल्यन, परिवार नामक संस्था का कमज़ोर पड़ना, बढ़ती व्यवसायिकता और कमज़ोर क़ानून. एक ओर जहां हमारा देश सामाजिक विकास के मानकों पर लगातार आगे बढ़ रहा है, वहीं समाज की नैतिकता के स्तर में लगातार ह्रास हो रहा है. अब संबंध मायने नहीं रखते, रिश्तों की डोर कमज़ोर पड़ती जा रही है. संयुक्त परिवार की परंपरा अब इतिहास की चीज बनती जा रही है. हम दो–हमारे दो के इस दौर में माता–पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता, उनका सारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में लगा रहता है. पैसे की इस धमाचौकड़ी के चलते उपजा अकेलापन बच्चों को निराशा की ओर ले जाता है. हालांकि समय की इस कमी की भरपाई के लिए माता–पिता बच्चों की हर छोटी–बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचपन का अबोध मन अक्सर अपने रास्ते से भटक जाता है. सही–ग़लत के ज्ञान के अभाव में बच्चे ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, जो उन्हें अपराध की दुनिया में ले जाता है.

बाल अपराधों की बढ़ती संख्या के लिए मीडिया की भूमिका से भी इंकार नहीं किया जा सकता. फिल्में हों या टेलीविजन चैनल, इनमें हिंसा और अपराध के दृश्यों की भरमार होती है. यहां तक कि अख़बारों में भी अपराध की ख़बरों को ही ज़्यादा जगह मिलती है. कई बार अपराधियों को नायक के रूप में महिमामंडित भी किया जाता है. बच्चे इससे प्रभावित होकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं और अपराधी बनकर रह जाते हैं. बाल अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए देश में ज्युवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2000 बनाया गया है, लेकिन इसके प्रावधानों का सही तरीक़े से पालन नहीं किया जाता. इस क़ानून के मुताबिक़, हर पुलिस स्टेशन में बाल अपराध शाखा का होना अनिवार्य है, जिसमें बाल अपराध से निबटने और उसे रोकने में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन ऐसा हक़ीक़त में नहीं होता. अधिकांश पुलिस स्टेशनों में बाल अपराध शाखा होती ही नहीं है और होती भी है तो उसमें नियुक्त अधिकारी दूसरे कामों की अधिकता के चलते अपनी प्राथमिक ज़िम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाते. बाल अपराधियों को बाल सुधार गृहों में रखा जाता है, लेकिन इन सुधार गृहों की हालत ऐसी होती है कि अच्छे बच्चे भी यहां आकर अपराधी बन जाते हैं. एक–एक कमरे में 25–30 बच्चों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है. बच्चों के सुधार के लिए जो कार्यक्रम हैं, वे मौजूदा दौर के अनुकूल नहीं हैं. कंप्यूटर क्रांति के इस जमाने में उन्हें बढ़ईगिरी और हथकरघा जैसे कामों का प्रशिक्षण दिया जाता है. एक सच्चाई यह भी है कि जो बच्चे एक बार बाल सुधार गृह में आ जाते हैं, वे हमेशा के लिए अपराधी बनकर रह जाते हैं, हमारा समाज उन्हें उसी रूप में स्वीकार करता है.

बाल अपराधों की बढ़ती संख्या भविष्य के लिए ख़तरे का संकेत है. बच्चे भविष्य की धरोहर हैं, लेकिन सामाजिक कमज़ोरियों और सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते हमारी यह धरोहर लगातार पतन के रास्ते पर आगे बढ़ रही है. बाल अपराधों की बढ़ती संख्या हमारे समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक है, जिससे तत्काल निजात पाने की ज़रूरत है. इसके लिए आवश्यक है कि ज्युवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2000 में सुधार किए जाएं और इसके प्रावधानों के पूरी तरह पालन की व्यवस्था की जाए. सामाजिक स्तर पर भी इसके लिए अलग से क़दम उठाने की दरकार है. इसके साथ–साथ मीडिया को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाने की ज़रूरत है, अन्यथा हमारे देश का भविष्य इसी तरह अपराध की भेंट चढ़ता रहेगा.

aditya@chauthiduniya.com

बाल अपराध के आंकड़े (1998–2008)

वर्ष	बाल अपराधों की संख्या	कुल अपराध	कुल अपराध में बाल अपराधों का प्रतिशत	बाल अपराध दर (प्रतिशत में)
1998	9352	1778815	0.5	1.0
1999	8888	1764629	0.5	0.9
2000	9267	1771084	0.5	0.9
2001	16509	1769308	0.9	1.6
2002	18560	1780330	1.0	1.8
2003	17819	1716120	1.0	1.7
2004	19229	1832015	1.0	1.8
2005	18939	1822602	1.0	1.7
2006	21088	1878293	1.1	1.9
2007	22865	1989673	1.1	2.0
2008	24535	2093379	1.2	2.1

बागपत जनपद में बंदरों के हमले से घबरा कर औरंगाबाद निवासी जगवती अपने मकान की छत से सड़क पर गिर गई.

बंदरों का आतंक

हर इलाक़े में बंदरों का आतंक है. वे काट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन शासन-प्रशासन कान में उंगली डाले बैठा है. नगर निगम और वन विभाग कुछ करने के बजाय एक-दूसरे का मुंह ताकते हैं. कोई मरता है तो मरे, सरकार की बला से.

सुरेंद्र अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में थाना बेनीगंज अंतर्गत ग्राम सिकंदरपुर के निकट एक खेत में एक साथ नौ बंदर मृत पाए गए. बंदरों की मौत की ख़बर लगते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्र हो गई. अयोध्या फ़ैसले को लेकर चौकन्नी पुलिस ने किसी अनहोनी से पहले मामला रफा-दफा कर दिया, लेकिन बंदरों की लगातार बढ़ती संख्या शहर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है. बंदरों से परेशान नगर निगम ने कुछ समय पूर्व वन विभाग को भी एक पत्र लिखा था, लेकिन उसने शहरी क्षेत्र होने के कारण हाथ खड़े कर दिए. राजधानी लखनऊ में लगभग दो दर्जन क्षेत्र ऐसे हैं, जहां बंदरों के आतंक के चलते लोगों का जीना मुहाल है. बंदरों के शिकार हुए लोगों के लिए अस्पतालों में एंटी रैबीज़ वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है. पीड़ितों को यह महंगी वैक्सीन बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती है. अकेले चारबाग स्टेशन पर ही पिछले एक माह के अंदर कम से कम बीस लोग बंदरों के शिकार बन चुके हैं. बंदर घरों से कपड़े और खाने-पीने का सामान उठा ले जाते हैं. विरोध करने पर हमला करने से भी नहीं चूकते. वे हाथ में खाने-पीने की चीज़ें लेकर जा रहे राहगीरों को लूटने से परहेज़ नहीं करते. डर के मारे लोग अपने घरों की खिड़कियां-दरवाज़े बंद रखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी भी चूक हुई तो बंदर इसका लाभ उठाने से नहीं चूकते. एक अनुमान के अनुसार, शहर में तक़रीबन दो हज़ार बंदर हैं, जिनके चलते लोगों का जीना मुहाल है.

बंदर घर के ऊपरी कमरों में घुसकर या छत से कपड़े उठा लेते हैं और तब तक वापस नहीं देते, जब तक उन्हें खाने-पीने के लिए कुछ दिया न जाए. लोग जब इन्हें मारने दौड़ते हैं तो ये हमले की मुद्रा में आ जाते हैं. हालत यह है कि हाथरस ज़िले के बंदर अब पेशेवर अपराधियों की तरह पेश आने लगे हैं. पहले ये सामान छीन-उठा लेते हैं, फिर उसे वापस करने के नाम पर खुलेआम खाने-पीने की चीज वसूलना इनकी आदत बन गई है. राह चलते किसी से भी सामान छीन लेना इनकी दिनचर्या में शामिल है. बंदरों से बचाव के लिए लोग तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं दिख रहा. पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिनमें बंदरों के चलते लोगों की मौत हो गई या वे गंभीर रूप से घायल हो गए. सिकंदरामऊ में बंदर से डरी एक महिला की छत से गिरकर मौत हो गई. सहपऊ में एक युवती बंदर घुड़की से डरकर छत से गिर पड़ी. काफी उपचार के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका. जलेसर रोड पर एक महिला बंदर घुड़की से डरकर जीने से गिरी. उसे भी बचाया नहीं जा सका. इसी तरह गांव दर्शना में एक वृद्ध घर की छत पर सो रहा था. सुबह-सुबह बंदरों ने उसे घेर लिया. बचने के चक्कर में छत की मुंडेर से गिरकर वह भी मौत के मुंह में समा गया. अईयापुर गांव में भी बंदर घुड़की से एक युवती छत से गिरकर मर गई. बंदर दर्जनों लोगों को काटकर जख्मी कर चुके हैं. कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे मासूम बच्चों के लिए भी बंदर मुसीबत बन गए हैं. लखनऊ चिकित्सा विश्वविद्यालय में बंदरों ने छह बच्चों को काट खाया. इनमें से चार बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं.

बंदर घर के ऊपरी कमरों में घुसकर या छत से कपड़े उठा लेते हैं और तब तक वापस नहीं देते, जब तक उन्हें खाने-पीने के लिए कुछ दिया न जाए. लोग जब इन्हें मारने दौड़ते हैं तो ये हमले की मुद्रा में आ जाते हैं. हालत यह है कि हाथरस ज़िले के बंदर अब पेशेवर अपराधियों की तरह पेश आने लगे हैं. पहले ये सामान छीन-उठा लेते हैं, फिर उसे वापस करने के नाम पर खुलेआम खाने-पीने की चीज वसूलना इनकी आदत बन गई है.

बागपत जनपद में बंदरों के हमले से घबरा कर औरंगाबाद निवासी जगवती पत्नी भीम सिंह अपने मकान की छत से सड़क पर गिर गई. बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई. इसी तरह राजधानी लखनऊ से लगे अर्जुनगंज में बंदरों ने 80 वर्षीय राजकुमारी को अपना निशाना बनाया. इसी क्षेत्र में बंदरों ने आशा, विशाल, कमलेश तिवारी एवं रामचंद्र जायसवाल की पत्नी सहित 50 लोगों को घायल कर दिया. गोसाईगंज क़स्बे के सराई करोरा मोहल्ले के उत्पाती बंदर कई लोगों को काट चुके हैं. मातन टोला निवासी मुन्ना शर्मा बताते हैं कि राजधानी से कुछ बंदर पकड़ कर यहां छोड़ दिए गए. इन बंदरों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है. अमेठी के सखावत अली एवं चंद्रपाल बताते हैं कि बंदरों द्वारा घर से कपड़ा उठाना, बच्चों को काटना और सामान छीन लेना रोज की बात हो गई है. लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांव बंदरों के आतंक से पीड़ित हैं. वहीं बिरहाना में एलटी लाइनों पर बंदरों की उछलकूद के कारण आए दिन बिजली ग़ायब रहती है. बंदरों ने राजधानी के नादान महल उपकेंद्र में आग तक लगा दी थी. रायबरेली के सालोन क़स्बे में भी बंदरों ने आतंक मचा रखा है. लगभग पांच सौ बंदरों ने क़स्बे में इतनी मुश्किलें पैदा कर दी हैं कि यहां के नागरिक सोनिया गांधी तक से गुहार लगा चुके हैं.

हाथरस के शहरी क्षेत्र में बंदरों को पकड़ने की ज़िम्मेदारी नगरपालिका परिषद की है, लेकिन कस्बों में यह ज़िम्मेदारी नगर पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की है. बंदरों को पकड़ कर उनकी नसबंदी करने से नियंत्रण हो सकता है, लेकिन यह काम कौन करे? शहर की आबादी तेज़ी से बढ़ने के कारण बंदरों के आवासीय क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं. राजधानी लखनऊ के आसपास बसे कई गांव शहर की सीमा से आ मिले हैं.

वहां भी शहर की तर्ज़ पर पेड़ काटे जा रहे हैं और ऊंचे भवनों का निर्माण हो रहा है. ऐसे में स्वाभाविक है कि बंदर कहां जाएं? भोजन-पानी बंद होने की नौबत आते ही वे शहर की ओर रुख़ करने लगते हैं. बंदरों के प्रति भारतीय समाज का नज़रिया अलग तरह का होने के कारण इनसे मुक्ति के मार्ग में अनेक प्रकार के रोड़े आते हैं. वाराणसी में पिछले वर्ष एयरगन से मारे गए छह बंदरों की विधि-विधान से तेरहवीं की गई, जिसमें बंदरों ने छक कर भोजन किया. वानर नामक जीव जंगल से शहर में आए थे, तब वे बहुत शर्मीले थे, लेकिन भोजन एवं प्राकृतिक आवास के अभाव में आक्रामक और अड़ियल हो गए.

आज हालत यह है कि प्राचीन काल में जो वानर मानव के सहयोगी, मित्र और रक्षक की भूमिका में होते थे, वही आज मानव के प्रतिद्वंद्वी हो गए हैं. यही वजह है कि वृंदावन को जेलनुमा जालियों वाला तीर्थ क्षेत्र बनने के लिए मजबूर होना पड़ा. बंदरों को शहर से दूर करने के काम में लगे रजत भार्गव कहते हैं कि पूरे देश में 2 लाख 75 हज़ार बंदर मानव के आसपास रहते हैं. इनकी लगातार बढ़ती संख्या को रोकने के लिए नसबंदी कारगर उपाय हो सकती है. अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, लखनऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, सीतापुर, हरदोई, बरेली, कानपुर, गाजियाबाद एवं झांसी आदि ज़िले बंदरों से खासे परेशान हैं. बंदरों को पिंजरे लगाकर पकड़ने और जंगलों में छोड़ने वाले उस्मान कहते हैं कि बंदर एक सामाजिक प्राणी है. जब उसके कुनबे के अधिकतर बंदर पिंजरे में आ जाते हैं तो मुखिया बंदर स्वयं बंद होने चला आता है, लेकिन अपने साथियों को छुड़ाने के लिए वे हमला करने से भी नहीं डरते. इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में बंदरों के उत्पात से लोगों का जीवन प्रभावित है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सो रही है.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... बिग बॉस!! ...धीर

अयुध्या का सबसे महत्वपूर्ण भवन है तीन छेदी, जिसमें तीन राजाओं की खाक मिली है. यह जगह खास लोगों को समर्पित की गई.

एक और अयोध्या

रीतिका सोनाली

भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पूरे विश्व में गौरवपूर्ण स्थान हासिल है. संसार ने हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुराणों एवं ग्रंथों का लोहा माना है. विश्व के कई देशों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण किया है. दक्षिण पूर्व एशिया स्थित देश थाइलैंड भी प्रभु श्रीराम के जीवन से प्रेरित है. भारत के अयोध्या से प्रेरित थाइलैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आता है प्राचीन शहर अयुध्या. अयुध्या का उल्लेख इतिहास में स्याम राज्य की राजधानी के तौर पर किया गया है. अयुध्या नगरी की स्थापना एवं इसके इतिहास में यहां के आस-पड़ोस की जगहों का काफी महत्व और योगदान है. छोप्रया, पासाक एवं लोबपुरी नदियों के संगम पर बसा द्वीपनुमा शहर अयुध्या व्यापार, संस्कृति के साथ-साथ आध्यात्मिक अवधारणाओं का भी गढ़ रहा है. इसका नामकरण भारत के अयोध्या के नाम पर हुआ. अयोध्या का मतलब है अपराजेय. अयोध्या से इस शहर का नाम जोड़ने की वजह यह हो सकती है कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में इस क्षेत्र में हिंदुओं का वर्चस्व काफी ज्यादा था. पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित पर भारत में वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण थाइलैंड में महाकाव्य के रूप में प्रचलित है. लिखित साक्ष्यों के आधार पर माना गया है कि इसे दक्षिण एशिया में पहुंचाने वाले भारतीय तमिल व्यापारी और विद्वान थे. पहली सदी के अंत तक रामायण थाइलैंड के लोगों तक पहुंच चुकी थी. वर्ष 1360 में राजा रमाथीबोधी ने तर्वदा बौद्ध धर्म को अयुध्या शहर का शासकीय धर्म बना दिया था, जिसे मानना नागरिकों के लिए अनिवार्य था. लेकिन फिर इसी राजा को हिंदू धर्म का प्राचीन दस्तावेज हाथ लगा, जिससे प्रभावित होकर इसने हिंदू धर्म को ही यहां का आधिकारिक धर्म बना दिया, जो अब से एक शताब्दी पहले तक वैध था. अयुध्या के राजा केवल बौद्ध धर्म मानने वाले नहीं, बल्कि देवराजा भी हुआ करते थे. इसलिए इनकी शक्तियां केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होती थीं, जो हिंदुओं के इष्टदेव इंद्र एवं विष्णु से जुड़ी होती थीं. 17वीं शताब्दी के लेखक वैन लिएट ने लिखा है कि स्याम का राजा अपने राज्य के लोगों द्वारा अपने उसूलों की वजह से देवताओं से भी ज़्यादा पूजा जाता था. सम्राट के ख़िलाफ़ बोलने पर पंद्रह वर्षों की सजा का प्रावधान था. थाई संस्कृति एवं साहित्य का रामायण और पुरुषोत्तम राम से इस कदर जुड़ाव है कि यहां के राजा अपने नाम के साथ राम लगाया करते थे. चक्री वंश के राजा के नाम के साथ भी राम शब्द जुड़ा है. अयुध्या पर पांच राजवंशों के 33 राजाओं ने शासन किया है.

पुरातत्व शोधकर्ताओं के अनुसार, पत्थरों के ढेर में तब्दील हुए अयुध्या का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है. यहां स्थित अवशेष इसके वैभव का बखान करते हैं. इन्हीं अवशेषों के आसपास आधुनिक शहर बस जाने से अयुध्या थाइलैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार हो गया है, जिसे देखने प्रति वर्ष तक़रीबन दस लाख लोग आते हैं. ढही इमारतों की दीवारों में उग आए पेड़-पौधे, बिखरी पड़ी ईटें और अवशेष अयुध्या के आलीशान इतिहास से लेकर इसकी दुर्गति तक की कहानी बयां करते हैं. अयुध्या के इतिहास को लेकर दो तरह की मान्यताएं हैं. इसके बारे में उपलब्ध अधिकांश जानकारियां वर्ष 1350 और उसके इर्द-गिर्द ही घूमती हैं. पहली मान्यता यह है कि अयुध्या उस दौर की उत्तेजनात्मक राजनीतिक और फौजी गतिविधियों का केंद्र बनकर उभरा था, जबकि दूसरी मान्यता यह है कि यह शहर सांस्कृतिक और व्यापारिक विनियम का केंद्र हुआ करता था. अपने शिल्प-वैभव की वजह से अयुध्या राजनीतिक और आध्यात्मिक तौर पर अति प्रभावशाली राज्य माना जाता रहा. मठों, आश्रमों, नहरों एवं जलमार्गों की वजह से उस वक़्त इस शहर की तुलना धार्मिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से वेनिस और ल्हासा से की जाती थी. 1767 में म्यांमार के नागरिकों ने अयुध्या पर चढ़ाई करके इसे लूट लिया और तहस-नहस कर डाला. स्याम की राजधानी कहलाने वाला अयुध्या एक लुटे-पिटे शहर में तब्दील हो गया. अब यह स्याम की राजधानी नहीं रहा था. यहां केवल जंगल रह गए. 1976 में थाइलैंड की सरकार ने इस शहर के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया. यहां के जंगलों को साफ करके अवशेषों की मरम्मत की गई और वैश्विक पटल पर इसे खड़ा किया गया. वर्ष 1991 में यूनेस्को ने अयुध्या को मानवता का सम्मान करने वाले शहर की संज्ञा दी और इसे वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब दिया.

अयुध्या अपनी शिल्प प्रतिमाओं की वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ. यहां पर सबसे ज़्यादा वट, मंदिर एवं महल थे, जो भव्य और शानदार थे. तक़रीबन 400 वटों के साथ-साथ लगभग सभी स्मारकों का निर्माण शहर की स्थापना के 150 वर्षों के अंदर हुआ था. सभी इमारतें तो नहीं बची हैं, लेकिन जो बची हैं, वे अपनी गौरव गाथा बख़ूबी सुनाती हैं. अयुध्या का मुख्य आकर्षण है शहर के मध्य स्थित प्राचीन पार्क. इसके बिना शिखर वाले खंभों, दीवारों, सीढ़ियों एवं बुद्ध की सरकटी प्रतिमा की ओर लोगों का ध्यान बरबस ही चला जाता है. स्कल्पचर के बेहतरीन लालित्य एवं कला ने यहां की संस्कृति को जीवित रखा है, वरना यहां की सिरकटी मूर्तियां हास्यास्पद बन गई होतीं. थाइलैंड सरकार ने सोचा कि शहर में स्थित बौद्ध प्रतिमाओं को बचाने का सिर्फ़ एक उपाय है कि इनके आकार को बिगाड़ दिया जाए, इसलिए इन प्रतिमाओं के सिर हटाकर उन्हें संग्रहालयों में रखा गया. हालांकि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ. इसी जगह पर बची सिर वाली कुछ बौद्ध मूर्तियां अब भी उन कलाकारों की कारीगरी का प्रमाण हैं.

अयुध्या अपनी शिल्प प्रतिमाओं की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ. यहां पर सबसे ज्यादा वट, मंदिर एवं महल थे, जो भव्य और शानदार थे. तकरीबन 400 वटों के साथ-साथ लगभग सभी स्मारकों का निर्माण शहर की स्थापना के 150 वर्षों के अंदर हुआ था. सभी इमारतें तो नहीं बची हैं, लेकिन जो बची हैं, वे अपनी गौरव गाथा बख़ूबी सुनाती हैं.

सबसे ज़्यादा खास वह प्रतिमा है, जिसमें बुद्ध का सिर सैंड स्टोन से बनाया गया है और एक पीपल के वृक्ष की जड़ों में जकड़ा हुआ है. यह वृक्ष अयुध्या में वट महाथाट यानी 14वीं शताब्दी के प्राचीन साम्राज्य की स्मृति चिन्हों वाले मंदिरों केअवशेषों में मौजूद है. शहर में शेष बची बुद्ध प्रतिमाओं में से कुछ को बेच दिया गया या फिर सफाई के बाद तराश कर उन्हें दोबारा आकार देने की कोशिश की गई, जिससे उनका मूल स्वरूप नष्ट हो गया. पुरातत्वविदों ने इस मंदिर को शहर के केंद्र में बना सबसे ऐतिहासिक मंदिर बताया है. इसके साथ यह कथा प्रचलित है कि एक सुबह राजा इसी जगह पर बैठकर ध्यानमग्न था कि तभी उसे भूगर्भ से निकलती हुई अद्भुत दैवीय रोशनी नज़र आई. राजा को यह ज़मीन के नीचे गड़ी बुद्ध प्रतिमा से निकलने वाला प्रकाश लगा, इसीलिए इस जगह पर मंदिर का निर्माण कराया गया. यह मंदिर काफी आकर्षक था. इसके मध्य में बड़ा सा प्रांगण, 38 मीटर ऊंची भव्य मीनार और उस पर बनी लपेट छह मीटर ऊंची थी, लेकिन मंदिर की यह ख़ूबसूरती ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और 15वीं शताब्दी में यह ढह गया. बाद में इसे कई बार बनवाया गया, लेकिन असल रूप वापस नहीं हो सका. अब मीनारों की केवल नींव बची है. 1424 में राजा रक्षतीरथ द्वितीय द्वारा रक्षबुराना के प्रांगण में अपने पिता की समाधि के ऊपर एक वट बनवाया गया था. यहीं पर दो स्तूप हैं, जिन्हें राजा ने अपने दोनों भाइयों राजकुमार अई और राजकुमार ई की याद में बनवाया था. अब इन स्तूपों के अवशेष के रूप में केवल नींव ही बची है. 1957 में लुटेरों ने किसी पुराने खजाने को पाने की उम्मीद में प्रांगण के नीचे सुरंग बना दी थी. लुटेरे तो धरे गए, लेकिन सुरंग ने थाइलैंड के ललित कला विभाग को इस जगह और भी ज़्यादा अन्वेषण का मौक़ा दे दिया. खुदाई करने पर यहां बुद्ध की कई प्रतिमाएं, सोने के जेवरात और दीवारों पर टांगे जाने वाले चित्र मिले. राजा के महल के क़रीब बना वट हरे राम मंदिर सबसे ज़्यादा सुरक्षित तरीक़े से रखा गया है. इस वट में बने संगमरमर के स्तूप खास हैं. ये चारों तरफ़ से गरुड़, नाग एवं बुद्ध की प्रतिमाओं से घिरे हैं.

अयुध्या का सबसे महत्वपूर्ण भवन है तीन छेदी, जिसमें तीन राजाओं की खाक मिली है. यह जगह खास लोगों को समर्पित की गई. यहां पूजा-अर्चना की जाती थी और समारोह आयोजित होते थे. विहार फ्रा मोंग खोन बोफिट एक बड़ा प्रार्थना स्थल है. यहां बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा है. यह पहले 1538 में बनाई गई थी, लेकिन बर्मा द्वारा अयुध्या पर चढ़ाई के दौरान नष्ट हो गई थी. यह प्रतिमा पहले सभागार के बाहर हुआ करती थी, बाद में इसे विहार के अंदर स्थापित किया गया. जब विहार की छत टूट गई, तब एक बार फिर प्रतिमा को काफी नुक़सान पहुंचा और राजा राम षष्ठम ने लगभग 200 वर्षों बाद इसे वहां से हटवा कर संग्रहालय में रखवा दिया. 1957 में फाइन आर्ट्स विभाग ने पुराने विहार को फिर से बनवाया और सुनहरे पत्तों से ढंक कर बुद्ध की प्रतिमा को फिर से पुरानी जगह पर रखवाया. फ्रा भेदी सी सूर्योथाई स्मारक रानी सूर्योथाई के सम्मान में बनवाया गया था, क्योंकि वह ख़ुद सिपाही का वेश धारण करके हाथी पर सवार होकर अपने पति को बचाने के लिए जंग में उतर पड़ी थीं. स्तूप उसी जगह पर बना है, जहां रानी को दफनाया गया था. अयुध्या का पुनर्निर्माण इस तरह संभाल कर किया गया, जिससे आकृतियों को नुक़सान न पहुंचे.

ritika@chauthiduniya.com

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्य विभागों द्वारा यद्यपि गर्भवती महिलाओं को न्यूनतम भोजन देने की कई योजनाएं हैं, पर पता नहीं क्यों, उनका लाभ समय रहते जरूरतमंद महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है.

मेघनाद देसाई

भ्रष्टाचार एक लाइलाज बीमारी

उन्नीस सौ पचास के दशक के आख़िरी दिनों में गुजरात में एक अभिनेता–लेखक हुआ करते थे, जयंती पटेल. उन्होंने एक नाटक लिखा था नेता अभिनेता, जिसमें मुख्यमंत्री अपने एक भ्रष्ट मंत्री से इस्तीफ़े की मांग करता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहता है कि उसे केवल अपना इस्तीफ़ा देना है, पैसे वापस नहीं करने हैं. मैं इस वाकये के साथ शुरुआत यह बताने के लिए कर रहा हूं कि राजनीतिज्ञों के बीच भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है. अब इसमें पैसे की मात्रा बढ़ गई है और यह लगातार नई उंचाइयां छू रही है, लेकिन भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पहले भी मौजूद रही है. अब घूसखोर नेता ज़्यादा निर्लज्ज हो गए हैं और क़ानून भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता. आदर्श सोसाइटी घोटाले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा देने या पूर्व सैनिकों, जिन्हें घर मिलने के अधिकार से उन्होंने वंचित किया, को किसी प्रकार का जुर्माना देने की कोई चर्चा नहीं हुई. अब यदि आप इसलिए डर रहे हैं कि चव्हाण को दंडित किया जाएगा तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. वैसे भी मामले की जांच का जिम्मा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को दिया गया है, जो इस बात की गारंटी है कि चव्हाण का कुछ नहीं बिगड़ेगा. यह भी सुनने में आ सकता है कि चव्हाण ने कुछ ग़लत किया ही नहीं था. उन्होंने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के क़ानूनों के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन एक मंत्री होने के नाते उनके पास ऐसा करने के अधिकार थे. ऐसे तर्कों का एक ही मतलब है कि मौजूदा दौर में फर्जीवाड़े और घोटाले गैर कानूनी नहीं रह गए हैं. सुरेश कलमाडी को कांग्रेस पार्टी में केवल उनके पद से ही हटाया गया है. वह भी केवल इसलिए कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में विपक्षी पार्टियों को सरकार पर उंगली उठाने का मौक़ा न मिले. इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉमनवेल्थ घोटाले का शोर ठंडा होने के साथ इसमें शामिल हर शख्स बेदाग बच जाएगा, उन्हें आम माफी मिल जाएगी. ऐसी चीजें तब होती हैं, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, ताकि कोई शोरगुल न हो और सदन की कार्यवाही में कोई बाधा न पहुंचे.

यही बात ए राजा पर भी लागू होती है. हमें यह बताया जाएगा कि 1.7 लाख करोड़

रुपये का घाटा कोई बड़ी बात नहीं है. यदि राजा ने 2–जी लाइसेंस के लिए नीलामी का सहारा लिया होता तो यह पैसा आम जनता के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने नीलामी का रास्ता नहीं चुनने की नीति बनाई है और करोड़ों की संपत्ति औने–पौने दामों पर बेची जा रही है. यह वह बहाना है, जो हमें आने वाले दिनों में सुनने को मिलेगा. लेकिन सवाल यह है कि जब पहली बार ऐसा फ़ैसला लिया गया था तो क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ था और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि स्पेक्ट्रम का लाइसेंस हासिल करने वाली पार्टियों ने फ़ैसला लेने के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कोई रिश्वत तो नहीं दी थी? ब्रिटेन की सरकार ने स्पेक्ट्रम लाइसेंस के आवंटन से 23 बिलियन डॉलर की कमाई की थी और दुनिया के कई अन्य देशों की सरकारों ने भी ऐसा ही किया. लाइसेंस के आवंटन के लिए नीलामी का रास्ता न चुनना भारत की जनता के साथ एक फर्जीवाड़ा है, तो इसके लिए दोषी कौन है? लेकिन हमें इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे सवाल कभी उठाए ही नहीं जाते हैं. जरा कर्नाटक विधानसभा के उन दृश्यों को याद कीजिए, जिसमें सदस्यों ने दलबदल के लिए 15–25 करोड़ रुपये लिए थे और इसे कई लोगों ने टीवी न्यूज़ चैनलों पर देखा था, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसके ख़िलाफ़ मामला दायर करने की मांग नहीं की. इसकी वजह यह है कि हमाम में सभी नंगे हैं, सभी पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए ऐसे दुष्कृत्यों में शामिल हैं. इसी का नतीजा है कि व्यवस्था में सुधार के लाख वादे किए जाएं, लेकिन होता कुछ नहीं है और न ही होने की उम्मीद है. दलबदल के लिए सांसदों और विधायकों के साथ पैसों का लेनदेन होता है और यह बात हम सभी जानते हैं. इसका एक उदाहरण हम न्यूक्लियर डील पर मतदान के दौरान संसद में भी देख चुके हैं, जब नोटों के बंडल लोकसभा में पहुंच गए थे और हमने उसे टीवी पर देखा था.

भारत एक महान लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन यह सबसे भ्रष्टतम देशों में से भी एक है. 1950 के दशक में राजनीतिज्ञ व्यक्तिगत स्तर पर रिश्वत लेते थे, लेकिन अब तो इस काम में हर राजनीतिक पार्टी शरीक है. पार्टियों की फंडिंग का तरीक़ा बिल्कुल अपारदर्शी है और इसमें सदस्यता शुल्क या चंदे के बजाय भ्रष्टाचार का ही ज़्यादा योगदान होता है. निराशाजनक तथ्य यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है, जिससे इस भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोई उम्मीद की जा सके. भारतीय मतदाता अब इसे स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि वे पंगु व्यवस्था के रंग–ढंग में बस चुके हैं. ताजा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से भारत की इस स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. 1990 में इसकी शुरुआत के बाद से ही भारत मानव विकास सूचकांकों के विभिन्न पैमानों पर लगातार पिछड़ता रहा है, लेकिन स्थिति में सुधार के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं. ख़ैर, ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी तरह के अकेले भले हों, लेकिन वह भ्रष्ट नहीं हैं.

feedback@chauthiduniya.com

जन्म से पहले की भूख

ग़रीबों के नाम पर योजनाएं ढेर सारी हैं, लेकिन वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियों के कारण आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी होती जा रही है. भारत में हर साल लगभग 25 लाख शिशुओं की अकाल मृत्यु हो जाती है. इसी तरह 42 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं. यहां असली समस्या बच्चों के जन्म के पहले ही शुरू हो जाती है. हाल में आई अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट अनुसार, ग़रीबी, भुखमरी और कुपोषण से प्रभावित 84 देशों की सूची में भारत चीन और पाकिस्तान से ही नहीं, सूडान से भी पिछड़ता हुआ 67वें स्थान पर है. पाकिस्तान का 52वां एवं नेपाल का 56वां स्थान है, जबकि चीन 7वें स्थान पर है. मतलब यह कि सारी राजनीतिक बुराइयों के बावजूद अपनी जनता की देखभाल में चीन की स्थिति हमसे बहुत बेहतर है. संस्थान ने बच्चों में कुपोषण, बाल मृत्यु दर और न्यूनतम कैलोरी पा सकने वाले लोगों के अनुपात को अपने अध्ययन का आधार बनाया है. मनमोहन सिंह सरकार मंदी के दौर में भी प्रगति और उच्च विकास दर के दावे कर रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने तथ्यों के आधार पर साबित किया है कि यहां पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक लोग भुखमरी के शिकार हैं और ऊंची विकास दर का लाभ अत्यंत ग़रीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है.

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्य विभागों द्वारा यद्यपि गर्भवती महिलाओं को न्यूनतम भोजन देने की कई योजनाएं हैं, पर पता नहीं क्यों, उनका लाभ समय रहते जरूरतमंद महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है. गोदामों के अभाव में अनाज सड़ रहा है, बावजूद इसके सरकार उसे भूखे–नंगों को मुफ्त बांटने के लिए तैयार नहीं है. यह तर्क दिया जाता है कि मुफ्त या सस्ता अनाज उपलब्ध कराने से किसान उत्पादन के क्षेत्र में हतोत्साहित होंगे. यह तर्क बेमानी है. सरकार किसानों को अधिक सब्सिडी देने की योजना क्यों नहीं अपनाती? अमेरिका और यूरोप में अनाज सस्ता होने के बावजूद सरकारी संरक्षण के चलते किसानों को कोई शिक़ायत नहीं है. इसी तरह अति पिछड़े–आदिवासी क्षेत्रों एवं शहरों की ग़रीब बस्तियों में सरकार बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए समुचित खाद्यान्न वितरण की योजनाएं क्यों नहीं लागू कर रही है? यह एक बड़ा सवाल है. भारत के एक ग़ैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, आबादी के हिसाब से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश में तक़रीबन 21 करोड़ से अधिक लोगों को भरपेट भोजन नहीं

मिल पाता है. संख्या के अनुपात में यह अफ्रीका के सबसे ग़रीब देशों से भी ज़्यादा है.

उक्त आंकड़े नवदान्य ट्रस्ट द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जिसमें कहा गया है कि बढ़ती महंगाई और सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हाल के दिनों में फैलाई गई अव्यवस्था ने स्थिति को और भी बदतर कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक़, सरकार और देश का एक वर्ग भले ही जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने को ही सबसे अहम काम समझ रहा है, पर सच तो यह है कि एक आम आदमी को प्रति वर्ष मिलने वाली खाद्य सामग्री पिछले 10 वर्षों के भीतर 34 किलो कम हो गई है. वर्ष 1999 के आसपास भारत में खाद्य सामग्री की प्रति व्यक्ति सालाना खपत 186 किलोग्राम थी, जो 2001 तक 152 किलोग्राम जा पहुंची. देश में आर्थिक उदारीकरण का काम 90 के दशक में शुरू हुआ था, तब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की नरसिंहराव सरकार थी. पिछले पांच–छह वर्षों में ग़रीबों को मिलने वाली खाद्य सामग्री में और भी कमी आई है. क़ीमतों में बढ़ोत्तरी की सच्चाई छिपाने के लिए सरकार ने खाद्य पदार्थों को स्टील और अन्य धातुओं की क़ीमतों के आकलन वाले वर्ग में डाल दिया है, जिनकी क़ीमतें तेजी से गिरती रही हैं. इस तरह खाने–पीने की वस्तुओं की थोक क़ीमतों में गिरावट तो देखी गई है, लेकिन असल में खाद्य पदार्थों की क़ीमतें बढ़ी हैं. सालाना महंगाई जिस फार्मूले से आंकी जाती हैं, उसमें ज़रूरत के सामानों के अलग–अलग वर्ग तैयार किए जाते हैं, जिसमें मौजूदा क़ीमतों के आधार पर एक महंगाई दर का आकलन किया जाता है.

भूख के कारण नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र एवं खाद्य सामग्री के वितरण में निजी कंपनियों के बढ़ते दखल ने खाने–पीने की चीजों की क़ीमतें बढ़ा दी हैं. इससे खाने–पीने की वस्तुओं पर सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट यानी सब्सिडी में भी इज़ाफ़ा हुआ है. आर्थिक उदारीकरण के पहले दी जाने वाली सब्सिडी 2450 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 32,667 करोड़ रुपये हो गई है. कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि अगले साल खाद्य सामग्री पर दी जाने वाली कुल छूट 50,000 करोड़ रुपये हो जाएगी. उदारीकरण के बाद से सरकार ने छूट के नाम पर सिर्फ़ बहुत ग़रीब वर्गों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ता अनाज देने की सुविधा जारी रखी है. पहले सस्ते दामों पर खाने–पीने के सामान की सुविधा सभी नागरिकों को थी. अब यह सुविधा जनसंख्या के सिर्फ़ एक छोटे वर्ग को ही मिल रही है. एक अनुमान के मुताबिक़, ग़रीबों में भी यह सुविधा केवल 10 प्रतिशत लोगों को ही उपलब्ध है. हाल के वर्षों में 80 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर निर्यात की जाने वाली सामग्री उगाई जा रही है, जबकि एक करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर जैविक ईंधन पैदा करने वाले पेड़ लगा दिए गए हैं. विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ली जाने वाली ज़मीनों से कृषि क्षेत्र पर दबाव और बढ़ेगा. सरकार को हर नागरिक के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था करनी होगी, जिसका नियंत्रण स्थानीय स्तर पर होना चाहिए. साथ ही एक ऐसी कृषि व्यवस्था को दोबारा बढ़ावा देना होगा, जहां केवल नगदी फ़सल पर जोर न होकर पहले की भांति हर किस्म का अनाज उपजाने को महत्व मिले, अन्यथा कहानी दिन–प्रतिदिन बिगड़ती चली जाएगी.

आशा त्रिपाठी
feedback@chauthiduniya.com

राहुल गांधी और बिहार

15–21 नवंबर के अंक की आवरण कथा–बिहार में राहुल फेल हो गए पढ़ी. राहुल के संदर्भ में आपने सही कहा कि बिहार चुनाव उनके लिए एक प्रयोगशाला के समान है, जहां के परीक्षण ही उन्हें प्रधानमंत्री पद की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं. इस सच से तो कोई इंकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस किसी समय बिहार की सबसे मज़बूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज उसकी हालत राज्य में संतोषजनक नहीं हैं. इसके भी कई कारण हैं. सबसे खरी बात आपने यह कही कि जिन समस्याओं–सवालों को चुनावी मुद्दा बनना था, उन्हें हाशिए पर छोड़ सबने नीतीश को ही अपने निशाने पर रखा.

–रामानंद पांडेय, *सहरसा, बिहार.*

काश कि ऐसा हो

तोप मुकाबिल (15–21 नवंबर) के तहत बिहार पूरे देश को सबक दे पढ़ा. बिहार में चुनाव लोकसभा के हों या विधानसभा के, बाहुबलियों का हमेशा वर्चस्व रहा है. वे जीतते भी रहे हैं और दूसरों को जितवाते भी रहे हैं. उन्हें टिकट देने के पीछे राजनीतिक दलों का अपना स्वार्थ रहा है. यह अच्छी बात है कि अब जनता ने परिवारवाद के पोषकों, अपराधियों, दागियों और बाहुबलियों से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है. इस संदर्भ में आपकी अपील कि ऐसे तत्वों को चुनाव में जीतना नहीं चाहिए, बिहार के लिए सर्वथा हितकारी साबित होगी, बशर्ते यह बात जनसाधारण की समझ में आ जाए.

–जय प्रकाश सिंह, *पटना, बिहार.*

स्वास्थ्य सेवाओं में लिंगभेद

आलेख–स्वास्थ्य सेवाओं में लिंगभेद: नज़रिए में बदलाव की ज़रूरत के जरिए लेखक ने एक गंभीर समस्या पर रोशनी डाली है और यह सच है कि आज भी विभिन्न बिंदुओं पर लिंगभेद जारी है. लड़कियों–महिलाओं को हर मोड़ पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है. चाहे शिक्षा की बात हो या चिकित्सा सुविधा की, यह वर्ग हमेशा वंचित रखा जाता है. यह स्थिति समाज के लिए किसी भी नजरिए से उचित नहीं है. हमें निश्चित तौर पर अपनी सोच में बदलाव करना होगा.

–रचना सत्संगी, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

धीर के कॉर्टून

मेरी दुनिया पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला कार्टून कॉलम मैं हमेशा पढ़ता हूं. कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से सामने रखना धीर जी की खासियत है. इसके लिए उन्हें और चौथी दुनिया को बधाई.

–राजकुमार, *उत्तम नगर, नई दिल्ली.*

अरुंधति और पडगांवकर के बयान

कश्मीर मसले को लेकर पिछले दिनों आए अरुंधति राय और दिलीप पडगांवकर के बयानों के संदर्भ में सरकार के रवैये में ज़बरदस्त विरोधाभास नज़र आता है. अगर अरुंधति का यह कहना कि कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं रहा, देशद्रोह की श्रेणी में आता है तो पडगांवकर के बयान को सामान्य क्यों मान लिया गया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए जारी बातचीत में पाकिस्तान को भी एक पक्ष बनाया जाना चाहिए. यह तो सीधा–सीधा राष्ट्रद्रोह है. इस तरह का दोहरापन न केवल सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा करता है, बल्कि किसी भी समस्या को और पेचीदा बना सकता है.

–राजेंद्र निगम, *भोपाल, मध्य प्रदेश.*

जनस्वास्थ्य की अनदेखी

माफिया के हवाले स्वास्थ्य सेवाएं शीर्षक से उत्तर प्रदेश के संबंध में प्रकाशित रपट चिंतित करती है. इससे बड़ा दुर्भाग्य भला और क्या हो सकता है कि जनस्वास्थ्य की इस कदर अनदेखी की जा रही है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में अपराधियों–माफ़ियाओं की घुसपैठ है. यही नहीं, विभागीय मंत्री भी इस हैसियत में नहीं हैं कि वे ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ कुछ कर सकें. जिन अफसरों ने सख्ती बरतने का प्रयास किया, वे अपनी जान से हाथ धो बैठे. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के निमित्त दिए जा रहे पैसे माफ़ियाओं की जेब में जा रहे हैं. लूट के इस खुले खेल के ख़िलाफ़ शीघ्र ही कठोर कदम उठाए जाने चाहिए.

–रणधीर कुमार रावत, *बरेली, उत्तर प्रदेश.*

पिपलांत्री का संदेश

भारत गांवों का देश है. यहां कई ऐसे पिछड़े गांव हैं, जहां जनता में जागरूकता के अभाव के चलते विकास नहीं हो पाता. वहां जनप्रतिनिधि मनमानी करते रहते हैं, विकास का पैसा उनकी जेबों में चला जाता है और इलाके की हालत जस की तस रहती है. पिपलांत्री पंचायत के बारे में छपी सकारात्मक ख़बर पढ़कर अच्छा लगा. यह संदेश दूर तक पहुंचना चाहिए. यह विकास की वह कहानी है, जिससे पूरे देश के लोग सबक ले सकते हैं.

–धनंजय, *रोहतक, हरियाणा.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

अब भ्रष्टाचार से लड़ने का समय आ गया है

अभी कुछ महीनों पहले तक कहा जाता था कि भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अंग बन गया है और अब इस पर बात करना बेकार है. यहां तक बातें शुरू हो गई थीं कि काली कमाई पर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगा दो, ताकि लोग उसे डिक्लेयर कर अपने बैंक में रख सकें, इससे पैसा विदेशी बैंकों में तो नहीं जाएगा.

लेकिन अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, यही कहावत हमारे समाज में प्रचलित है. भ्रष्टाचार की अति हो गई. सरकार चलाने के लिए देश लूटने की छूट देने वाला प्रधानमंत्री कार्यालय अपने मन से तो यह फ़ैसला नहीं कर सकता. दयानिधि मारन ने संचार मंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को खत लिखा कि क़ीमतें तय करने में कोई हस्तक्षेप न करे और न ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने. प्रधानमंत्री ने इसे मान लिया. जब ए. राजा ने लूट और मनमानी शुरू की, तब प्रधानमंत्री ने उस समय के ट्राई के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र को बुलाया और बात की. नृपेंद्र मिश्र ने अपनी स्पष्ट राय दी. इसके बाद नृपेंद्र मिश्र ने प्रधानमंत्री कार्यालय को खत लिखकर सारी बातें आधिकारिक कर दीं.

इसके बाद भी प्रधानमंत्री खामोश रहे. सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, जिसका उत्तर प्रधानमंत्री ने पंद्रह महीनों तक नहीं दिया. स्वामी और प्रधानमंत्री दोनों न केवल अर्थशास्त्री हैं, बल्कि 23 साल पुराने दोस्त भी हैं. स्वामी ख़ुद भूतपूर्व मंत्री और भूतपूर्व सांसद हैं. हक़ीक़त यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जब सांसदों के पत्रों का ही समय पर उत्तर नहीं देता तो भूतपूर्व सांसद तो उसके लिए कीड़े–मकोड़े हैं.

ए. राजा का भ्रष्टाचार, जिसके कारण सरकार को दो लाख करोड़ के आसपास का नुक़सान हुआ, यूं ही नहीं हुआ. इसके एवज में अगर दो प्रतिशत भी किसी के पास इस अनुकंपा की वजह से गए हों तो रकम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. आशंका इस बात की है कि करुणानिधि अब ए. राजा का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें भी ए. राजा ने सही रकम का अंदाज़ा नहीं दिया था. यह रकम हवाला के ज़रिए बाहर गई और अब मॉरीशस के रास्ते वापस हिंदुस्तान आई है. अगर किसी कंपनी के एक शेयर की क़ीमत डेढ़ सौ करोड़ रुपये रखी जाए और उसे कोई ख़रीद ले तो इसका मतलब कि पैसा सफेद होकर वापस आ रहा है.

ए. राजा का इस्तीफ़ा हुआ. इस्तीफ़ा इसलिए नहीं हुआ कि संसद नहीं चल रही थी, बल्कि इसलिए हुआ, क्योंकि पिछली पंद्रह नवंबर को इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लगा कि कहीं प्रधानमंत्री पर कोर्ट ने टिप्पणी कर दी तो क्या होगा? उनकी आशंका सही थी. कोर्ट ने टिप्पणी भी की और पहली बार प्रधानमंत्री को एफीडेविट देने के लिए कहा. पहली बार अदालत को लगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी झूठ बोल सकता है. एफीडेविट या शपथ पत्र तभी लिया जाता है, जब यह निश्चित करना हो कि बयान बदला नहीं जाएगा. सोनिया गांधी और उनके सलाहकारों को लगा कि अब किसी मज़बूत आदमी को बचाव में उतारना चाहिए. कपिल सिब्बल को संचार मंत्रालय का अतिरिक्त चार्ज देना दस जनपथ की राय पर हुआ है. दस जनपथ को लगा कि सुब्रमण्यम स्वामी को हीरो नहीं बनने देना है और कपिल सिब्बल ने इसकी कोशिश भी शुरू कर दी है.

एक सवाल खड़ा होता है दिमाग़ में कि क्या ए. राजा अकेले इतना बड़ा काम कर सकते थे? उत्तर है नहीं, जब तक इसमें किसी आईएएस अफसर का हाथ न रहा हो. कौन है वह आईएएस अफसर, जो संचार मंत्रालय के फ़ैसलों को कार्यान्वित करा सकता है और जिसके दस्तखत के बिना फाइल पर लिखा कुछ भी जाए, पर वह फ़ैसला नहीं बन पाता. फ़ैसला मंत्री का दस्तखत नहीं, आईएएस अफसर का दस्तखत होता है. इस अफसर को कौन तलाश करेगा और कौन पहचान करेगा. सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट यह कर सकता है, क्योंकि आज तक किसी भी केस में कोई आईएएस अफसर फंसा ही नहीं है.

जो छोटा भ्रष्टाचार करते हैं, वे भी सदमे में हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने वाला गिरोह भी बच सकता है क्या. जनता भी सदमे में है कि भारत जैसे महान देश में यह क्या हो रहा है. लोगों को डर है कि सरकारी भ्रष्टाचार की जब दुनिया की सूची बनेगी तो भारत उसमें सबसे ऊपर होगा. सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनीं, देश ने इसे काफी सराहा. पर अब जो हो रहा है, क्या उसकी रत्ती भर भी ख़बर सोनिया गांधी को नहीं थी?

अब समय आ गया है कि भ्रष्टाचार के ऊपर देश के लोग एक बार फिर सोचें. चाहे छोटा हो या बड़ा, कांड करने में कोई पीछे नहीं है. कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें देश का एक बड़ा परिवार फंसा है. संचार घोटाले को भी दब जाना चाहिए, क्योंकि इसे दबाने के लिए ऐसे क़दम उठने शुरू हो गए हैं, जिनसे लगे कि अब हम कंपनियों से पैसा वसूल लेंगे. होना यह चाहिए था कि उन सभी कंपनियों को, जिनका न कोई अनुभव है, न उनका कोई अनुभवी सहयोगी, ऐसे सभी लोगों का पैसा जब्त कर लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए. एक बड़ी चेन होगी, जिसमें मंत्री से लेकर सेक्रेटरी, मंत्री का स्टाफ तथा औद्योगिक घरानों को एक साथ, एक बराबर अपराधी मानना चाहिए.

अब तो हद हो गई है. भारत की सेना भी भ्रष्टाचार का उदाहरण बनने जा रही है. एक छोटा उदाहरण आदर्श सोसाइटी घोटाला है, लेकिन पुणे–मुंबई के साथ लखनऊ में स्थित सेना के मध्य कमान की ज़मीन हड़पी गई है, बेची गई है. मध्य कमान की ज़मीन जहां–जहां है, वहां मॉल्स हैं, घर हैं, दुकानें हैं. इसमें सेना के ही लोग शामिल हैं. यह हमारी शानदार सेना है, जो चीन के अलावा किसी युद्ध में शर्मिंदा नहीं हुई. जवानों ने हर युद्ध में आगे बढ़कर जानें दीं. लेकिन जो लोग सीमा पर नहीं जाते, सेना के दूसरे अंग संभालते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है. पर ऐसे लोगों ने भारतीय सेना को शर्मसार कर दिया है. आज आवश्यकता है कि भारतीय सेना के ऊपर संसद की संयुक्त समिति बने और ऐसे लोगों की पहचान करे, जिन्होंने भ्रष्टाचार में हाथ बंटाया है.

जो छोटा भ्रष्टाचार करते हैं, वे भी सदमे में हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने वाला गिरोह भी बच सकता है क्या. जनता भी सदमे में है कि भारत जैसे महान देश में यह क्या हो रहा है. लोगों को डर है कि सरकारी भ्रष्टाचार की जब दुनिया की सूची बनेगी तो भारत उसमें सबसे ऊपर होगा. सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनीं, देश ने इसे काफी सराहा. पर अब जो हो रहा है, क्या उसकी रत्ती भर भी ख़बर सोनिया गांधी को नहीं थी? वह कहती हैं कि विकास हुआ, पर नैतिक मूल्य कमज़ोर हुए हैं. अगर यह एहसास है तो इसके लिए देश के सामने उदाहरण भी सर्वोच्च लोगों को ही प्रस्तुत करना होगा. लेकिन आज इसके लिए कौन तैयार है सोनिया जी... देश के लोग तैयार हों, तभी कुछ होगा...लेकिन देश के लोगों को तैयार करने वाले लोग भी तो चाहिए...

संपादक
editor@chauthiduniya.com

कश्मीरियों की व्यथा कब तक अनसुनी की जाएगी

अरुंधति राय के इस वक्तव्य कि कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा नहीं है, पर काफी बवाल मचा. भाजपा ने मांग की कि अरुंधति के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मुक़दमा क़ायम किया जाना चाहिए. भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने उनके दिल्ली स्थित निवास में तोड़फोड़ की और बजरंग दल ने उन्हें कई तरह की धमकियां दीं. इस वक्तव्य ने कई वर्गों को नाराज़ किया और अरुंधति को देशद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किए जाने की चर्चा कई दिनों तक चलती रही. अलग–अलग कारणों से, कश्मीर हमारे देश की जनता के एक बड़े हिस्से की दुखती रग बन गया है. कश्मीर समस्या का हल क्या हो, इस बारे में हमारे अरुंधति राय से मतभेद हो सकते हैं और प्रजातंत्र में ऐसे मतभेद पूरी तरह जायज़ भी हैं, परंतु इस मामले में दो तथ्यों को हम सभी को स्वीकार करना होगा. पहला यह कि कश्मीर का भारत में विलय कभी नहीं हुआ. कश्मीर केवल भारत का हिस्सा बना और वह भी इस शर्त पर कि रक्षा, मुद्रा, विदेशी मामलों और संचार को छोड़कर अन्य सभी मामलों में उसे पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त रहेगी. दूसरा यह कि कश्मीर मामले पर अरुंधति के बयानों, लेखों एवं भाषणों से कश्मीरियों की व्यथा से परिचित होने में हमें मदद मिली है. अरुंधति पर किए जा रहे हमले संबंधित लोगों की कश्मीर के भारत का हिस्सा बनने के इतिहास के बारे में अज्ञानता को प्रतिबिंबित करते हैं. धर्म आधारित राष्ट्रवाद के पैरोकार, कुछ बुद्धिजीवी एवं आमजन एक प्रकार की देशभक्ति की भावना के वशीभूत होकर यह मानते हैं कि भारत के लिए अपनी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करना सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए कश्मीरियों की समस्याओं को दरकिनार क्यों न करना पड़े.

कश्मीर भारत में कैसे मिला? हम सभी को मालूम है कि स्वतंत्रता के समय देश में सैकड़ों राजे–रजवाड़े थे. इनमें से

कश्मीर की समस्या जटिल है, जिसका कोई आसान हल दिखाई नहीं देता. इसका एक कारण यह है कि इस मामले से कई पक्षों के हित जुड़े हुए हैं. इनमें शामिल हैं अमेरिका समर्थित पाकिस्तानी सेना, कश्मीर की आम जनता, वहां के अतिवादी, भारतीय सेना, भारत सरकार एवं कश्मीर के राजनीतिक दल और नेता. कश्मीरियों ने अतिवादियों और सेना, दोनों के घोर अत्याचार सहे हैं. उनके दुःख और व्यथा को समझना ज़रूरी है. संवाद तो आवश्यक है ही, सेना की उपस्थिति भी कम की जानी चाहिए.

जूनागढ़, कश्मीर एवं हैदराबाद को छोड़कर शेष सभी भारत में विलय के लिए सहर्ष राजी हो गए. देश के विभाजन के समय राजे–रजवाड़ों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वे या तो भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, परंतु इस मामले में निर्णय लेने से पहले वे अपनी जनता की भावनाओं और अपनी भौगोलिक स्थिति का ख्याल रखें. जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद के शासकों द्वारा अपने राज्यों का भारत में विलय न करने के पीछे उनकी अलग–अलग सोच थी. जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे. हैदराबाद के निजाम या तो स्वतंत्र बने रहना चाहते थे अथवा पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे. इसका कारण यह था कि पाकिस्तान ने देशी रियासतों के शासकों को अधिक शक्तियां देने का वादा किया था. भौगोलिक दृष्टि से जूनागढ़ और हैदराबाद का पाकिस्तान में विलय मुश्किल था, क्योंकि वे पाकिस्तान की सीमा से बहुत दूर स्थित थे. दूसरी बात यह कि इन दोनों राज्यों की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी. सैन्य बल का इस्तेमाल करके इन दोनों राज्यों को भारत में अपना विलय करने के लिए मजबूर कर दिया गया. इस तरह यह अध्याय बंद हुआ. अब बचा कश्मीर. कश्मीर की स्थिति इन दोनों राज्यों से अलग थी. उसकी सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती थीं. कश्मीर की 80 प्रतिशत आबादी मुस्लिम थी और वहां के निवासियों के लंबे समय से उन इलाक़ों में संपर्क–संबंध थे, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे. कुल मिलाकर कश्मीर द्विराष्ट्र सिद्धांत के पैरोकारों का स्वर्ग था.

कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने भारत या पाकिस्तान दोनों में विलय करने से इंकार कर दिया. पाकिस्तानी सैनिकों ने कबाइलियों का वेश धरकर कश्मीर में वही करने की कोशिश की, जो भारतीय सेना ने हैदराबाद और जूनागढ़ में किया था, परंतु कश्मीर के मामले में अंतर यह था कि वहां नेशनल कांफ्रेंस का व्यापक प्रभाव था और उसके नेता शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानी शासक वर्ग की सामंती सोच से अच्छी तरह वाक़िफ़ थे. कश्मीर पर हमला होते ही महाराजा हरी सिंह अपनी जान बचाने के लिए जम्मू भाग गए और उन्होंने अपने एक दूत को दिल्ली भेजकर भारत सरकार से मदद मांगी. भारत सरकार चाहती थी कि अपनी सेना भेजने से पहले वह कश्मीर के साथ किसी तरह का समझौता कर ले. इन परिस्थितियों में कश्मीर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें रक्षा, संचार, मुद्रा एवं विदेशी मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में कश्मीर को पूर्ण स्वायत्तता दी गई. इसके बाद भारतीय सेना कश्मीर पहुंची, परंतु तब तक पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के एक तिहाई हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया था. इसके बाद युद्ध विराम हो गया. कश्मीर में चुनाव हुए, जिसमें शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधानमंत्री (मुख्यमंत्री नहीं) चुने गए.

पंडितों सहित सभी कश्मीरियों की व्यथा समझने के लिए हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए कश्मीर इलाक़े पर अपना प्रभाव जमाने का षड्यंत्र किया. इसका कश्मीर के भविष्य के घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा. कश्मीर अमेरिका की कम्युनिस्ट विरोधी रणनीति के लिहाज़ से महत्वपूर्ण क्षेत्र था. कश्मीर सोवियत संघ और चीन के बीच स्थित था. अमेरिका कश्मीर विवाद को हवा देता रहा, ताकि पाकिस्तान के ज़रिए उसे वहां अपनी पैठ बनाने का मौक़ा मिल सके. इधर भारत में सांप्रदायिक तत्व सक्रिय हो गए और कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय की मांग करने लगे. भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस मांग को जोर–शोर से उठाना शुरू कर दिया. महात्मा गांधी की हत्या से भारतीय गणतंत्र के धर्म निरपेक्ष मूल्यों के प्रति शेख अब्दुल्ला की आस्था को गहरा आघात पहुंचा. शेख अब्दुल्ला को भारत की धर्म निरपेक्षता, गांधी एवं नेहरू पर गहरा भरोसा था. गांधी जी की हत्या के बाद कश्मीर का भारत में ज़बरदस्ती विलय कराने के लिए सांप्रदायिक ताक़तों का दबाव बहुत बढ़ गया. इससे भी शेख अब्दुल्ला बहुत व्यथित हो गए. उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का निर्णय ग़लत तो नहीं था. उस समय नेहरू लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि कश्मीरियों का दिल जीतना सबसे महत्वपूर्ण है.

इसके विपरीत छद्म राष्ट्रवादी अनवरत कश्मीर का भारत में बलपूर्वक विलय कराने का राग अलाप रहे थे. सांप्रदायिक तत्वों के बढ़ते शोर से पहले से ही परेशान पंडित नेहरू पर तब दबाव और बढ़ गया, जब शेख अब्दुल्ला ने अमेरिकी राजदूत और चीन से वार्ताएं शुरू कर दीं. नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ़्तार कर जेल में डलवा दिया और यहीं से कश्मीरियों के अलगाव की प्रक्रिया शुरू हुई. इसके बाद अमेरिका के सहयोग एवं समर्थन से पाकिस्तान ने कश्मीरियों के असंतुष्ट वर्ग को हर तरह की मदद मुहैय्या करानी शुरू कर दी. 1980 के दशक में अलक़ायदा के उभरने के साथ ही समस्या और विकट हो गई. अमेरिका द्वारा स्थापित मदरसों में प्रशिक्षित अलक़ायदा के लड़ाकों ने काफिर और जिहाद जैसे शब्दों के अर्थ को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया. इससे कश्मीर समस्या का सांप्रदायिकीकरण हो गया. कश्मीर में इस्लाम के नाम पर राजनीति की जाने लगी. बची–खुची कसर भारतीय सेना ने पूरी कर दी. अतिवादियों को कुचलने घाटी में पहुंची सेना ने कश्मीरियों के रोजमर्रा के जीवन में बेजा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया. निर्दोष मारे जाने लगे. देश की रक्षा के नाम पर सेना क्रूरता करने लगी. सेनाओं की यह सोच होती है कि बंदूक़ ही सत्ता का एकमात्र स्रोत है. जब कोई सेना नागरिक इलाक़े में लंबे समय तक रहती है, तब यह सोच मुसीबत का सबब बन जाती है. सेना की मौजूदगी मात्र से आमजनों में अलगाव का भाव पनपता है. सेना की मनमानी का शिकार अक्सर निर्दोष होते हैं. महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा दुःख भोगते हैं. कश्मीर में सेना द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और उसकी लगातार मौजूदगी के कारण सामान्य जीवन के पटरी से उतर जाने से आमजन इतने कुंठित हो गए हैं कि वे अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए पत्थर फेंक रहे हैं.

कश्मीर की समस्या जटिल है, जिसका कोई आसान हल दिखाई नहीं देता. इसका एक कारण यह है कि इस मामले से कई पक्षों के हित जुड़े हुए हैं. इनमें शामिल हैं अमेरिका समर्थित पाकिस्तानी सेना, कश्मीर की आम जनता, वहां के अतिवादी, भारतीय सेना, भारत सरकार एवं कश्मीर के राजनीतिक दल और नेता. कश्मीरियों ने अतिवादियों और सेना, दोनों के घोर अत्याचार सहे हैं. उनके दुःख और व्यथा को समझना ज़रूरी है. संवाद तो आवश्यक है ही, सेना की उपस्थिति भी कम की जानी चाहिए. प्रजातंत्र की जड़ें गहरी की जाएं और कश्मीर के लोगों की मनःस्थिति को सहानुभूति पूर्वक समझा जाना चाहिए. भगवा लबादा ओढ़े राजनेताओं के आक्रामक रवैये से कश्मीरियों के घावों पर नमक छिड़कने के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा. इससे समस्या और बढ़ेगी. कश्मीर में हर स्तर पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए और असंतुष्टों की आवाज़ को ध्यान पूर्वक सुना जाना चाहिए. उनका अपमान या विरोध करने से काम नहीं चलेगा, इससे कश्मीरियों के कष्ट ही बढ़ेंगे.

राम पुनियानी
feedback@chauthiduniya.com

नए शब्द डोमेन लेते समय संबंधित व्यक्ति के दिमाग़ में नहीं आते, मगर जब तक आते हैं, लोग उसे अपने-अपने हिसाब से पढ़कर अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं.

निर्माण कार्यों का निरीक्षण आपका अधिकार है

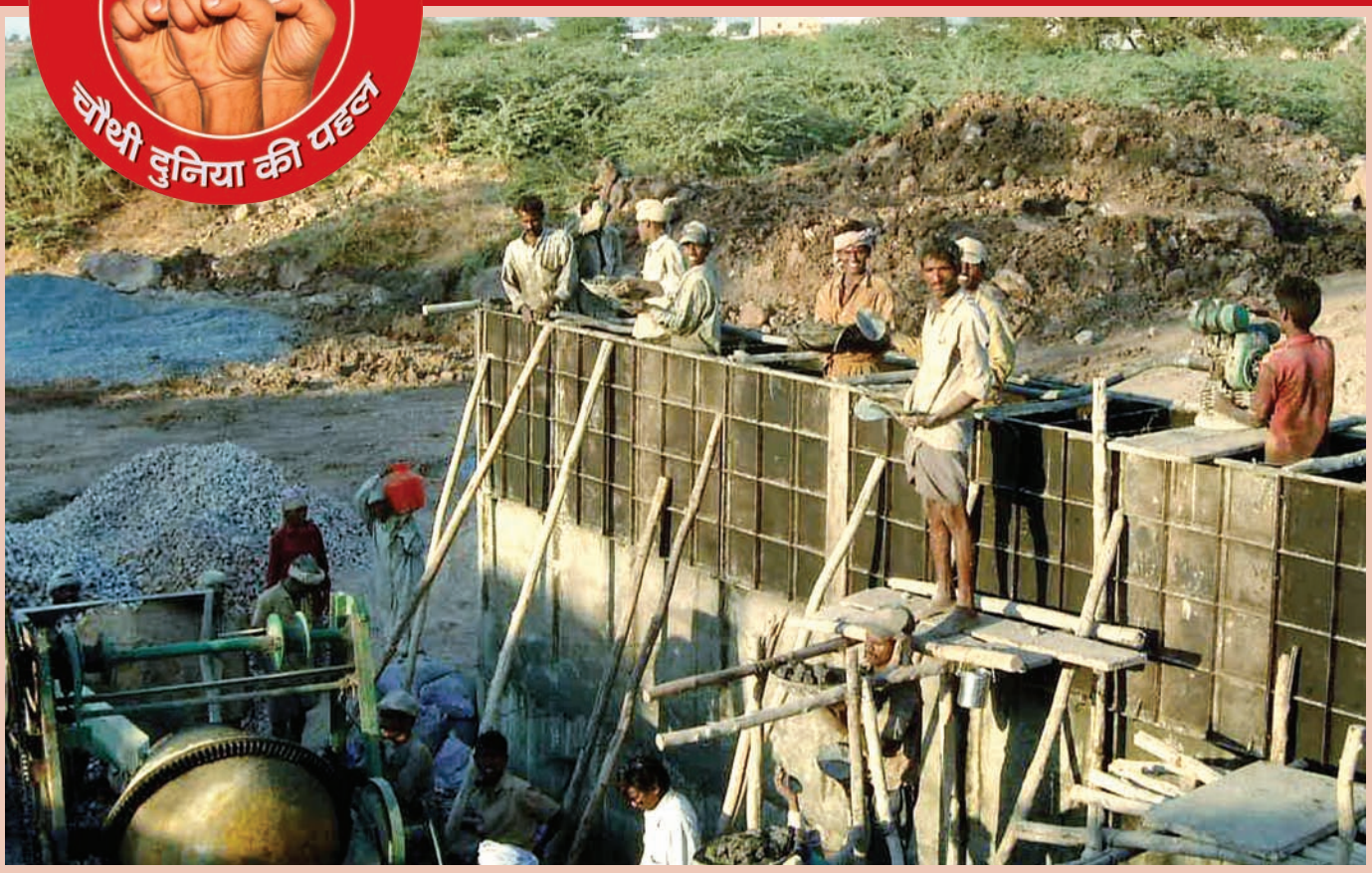

कई बार आपको मांगी गई सूचना के बदले ग़ैर ज़रूरी सूचना थमा दी जाती है या फिर आपके मोहल्ले या शहर की सड़क बनने के एक महीने के भीतर ही टूट जाती है. फिर सालों तक उसकी मरम्मत नहीं होती. आख़िर सरकार ने तो पूरा पैसा दिया था, तब इतनी घटिया सड़क क्यों बनी? सड़कें निर्धारित मापदंड के अनुसार क्यों नहीं बनीं? सड़कों की चौड़ाई निर्धारित सीमा से कम क्यों हो जाती है? मस्टर रोल में भी फर्जी इंट्री की शिक़ायतें आम हैं. सड़क बनाने के काम पर अक्षम और गांव में न रहने वाले लोगों की एंट्री भी मस्टर रोल में दिखा दी जाती है. आख़िर इस सबका उपाय क्या है? सूचना क़ानून में ऐसी समस्याओं का समाधान है. इसके तहत कई प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है. निरीक्षण का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी विभाग की फाइलों या किसी भी विभाग द्वारा कराए गए कामों का निरीक्षण कर सकते हैं. उदाहरण के लिए आपके क्षेत्र में यदि कोई सड़क बनाई गई है और आप सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री या सड़क की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं तो आप निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं. आप सरकारी फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं. कई बार जब आप किसी सरकारी विभाग से सूचना मांगते हैं तो आपसे कहा जाता है कि अमुक सूचना हज़ार पृष्ठों की है और इसके लिए आपको एक खास शुल्क अदा करनी होगी. कुछ मामलों में तो आवेदक से लाखों रुपये तक की मांग की गई है. ज़ाहिर है, एक ज़िम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते आप यह ज़रूर जानना चाहते होंगे कि इन स्थितियों का मुक़ाबला कैसे किया जाए? आरटीआई एक्ट की धारा 2(जे)(1) के तहत आप किसी भी सरकारी काम या फाइल के निरीक्षण की मांग कर सकते हैं. इस अंक में हम इसी से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी समस्या के समाधान या सुझाव के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301

ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

कार्यों का निरीक्षण

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

कृपया मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी दी जाए:

1. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-2(जे)(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार है. इसके तहत मैं निम्नलिखित कार्य का निरीक्षण करना चाहता हूं. कृपया मुझे तिथि, समय एवं स्थान बताएं, जबकि मैं आकर इस कार्य की जांच कर सकूं. (कार्य का विवरण)
2. मैं निरीक्षण के दौरान इस कार्य से संबंधित दस्तावेजों का भी निरीक्षण करना चाहूंगा, इसलिए निरीक्षण के समय निम्नलिखित दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराएं:
   क. मेज़रमेंट बुक
   ख. खर्चों का विवरण
   ग. रेखाचित्र
   इन दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद यदि मुझे किसी दस्तावेज की प्रति की आवश्यकता होगी तो कानून के तहत निर्धारित शुल्क लेकर प्रतियां उपलब्ध कराएं.
3. धारा-2(जे)(3) के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को सरकारी कार्यों में प्रयोग की गई सामग्री का प्रमाणित नमूना लेने का अधिकार है. इसके तहत मैं उपरोक्त कार्य में प्रयोग की गई सामग्री का विभाग द्वारा प्रमाणित नमूना लेना चाहता हूं. नमूना मेरी उपस्थिति में विभाग द्वारा एकत्र किया जाए और सीलबंद हो तथा विभाग द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि सीलबंद नमूना कार्य की सामग्री का असली नमूना है. कृपया मुझे स्थान, समय एवं तिथि सूचित करें, जबकि मैं प्रमाणित नमूने के लिए आ सकूं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

ज़रा हट के

इंसानों की बलि

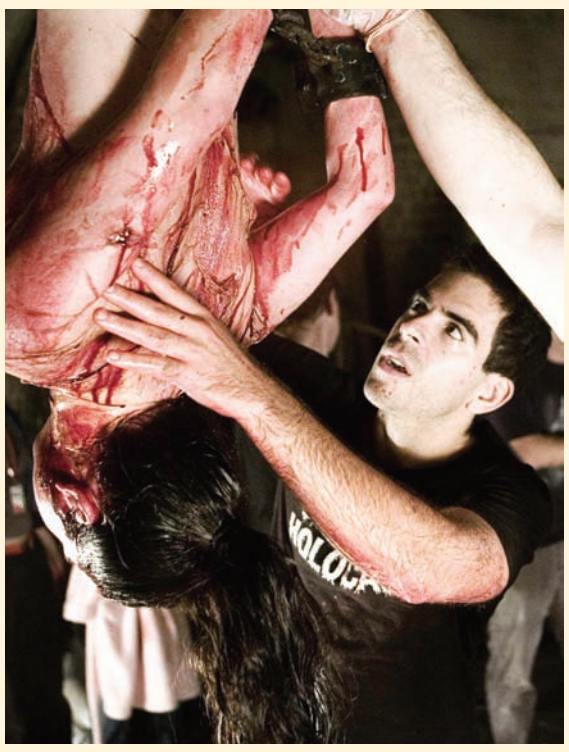

अभी तक आपने जानवरों की बलि से जुड़ी कई घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन पेरू के पुरातत्वविदों की मानें तो एक ऐसी जगह भी है, जहां छठवीं शताब्दी में इंसानों की बलि दी जाती थी. इस जगह का नाम लैम्बेक है. यह पेरू के उत्तरी भाग में स्थित है. जानकारी के अनुसार, पुरातत्वविदों ने यहां एक 60 मीटर लंबा हॉल खोजा है, जिसकी दीवारें कई रंगों में रंगी हुई थीं. पुरातत्वविदों के अनुसार, उस समय इस हॉल को काफी ख़ूबसूरती से सजाया जाता रहा होगा. पुरातत्वविदों की टीम का नेतृत्व करने वाले कार्लोस वेस्टर ला टोरे का कहना है कि इस हॉल का निर्माण मोचे लोगों ने किया था. ग़ौरतलब है कि मोचे लोगों की सभ्यता एक कृषि आधारित विकसित सभ्यता थी, जो वर्ष 100 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईस्वी के बीच पनपी थी. इसका अस्तित्व पेरू के इंका साम्राज्य के पहले था. पुरात्वविदों का मानना है कि यहां युद्ध बंदियों की बलि चढ़ाई जाती थी. इस जगह की तस्वीर में फर्श पर कम से कम छह मानव कंकाल दिखाई पड़ते हैं. वेस्टर के अनुसार, समारोह के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इस हॉल में मौजूद चीजों से मोचे समुदाय के अभिजात्य लोगों की उपस्थिति और मानव बलि के प्रमाण मिलते हैं. ग़ौरतलब है कि पिछले 25 सालों में पुरातत्वविदों को पेरू में मोचे समुदाय के समृद्ध लोगों एवं शासकों की ढेरों क़ब्रें और कलाकृतियां मिली हैं.

उफ़...यह क्या है?

शेक्सपियर ने भले कहा हो कि नाम में क्या रखा है, मगर सच तो यह है उन्होंने अपने इसी फ्रेज से ख़ूब नाम कमाया. वेब की दुनिया में अपनी पसंद का यूआरएल पाने के लिए लोग लाखों-करोड़ों तक ख़र्च करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब आपकी पसंद का यही यूआरएल अर्थ का अनर्थ करने लगे तो...? इसका अनुभव आप भी कर सकते हैं. बस आपको इंटरनेट पर कुछ टाइप करना है, फिर देखिए वह-वह निकल कर सामने आएगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी. एक साइट का उदाहरण लेते हैं. यहां प्रोग्रामर अपनी युक्तियों को सांझा करते हैं. साइट का नाम वैसे तो विशेषज्ञों द्वारा लेना-देना या सांझा करना यानी Experts Exchange.com है, मगर जब कोई इस यूआरएल को www.expertsexchange.com पढ़ता है तो उसे चक्कर आ जाता है, क्योंकि अब इसका मतलब Expert sex change यानी लिंग परिवर्तन विशेषज्ञ हो जाता है. इसी तरह उपचार विधियों की डायरेक्ट्री therapist finder (उपचार विधि खोजक) की वेबसाइट www.therapistfinder.com को अगर कोई बलात्कारी खोजने वाली साइट www. the rapist finder.com मान ले तो उसका क्या दोष?

अब तक तो आप समझ गए होंगे कि क्या माजरा है और सोच रहे होंगे कि आख़िर ऐसा होता कैसे है? असल में इन वेबसाइटों के नाम के शब्दों को अलग-अलग करके नहीं लिखा जा सकता. जब दो-तीन शब्द एक साथ लिखने होते हैं, तब उन्हें नए शब्दों में काटकर पढ़े जाने की संभावना बन जाती है. ये नए शब्द डोमेन लेते समय संबंधित व्यक्ति के दिमाग़ में नहीं आते, मगर जब तक आते हैं, लोग उसे अपने-अपने हिसाब से पढ़कर अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं. हालांकि इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ़ दिमाग़ी उलट-पुलट भर है, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि कभी-कभी इनके अर्थ इतने अश्लील हो जाते हैं कि वेबसाइट वालों की भद्द पिट जाती है. अब आप सोच रहे होंगे कि इस

समस्या का समाधान क्या है. आपको बता दें कि कुछ लोग तो अपना यूआरएल बंद कर देते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी वेबसाइट का नाम बदल देते हैं, जैसे www.molestationnursery.com को बदल कर molerivernursery कर दिया गया. हाल में प्रकाशित एक किताब Slurls में ऐसे ही लगभग 150 वेब पतों का विवरण है. अगर आपको भी इस तरह का प्रयोग करना है तो शिप island के वेब पते www.penisland.com को पढ़कर देखें और बताएं कि इसके और क्या-क्या मायने हैं? लेकिन, ज़रा संभल कर...

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 29 नवंबर-05 दिसंबर 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. क्रोध आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होगा और रिश्तों में दूरियों का कारण भी बन सकता है. संतान की ओर से तनाव मिलने की आशंका है. ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
बड़ों की सलाह से भविष्य की योजनाओं पर क़दम बढ़ाएं, आपकी राह आसान होगी. गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी. रुके हुए कार्य संपन्न होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. दांपत्य जीवन सुखमय होगा. प्रणय संबंध मधुर होंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
आर्थिक प्रगति होगी. अपनों का सहयोग मिलेगा. बच्चों पर ज़्यादा अंकुश उन्हें विरोधी बना सकता है. युवाओं का ध्यान घूमने-फिरने में रहेगा. खानपान में संयम रखें. उदर विकार या त्वचा संबंधी रोग की आशंका है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार मिलने की संभावना है. व्यर्थ के वाद- विवाद में न पड़ें. नौकरी के लिए दिए गए साक्षात्कार में सफलता के योग हैं. अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ सकता है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
क़रीबी रिश्तों में टकराव टालने की कोशिश सफल रहेगी. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी. संतान के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेंगे. अधीनस्थ कर्मचारी से विवाद हो सकता है. धन, पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
कोई महत्वपूर्ण योजना शुरू होने से आप प्रसन्न होंगे. यात्रा-देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद रहेगी. नए अनुबंध प्राप्त होंगे. किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. शाही ख़र्चों पर नियंत्रण हितकर होगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
कोई झूठ बोलकर आपको नुक़सान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है. नए संपर्क भाग्योदय में सहायक होंगे. व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी. वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. स्वास्थ्य शिथिल रहेगा.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
कामकाज को लेकर परेशान रहेंगे. सोच में बदलाव लाने से कई मुश्किलें आसान होंगी. धार्मिक कार्यों में प्रगति होगी. मन किसी अज्ञात आशंका से ग्रसित रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा. वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
भाग्यवश कुछ ऐसा होगा, जिसका आपको लाभ मिलेगा. शिक्षा के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. नवीन योजनाएं सफल होंगी. व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी. सामाजिक जीवन में मान बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में विशेष पहचान बनेगी.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
कार्य की अधिकता से स्वास्थ्य शिथिल रहेगा. रुका हुआ कार्य संपन्न होगा. स्वभाव में नरमी लाने से रिश्ते मज़बूत होंगे. विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह से लिए गए निर्णय स्थायित्व देंगे. आय के नए स्रोत बनेंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें. आर्थिक एवं व्यवसायिक वृद्धि होगी. विरोधी परास्त होंगे. मन ही मन किसी बात को लेकर घबराहट बनी रहेगी. दूसरों की बातों में आए तो क़रीबी रिश्तों में दरार आ सकती है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
पुराने मामलों को प्राथमिकता से सुलझाने का प्रयास करें, सुकून मिलेगा. अपनी रुचि को पूरा करने का अवसर पाकर आप ख़ुश होंगे. अपनी योजना पर आगे बढ़ें, धीरे-धीरे सभी का सहयोग मिल जाएगा.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

मध्य प्रदेश के एक शहर में ओबामा की यात्रा के विरोध में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निकाले गए एक जुलूस का नारा था-राष्ट्रपति नहीं, सौदागर है.

ओबामा का भारत प्रेम सिर्फ़ एक दिखावा है

अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है, दोज़ हू डू नाट लर्न फ्राम हिस्ट्री ऑर कंडेम्ड टू रिपीट इट (जो इतिहास से सबक नहीं सीखते, वे उसे दोहराने के लिए शापित होते हैं). अन्य कहावतों की तरह यह कहावत भी मानव के पीढ़ियों के संचित ज्ञान एवं अनुभव का निचोड़ है और इसमें छिपे सच को हम भारतीयों को भूलना नहीं चाहिए. संदर्भ है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की हालिया भारत यात्रा (6–9 नवंबर 2010). ओबामा के स्वागत में हमने शाब्दिक और लाक्षणिक–दोनों अर्थों में लाल कालीन बिछाया. प्रोटोकॉल को दरकिनार कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सपत्नीक एयरफोर्स वन की सीढ़ियों के नीचे खड़े रहे. ओबामा दंपत्ति हमारे देश में चार दिनों तक रहे और उन्होंने बार–बार हमें इस बात की याद दिलाई कि राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी सबसे लंबी विदेश यात्रा है. उन्होंने यह भी बार–बार दोहराया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वह पहले विदेशी मेहमान थे, जिनका उन्होंने व्हाइट हाउस में स्वागत किया था. ओबामा दंपत्ति भारत में नाचे–गाए, उन्होंने हमारी पीठ दर्जनों बार थपथपाई, हमें एक महान प्रजातंत्र निरूपित किया. हमें उन्होंने विश्व की उभरती, बल्कि उभर चुकी शक्ति बताया और यह वादा भी किया कि वह सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दिलवाने में मदद करेंगे.

मध्य प्रदेश के एक शहर में ओबामा की यात्रा के विरोध में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निकाले गए एक जुलूस का नारा था–राष्ट्रपति नहीं, सौदागर है. यद्यपि यह नारा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, परंतु यह भी सच है कि ओबामा भारत से विमानों की ख़रीद के लंबे–चौड़े ऑर्डर ले गए हैं, जिनसे अमेरिका में बाइस हज़ार नौकरियों का सृजन होगा. ओबामा दंपत्ति की यात्रा से हम अभिभूत हैं. नितांत निजी क्षणों को छोड़कर उनकी लगभग सारी गतिविधियों का हमारे टीवी चैनलों ने अनवरत प्रसारण किया, परंतु उत्साह और प्रसन्नता के इस अतिरेक में हमें इतिहास को नहीं भूलना चाहिए. हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस भाषा में ओबामा बोले, यदि उसी भाषा में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बोले होते तो भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति कुछ और ही होती. हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के साथ वैसा ही व्यवहार किया, जैसा कोई मां अपने बिगड़ैल, परंतु लाडले पुत्र के साथ करती है. 1947 के बाद से अमेरिका ने क़दम–क़दम पर भारत को कमज़ोर करने का प्रयास किया. हमने आज़ाद होते ही देश में संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया. आज अमेरिकी नेता यह कहते नहीं थकते कि अमेरिका और भारत दोनों दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, परंतु अमेरिका ने हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने में रत्ती भर भी सहायता नहीं की. इसके ठीक विपरीत उसने पाकिस्तान पर एक के बाद एक तानाशाहों को लादा.

अमेरिका वर्षों से एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रहा है. हम इस बात के कायल हैं कि अमेरिका में विभिन्न धर्मावलंबियों को सुरक्षा एवं बराबरी के समान अवसर प्राप्त हैं. हमने भी स्वयं को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया. इसके बावजूद अमेरिका ने हमसे सहयोग नहीं किया. उल्टे उसने धर्म आधारित देश होने के बावजूद पाकिस्तान को भरपूर मदद दी. पाकिस्तान के तानाशाहों ने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस्लाम का सहारा लिया. न सिर्फ़ पाकिस्तान, वरन् दुनिया के अनेक इस्लामिक राष्ट्रों के तानाशाहों एवं बादशाहों को अमेरिका ने बैसाखी प्रदान की. अनेक मामलों में यह स्थिति आज भी बनी हुई है. आज परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में अमेरिका बढ़–चढ़कर हमसे सहयोग करने के लिए तत्पर है, परंतु हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग की तकनीक प्राप्त करने के लिए हमारे देश के महान परमाणु वैज्ञानिक अमेरिका गए थे तो वह वहां से लगभग अपमानित होकर लौटे थे. डॉ. होमी जहांगीर भाभा से अमेरिका ने कहा था कि आप खेती करें और परमाणु शक्ति के विकास का काम हम पर छोड़ दें. हमें नहीं भूलना चाहिए कि न सिर्फ़ परमाणु शक्ति, वरन् उद्योग के किसी भी क्षेत्र में अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की. स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर में तो एक भी पूंजीवादी देश ने औद्योगिक विकास में हमारी कोई मदद नहीं की. पश्चिमी देशों ने तब हमें मदद देना शुरू किया, जब सोवियत संघ ने भिलाई में इस्पात कारखाने की स्थापना में हमें सहयोग दिया. आज भी हमारे देश में एक भी ऐसा बड़ा उद्योग नहीं है, जिसकी स्थापना अमेरिकी सहयोग से हुई हो.

अमेरिका ने विकास के क्षेत्र में हमारी सहायता तो नहीं की, बल्कि जब भी हम पर मुसीबत आई, हमारी टांग ही खींची. सबसे पहले कश्मीर का मसला लें. पाकिस्तान ने 1947 में कश्मीर पर हमला किया. हमने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया. अनेक अवसरों पर कश्मीर मामले पर सुरक्षा परिषद में लंबी बहसें चलीं. एक बार तो इसी तरह की लंबी बहस में भाग लेते हुए भारतीय पक्ष के नेता कृष्ण मेनन बेहोश हो गए थे. सुरक्षा परिषद ने अनेक बार बहुमत से भारत के पक्ष का समर्थन किया, परंतु अमेरिका ने अपने वीटो का प्रयोग कर संबंधित प्रस्ताव के अमल पर रोक लगा दी. सुरक्षा परिषद ने बार–बार पाकिस्तान से कश्मीर के उस इलाक़े को खाली करने के लिए कहा, जिस पर उसने बलात् कब्जा कर लिया था, परंतु अमेरिका ने इस मामले में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया. 1962 में चीन से युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने हमें ब्लैकमेल करने का प्रयास किया. युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन की एक उच्चस्तरीय टीम भारत आई थी, जिसने यह प्रस्ताव रखा था कि यदि हम कश्मीर समस्या का हल पाकिस्तान की मर्जी के अनुसार करने पर सहमत हो जाएं तो वे चीन के विरुद्ध हमारी मदद कर सकते हैं. हमने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया. 1965 में पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया. हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस आक्रमण में पाकिस्तान ने जिन हथियारों का उपयोग किया, वे उसे अमेरिका द्वारा ही दिए गए थे. यह वास्तविकता है कि यदि उस समय पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन नहीं होता तो उसने भारत के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत न की होती. उस समय सोवियत संघ समेत लगभग सभी समाजवादी देशों ने हमारी मदद की.

1971 में बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक बार फिर युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया. उस समय पाकिस्तान में हुए चुनाव में पूर्वी बंगाल (पूर्वी पाकिस्तान) के नेता मुजीबुर्रहमान और उनकी पार्टी अवामी लीग की जीत हो गई. इसके बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने शेख मुजीबुर्रहमान को सरकार नहीं बनाने दी. उस समय अमेरिका को शेख मुजीबुर्रहमान की मदद करनी थी, परंतु उसने फिर तानाशाहों की मदद की. पूर्वी बंगाल की जनता पर पाकिस्तान के शासकों ने तरह–तरह के जुल्म किए. पाकिस्तान के अत्याचारों से पीड़ित हज़ारों बांग्लादेशियों ने भारत में शरण ली. इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के निर्माण का बीड़ा उठाया. इससे अमेरिका इतना बौखलाया कि उसने अपने एक विशाल जहाजी बेड़े, जिसे सेवन्थ लीट कहा जाता है, को भारत पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया. सोवियत संघ ने तत्काल अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी प्रकार का सैन्य हस्तक्षेप करने के विरुद्ध सख्त चेतावनी दी. चेतावनी का असर हुआ और अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा वापस बुला लिया. बांग्लादेश के निर्माण के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान के तानाशाहों की मदद जारी रखी. आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही हमने यह फ़ैसला कर लिया था कि हमारी विदेश नीति गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित होगी. अमेरिका को हमारी यह नीति पसंद नहीं आई और उसने घोषणा कर दी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को वह अपने विरुद्ध मानता है. अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री ने कहा कि जो हमारे साथ नहीं है, वह हमारा शत्रु है. ओबामा यह सलाह देकर गए हैं कि हम ऐसे देशों की जनता की मदद करें, जहां तानाशाही या राजशाही है, परंतु वह भूल गए कि आज भी अमेरिका की छत्रछाया में अनेक देशों के तानाशाह और राजशाह पल रहे हैं. सऊदी अरब इसका जीता जागता उदाहरण है. 1984 में गैस त्रासदी के रूप में एक गंभीर मुसीबत हम पर आई. जापान को छोड़कर इस तरह की मुसीबत किसी अन्य राष्ट्र ने नहीं झेली. दिलचस्प बात यह है कि जापान पर आई मुसीबत के लिए भी अमेरिका ही ज़िम्मेदार था. गैस त्रासदी के दरम्यान अमेरिका ने हमारी कोई मदद नहीं की और आज भी करने के लिए तैयार नहीं है. गैस त्रासदी मामले का मुख्य अभियुक्त वारेन एंडरसन अमेरिका में मजे से रह रहा है. भारत की यात्रा के दौरान ओबामा ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा और बड़े दु:ख की बात है कि हमारी सरकार की तरफ़ से भी यह मुद्दा नहीं उठाया गया.

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चाहे हमने ओबामा की यात्रा को सुखद एवं सुरक्षित बनाने के लिए मुंबई की जनता को पानी तक के लिए तरसा दिया हो, परंतु जब हमारे देश के जॉर्ज फर्नांडीस जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और शाहरुख़ ख़ान जैसे जाने–माने कलाकार अमेरिका जाते हैं तो उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है. ऐसा कहा जाता है कि एक बार अमेरिकी हवाई अड्डे पर जॉर्ज फर्नांडीस को लगभग नग्न कर उनकी तलाशी ली गई थी. ओबामा की यात्रा की सफलता की ख़ुशी में हमें पिछले साठ सालों के इन कटु अनुभवों को भुलाना नहीं चाहिए, वरना जैसा कि कहावत कहती है, हम इतिहास को दोहराने के लिए शापित होंगे.

एल एस हरदेनिया
feedback@chauthiduniya.com

सभी फोटो–सुनील मल्होत्रा

अमेरिका वर्षों से एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रहा है. हम इस बात के कायल हैं कि अमेरिका में विभिन्न धर्मावलंबियों को सुरक्षा एवं बराबरी के समान अवसर प्राप्त हैं. हमने भी स्वयं को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया. इसके बावजूद अमेरिका ने हमसे सहयोग नहीं किया. उल्टे उसने धर्म आधारित देश होने के बावजूद पाकिस्तान को भरपूर मदद दी.

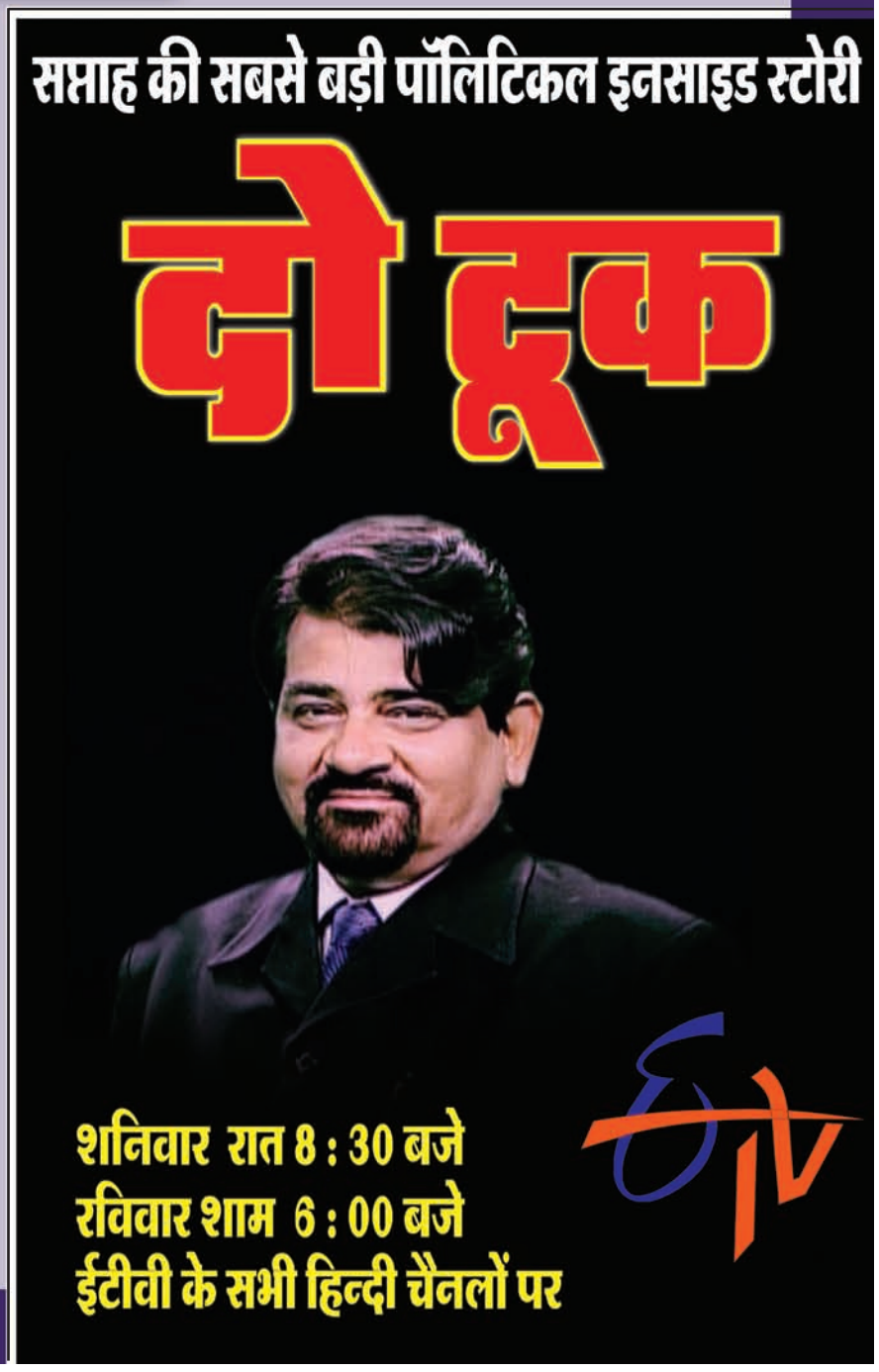

बाबा की ग़ैर मौजूदगी में मस्जिद की सफ़ाई करते समय एक भक्त से वह ईंट गिरकर टूट गई.

आश्चर्यजनक दर्शन

एक दिन रात्रि में शोभा के पति को एक विचित्र स्वप्न आया. उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर कारावास में डाल दिया है. तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सीखचों के बाहर उसके समीप खड़े हैं. उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आपकी कीर्ति सुनकर मैं आपके श्रीचरणों में आया हूं. फिर आपके इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपत्ति क्यों आई? तब बाबा बोले कि तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए. वह पुनः बोला कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं, जिसके कारण मुझे यह दुर्दिन देखना पड़ा. बाबा ने कहा, यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में ऐसा कुछ हुआ होगा. वह बोला, मुझे ऐसी कोई स्मृति नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लूं कि कोई बुरा कर्म हो गया होगा तो आपके यहां होते हुए उसे भस्म हो जाना चाहिए, जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है. बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है. उसने कहा, हां.

बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और जब उसने आंखें बंद कीं तो उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज़ सुनाई दी. आंखें खोलने पर उसने ख़ुद को कारावास से मुक्त पाया. पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा था और उसके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा था. वह अत्यंत भयभीत होकर बाबा की ओर देखने लगा. तब बाबा बोले कि बच्चू, अब तुम्हारी अच्छी तरह ख़बर ली जाएगी. पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ़्तार कर लेंगे. तब वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा, आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है. मुझे तो एकमात्र आपका ही सहारा है. भगवन, मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए. तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा. आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर सीखचों के बाहर खड़ा है और बाबा भी उसके समीप खड़े हैं. तब वह बाबा के श्रीचरणों पर गिर पड़ा. बाबा ने पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किसी प्रकार की भिन्नता है या नहीं. इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो. वह बोला कि जो अंतर आकाश और पाताल में है, वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है. मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है. पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं. बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं. प्रत्युत्तर में उसने कहा, जी नहीं. तब वह फिर पूछने लगे, क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं, क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काडबीबी नामक देवी है, जिसके सामने तुम विवाह एवं अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो. अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वह बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उसके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शनों की इच्छा हुई. बाबा के कहने पर ज्यों ही वह पीछे घूमा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं और जैसे ही वह उनके चरणों पर गिरने को तत्पर हुआ, वह तुरंत अदृश्य हो गए. तब वह बाबा से कहने लगा, आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं. क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने कहा कि तुम कहते हो कि मैं बूढ़ा हूं, थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़कर तो देखो! ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगा. दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी, उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद भी खुल गई. जागते ही वह गंभीरतापूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा. उसकी मानसिकता में परिवर्तन हो गया. अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी. उसकी लोभी एवं शंकालु वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी. वह था तो एक स्वप्न मात्र ही, परंतु उसमें जो प्रश्नोत्तर हुए थे, वे अधिक महत्वपूर्ण थे. दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के लिए एकत्रित हुए, तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग दो रुपये की मिठाई और दो रुपये नगद दिए. उसे कुछ दिन और रोककर उन्होंने आशीष देते हुए कहा कि अल्ला तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही करेगा. बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो नहीं हुई, परंतु उनकी कृपा अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत कल्याण हुआ. मार्ग में यथेष्ठ द्रव्य प्राप्त हुआ और यात्रा बहुत सफल रही. यात्रा में कोई कष्ट या असुविधा नहीं हुई और वे दोनों सकुशल अपने घर पहुंच गए. उन्हें बाबा के श्रीवचनों, आशीर्वाद और कृपा से प्राप्त आनंद की सदैव स्मृति बनी रही. इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप पधार कर उन्हें श्रेष्ठ मार्ग पर ले आते थे और आज भी ले आते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बाबा ने पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किसी प्रकार की भिन्नता है या नहीं. इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो.

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

द्वारिका माई और साई बाबा

चतुर्वर्णामपि वर्गाणां यत्र द्वाराणि सर्वतः
अतो द्वारावतीत्युक्ता विद्वद्भिस्तत्ववादिभिः

इसका भाव यह है कि जिस स्थान के द्वार चारों वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने के लिए सदा खुले रहते हों, विद्वान उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं. द्वारका माई के संदर्भ में यह व्याख्या पूरी तरह लागू होती है. साई बाबा ने यौगिक शक्ति से वहां अग्नि प्रज्जवलित की, जिसे निरंतर लकड़ियां डालते हुए आज तक सुरक्षित रखा गया है. भस्म को बाबा ने ऊदी नाम दिया और वह इसे अपने भक्तों को बांटते थे. ऊदी के सेवन से हज़ारों श्रद्धालु असाध्य रोगों से मुक्त हो चुके हैं. इस ऊदी में विशेष शक्ति आज भी है. भक्तजन बड़ी श्रद्धा से ऊदी को अपने मस्तक पर लगाते हैं और उसका सेवन करते हैं. इससे स्वास्थ्य और शांति की प्राप्ति होती है. द्वारका माई के समीप थोड़ी दूर पर वह चावड़ी है, जहां बाबा एक दिन छोड़कर विश्राम करते थे. साई नाथ के भक्त उन्हें शोभायात्रा के साथ चावड़ी लाते थे. उसकी स्मृति में प्रत्येक गुरुवार के दिन द्वारका माई से साई बाबा की पालकी चावड़ी जाती है. सन् 1886 ई. में मार्गशीर्ष की पूर्णिमा (दत्तात्रेय जयंती) के दिन बाबा ने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर त्रिदिवसीय समाधि ली थी. इससे पूर्व उन्होंने अपने भक्त म्हालसापति से कहा कि तुम मेरे शरीर की तीन दिनों तक रक्षा करना. मैं यदि वापस लौट आया तो ठीक, अन्यथा मेरी समाधि बना देना. ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग दस बजे ज़मीन पर लेट गए. उनका श्वांस लेना बंद हो गया. अनेक लोग वहां एकत्रित होकर बाबा के शरीर में पुनः प्राण आने की प्रतीक्षा करने लगे. तीन दिन बीत जाने पर रात के लगभग तीन बजे साई नाथ की देह में चेतना वापस लौट आई. सन् 1918 में विजयादशमी के दिन महासमाधि लेने से दो वर्ष पूर्व साई बाबा ने एक अद्भुत लीला करके अपने निर्वाण का संकेत दशहरे को सीमोल्लंघन करने (नगर की सीमा के बाहर जाने) की बात कहकर दे दिया था. साई नाथ के महाप्रयाण से पूर्व एक विशेष शकुन घटा. द्वारका माई मस्जिद में एक पुरानी ईंट हुआ करती थी, जिसे बाबाश्री अपनी जीवनसंगिनी की तरह सदा साथ रखते थे. वह रात में ईंट को सिर के नीचे रखकर सोते थे और दिन में उस पर हाथ टेककर बैठते थे. एक दिन बाबा की गैर मौजूदगी में मस्जिद की सफ़ाई करते समय एक भक्त से वह ईंट गिरकर टूट गई. यह जानकारी मिलते ही साई बाबा ने शरीर त्यागने की घोषणा कर दी. विक्रम संवत 1975 की विजयादशमी (15 अक्टूबर, 1918) को दोपहर 2.30 बजे साई बाबा ब्रह्मलीन हो गए. ऐसा कहा जाता है कि बायजाबाई, जिन्हें साई बाबा माई कहकर बुलाते थे, उन्हें दिए गए वचन के पालन में उनके पुत्र तात्या कोटे पाटिल की मृत्यु टालने के लिए साई नाथ ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया. शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी सेविका लक्ष्मीबाई शिंदे को नवधा भक्ति के प्रतीक के रूप में 9 सिक्के आशीर्वाद स्वरूप देते हुए कहा, मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, वहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बौद्धधर्म के हीनयन-महायान समुदायों के आपसी संघर्ष ने बद्रिकाश्रम को भी प्रभावित किया. आक्रमण एवं विनाश की आशंका के चलते असमर्थ-असहाय पुजारी भगवान श्री की मूर्ति नारद कुंड में डालकर इस धाम से पलायन कर गए.

विचारधारा का फासीवाद

अनंत विजय

चीन से एक दिल दहला देने वाली ख़बर आई है. क़ानून का ज़बरदस्ती और कड़ाई से पालन कराने की कई ख़बरें चीन से आती ही रहती हैं, लेकिन अभी जो ख़बर बाहर निकल कर आई है, वह एक विकसित राष्ट्र और शासन करने वाली पार्टी की विचारधारा पर कलंक की तरह है. चीन के पूर्वी तट के पास सीमिंग में एक छत्तीस वर्षीय महिला ने एक बच्चे के रहते दूसरी संतान को जन्म देने का इरादा किया और गर्भवती हो गई. जब उसका गर्भ आठ महीने का हो गया तो सरकारी अधिकारियों को इस बात का पता चला. यह जानकारी पाने के बाद तक़रीबन दो दर्जन चीनी अधिकारियों ने उस महिला के घर पर धावा बोल दिया. आठ माह की गर्भवती पर सरकारी अधिकारियों ने लात-घूंसों की बरसात कर दी. दोनों हाथ पीछे बांधकर उसके सिर को दीवार से टकराया और पेट पर कई प्रहार किए, ताकि गर्भपात हो जाए. जब वे कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने आईयिंग नामक उस महिला को घसीट कर अस्पताल में भर्ती कराया और गर्भपात का इंजेक्शन लगवा कर जबरन आठ माह का गर्भ गिरवा दिया. पेट में बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि गर्भपात के बावजूद उसके कुछ अंश पेट में रह गए, जिन्हें निकालने के लिए आईयिंग की मंजूरी के बग़ैर उसका ऑपरेशन भी करना पड़ा. एक ऐसा ऑपरेशन, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी. इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह घटना चीन में होने वाली अन्य ज़्यादतियों की तरह दबकर रह जाती, लेकिन उस महिला ने अस्पताल में अपने फोटो खींचने की इजाज़त दे दी. नतीजा यह हुआ कि उसी दास्तां और चोट के निशान वाले फोटोग्राफ इंटरनेट के ज़रिए सारी दुनिया के सामने आ गए.

दरअसल चीन ने बढ़ती जनसंख्या पर काबू करने के लिए एक संतान नीति लागू की है. वहां जुड़वां बच्चों के अपवाद को छोड़कर दूसरी संतान पैदा करने पर पूरी तरह से पाबंदी है. इस नीति का उल्लंघन करने वाले को भारी जुर्माना चुकाना पड़ता है. इस क़ानून की आड़ में ही क़ानून का पालन कराने के ज़िम्मेदार सरकारी अफसरों ने हैवानियत का नंगा नाच किया. चीन के उन सरकारी अधिकारियों को न तो उस महिला का दर्द समझ में आया, न ही उन्होंने उसके पति की भावनाओं को समझने की कोशिश की और न ही उन पर महिला की दस वर्षीय बेटी की गुहार का असर हुआ, जो पिछले आठ महीने से अपने घर में छोटे भाई-बहन की राह देख रही थी. जिस विचारधारा के आधार पर चीन का शासन चल रहा है, उसमें न तो भावनाओं की कद्र है और न संवेदना के लिए कोई जगह. वहां तो दबाई जाती है सिर्फ़ आवाज़. थ्येनमान चौक पर छात्रों को टैंक से कुचले जाने की घटना अब भी लोगों के जेहन में है. हाल में प्रकाशित एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक़, चीन में अब भी पांच लाख लोग बग़ैर किसी गंभीर आरोप के जेल की हवा खा रहे हैं. वहां बग़ैर किसी जुर्म के घर में कैद कर देना, लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी पर सरकारी निगरानी और आम आदमी की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस फोर्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आम बात है. चीन की जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता ली जियाबो को जब शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया तो वहां की सरकार की भौंहें तन गईं.

चीनी सरकार को लगा कि ली जियाबो को नोबल पुरस्कार मिलने से देश में मानवाधिकार

के लिए काम करने वाले लोगों की सक्रियता बढ़ सकती है, लिहाज़ा ली के नज़दीकी लोगों की निगरानी तेज कर दी गई. बग़ैर किसी शक या संदेह के हफ्ते भर में तक़रीबन चालीस लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया. ली के समर्थक संगठनों पर ज़बरदस्ती शुरू कर दी गई. ली जियाबो से नज़दीकी के शक में शंघाई के एक हाउस चर्च पर पहले निगरानी शुरू की गई, फिर कई दिनों तक पुलिस ने उसे अपने घेरे में ले लिया. चर्च के नेता झू योंग और उनकी पत्नी के घर से निकलने पर न केवल पाबंदी लगा दी गई, बल्कि घर का ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए उन्हें पुलिस के घेरे में निकलने पर मजबूर किया गया. जनता की सरकार और लोगों के बीच समानता के सिद्धांत की वकालत करने वाली इस विचारधारा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है. दरअसल ऐसा सिर्फ़ चीन में नहीं होता है, जहां भी इस विचारधारा का बोलबाला है, वहां ऐसा ही तानाशाही पूर्ण रवैया देखने को मिलता है.

हमारे देश में भी वामपंथी विचारधारा को मानने वाले हमेशा से तानाशाही और फासीवाद का विरोध करते रहे हैं. उनका यह विरोध सिर्फ़ दिखावे और अपने हित में उसका उपयोग करने के लिए होता है. चीन में हुई उस मार्मिक घटना के बारे में जानते ही जेहन में प्रख्यात कवि एवं शायर कैफी आजमी की बेगम शौकत कैफी की किताब, याद की रहगुजर का एक प्रसंग कौंध गया. कैफी के एक साल के लड़के खैयाम की असामयिक मौत हो गई थी, जिसने उन्हें और उनकी पत्नी शौकत को अंदर से तोड़कर रख दिया था. हर वक़्त, हर पल अपनी पहली संतान की मौत का गम झेल रहीं शौकत और उनके पति कैफी दोनों वामपंथी विचारधारा से जुड़े संगठन भारतीय जन नाट्य संघ यानी इप्टा में सक्रिय थे. जलसे, जुलूस एवं प्रदर्शन रोज के काम थे, लेकिन जब बेटे का गम लिए शौकत अपने साथी कॉमरेडों के पास जातीं तो वे कन्नी काट जाते थे. साथियों की संवेदनहीनता से शौकत को बेहद दु:ख पहुंचा. अपनी किताब में शौकत ने इस दर्द को बयां करते हुए लिखा, आहिस्ता-आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि लोग गमजदा लोगों से घबराने लगते हैं और चुपचाप उठकर चले जाते हैं. मैंने यह सोचकर अपने गम पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन पूरा मामला यहीं ख़त्म नहीं होता है. संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर पहुंचना अभी बाक़ी था.

कुछ दिनों बाद शौकत आजमी फिर से गर्भवती हुईं. अपने पहले बच्चे की मौत का गम भुलाने की कोशिश में लगीं शौकत के लिए यह सुकून देने वाला पल था. लेकिन अपना सब कुछ पार्टी पर न्योछावर करने के बावजूद उनकी पार्टी ने क्या हुक्म सुनाया, यह आप शौकत की ही जुबानी सुनिए, शबाना होने को थी. चूंकि मेरा पहला बच्चा गुजर गया था, इसलिए मैं तो बहुत ख़ुश थी, लेकिन पार्टी को यह बात पसंद नहीं आई. ऑर्डर हुआ कि एबॉर्शन करा दिया जाए, क्योंकि कैफी अंडरग्राउंड हैं, मैं बेरोज़गार हूं, बच्चे की ज़िम्मेदारी कौन लेगा. मुझे बेहद तकलीफ पहुंची. यह आपबीती है एक कॉमरेड की. यह एक ऐसी पार्टी की सच्चाई है, जो जनपक्षधरता और व्यक्तिगत आज़ादी का सबसे ज़्यादा शोर मचाती है, जो तानाशाही के ख़िलाफ़ होने का लगातार दंभ भरती है, लेकिन वक़्त पड़ने पर इस विचारधारा का पालन करने और कराने वाले लोग सबसे बड़े तानाशाह के तौर पर उभरते हैं. अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब पार्टी की बात न मानने पर सीपीएम ने अपने वरिष्ठ सदस्य सोमनाथ चटर्जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था. अगर सोमनाथ चटर्जी की मानें तो इस निष्कासन के पहले न तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और न ही पार्टी की नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च समिति पोलित ब्यूरो के सभी सत्रह सदस्यों की सहमति ली गई. सिर्फ़ पांच सदस्यों ने महासचिव के इशारे पर आनन-फानन में सोमनाथ चटर्जी जैसे पार्टी के कद्दावर नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया. अपनी किताब, कीपिंग द फेथ-मेमॉयर ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन में सोमनाथ चटर्जी ने यह दावा किया है कि उनका निष्कासन पार्टी के संविधान के ख़िलाफ़ और अलोकतांत्रिक था. पार्टी संविधान तो दूर की बात है, राजनीति में एक सामान्य परंपरा है कि नोटिस देने के बाद पार्टी से निष्कासन होता है, लेकिन सोमनाथ के मामले में सीपीएम ने इस सामान्य नियम का भी पालन नहीं किया. ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो उस विचारधारा से जुड़े लोगों, संगठन और सरकार के हैं, जो जनपक्षधरता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता, समान अधिकार एवं समान अवसर आदि के बारे में सबसे ज़्यादा दुहाई देते हैं. कथनी और करनी के इसी फ़र्क़ ने इस विचारधारा की बुनियाद पर टिकी कई शक्तिशाली व्यवस्थाओं से लोगों का मोहभंग कर दिया. नतीजा यह हुआ कि किसी जमाने में विश्व में एक वैकल्पिक विचारधारा के रूप में देखी जाने वाली यह व्यवस्था अब चीन और कुछ अन्य देशों में सरकार के सहारे अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

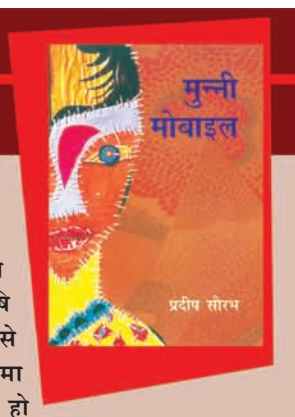

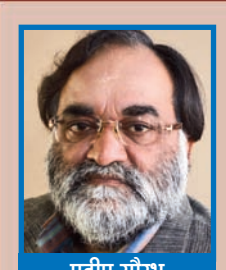

प्रदीप सौरभ

आनंद भारती नील को सुन रहे थे. उनके सामने दिल्ली की जमुना का चेहरा उभर आया. करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट बनने के बाद भी जमुना ज़हर की नदी बनी हुई है. नेता और नौकरशाह पैसा डकार चुके हैं. जमुना मैली की मैली. चुनाव के समय थोड़े वक़्त जमुना की चर्चा ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं है. बड़ी-बड़ी सभ्यताएं नदियों के रूठने से तबाह हो चुकी हैं, शहर के शहर बर्बाद हो चुके हैं, इस सबके बावजूद जमुना की मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है. जन भागीदारी भी नहीं हो रही है. शायद दिल्ली में अब दिल्ली वाले नहीं रहे हैं. यदि वे होते तो दिल्ली को बचाने के लिए जमुना को बचाते. बाहर से यहां आकर बसे लोगों का सरोकार जमुना से नहीं है. उन्हें तो अपना पेट भरने की सनक ही सवार रहती है. कमाई और कमाई. बस इतना ही सरोकार है उनका दिल्ली और जमुना से. पीने का पानी नहीं मिलेगा तो क्या! बाज़ार से ख़रीद लेंगे. लेकिन कितने समय तक. पानी बचेगा तब तक न. एक वक़्त ऐसा भी आ सकता है, जब इंसानों की अपनी करतूतों के चलते पानी पैसे देने पर भी नहीं मिलेगा. यह बात कही भी जा चुकी है कि अब जब कभी विश्व युद्ध होगा तो उसके मूल में पानी होगा.

आनंद भारती सोच रहे थे कि टेम्स की प्रदूषण मुक्ति की कार्ययोजना से दिल्ली की जमुना क्या, देश की अन्य प्रदूषित नदियां भी मुक्त हो सकती हैं. गंगा मैया तो भारतीयों के जीवन में बसती हैं. जन्म से लेकर मौत तक की साक्षी हैं, वह भारतीय समाज की. गंगा से मुक्ति का वरदान मांगने वाले उसे बचाने के लिए किसी भी भागीरथ प्रयास के लिए तैयार नहीं हैं. गंदगी बढ़ाने में इनकी भी भूमिका कम नहीं है.

नील पूरा प्रजेंटेशन दिखा और बता चुके थे. बारी थी इनवायरमेंट मिनिस्ट्री की. वहां टीम की मुलाक़ात क्लाइमेट साइंस के मुखिया क्रिस सिअर से होनी थी. बीते काफी समय से इंग्लैंड की सक्रियता ग्लोबल वार्मिंग को लेकर रही है. ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक तरह का आतंक है वहां. पूरे इंग्लैंड के किसी भी किनारे से दूसरे किनारे की पांच सौ किलोमीटर दूरी तय करने पर समुद्र आ जाता है. इंग्लैंड के वैज्ञानिकों की राय है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते यदि समुद्र की सतह एक इंच भी ऊपर आ जाए तो इंग्लैंड का बहुत सा भू-भाग डूब जाएगा. लंदन में भी टेम्स नदी का जलस्तर इतना बढ़ सकता है कि लंदन डूब जाए. इसकी वजह कार्बन उत्सर्जन को माना जाता है.

क्रिस सिअर टीम के साथ यही चर्चा कर रहे थे. इंडिया का संदर्भ आया. वह बताने लगे कि ग्लोबल वार्मिंग से भारत में पीने के पानी का संकट आ सकता है. मौसम में परिवर्तन आ सकता है, जिसके चलते कृषि प्रभावित हो सकती है. समुद्र की सतह ऊपर आने से गोवा और अंडमान निकोबार जैसे द्वीप पानी में समा सकते हैं. मलेरिया और दूसरी बीमारियों का विस्तार हो सकता है. प्रवचन की उस कड़ी में वह यह भी बताते हैं कि कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार है. इंडिया में उत्सर्जन की मात्रा मानक से अधिक है. इसके लिए उसे बेहतर प्रबंध करने होंगे.

उनका प्रवचन चल ही रहा था कि अनंत कृष्णनन ने क्रिस सिअर को रोकते हुए कहा, इंडिया तो कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको दी जाने वाली मदद उसे नहीं मिल रही है. क्वेटो संधि के तहत जो पैसे उसे मिलने थे, वह वायदा पूरा नहीं किया गया.

डेवलप कंट्री की साजिश लगती है, आनंद भारती अनंत कृष्णनन की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एनर्जी के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. इंडिया जैसे देशों के पास एनर्जी के नाम पर कोल ही है. उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश इंडिया के डेवलपमेंट को रोकने की साजिश है.

इंद्राणी मजूमदार भी पीछे कहां रहने वाली थीं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आप लोग इतने चिंतित हैं, लेकिन अमेरिका को समझाने की आप में कूव्वत नहीं है. दुनिया में कार्बन उत्सर्जन करने में अमेरिका नंबर वन है. वह ग्लोबल वार्मिंग की थ्योरी के जवाब में ग्लोबल कूलिंग की बात करता है.

अगले अंक में जारी...

बद्रीनाथ धाम : सृष्टि का आठवां बैकुंठ

राजकुमार शर्मा

ब्रह्मांड के पावनतम धामों में से एक है बद्रीनाथ धाम. कहा जाता है कि यह स्वयं भगवान विष्णु एवं नारद द्वारा सेवित है. इसी कारण सृष्टि में बद्रिकाश्रम को अष्टम बैकुंठ के रूप में मान्यता हासिल है.

पुराणों में चारों युगों में चार धामों की स्थापना का उल्लेख मिलता है. सतयुग का पावन धाम बद्रीनाथ, त्रेता का रामेश्वरम जिसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने की थी, द्वापर का द्वारिका एवं कलियुग का जगन्नाथ धाम. बद्रीनाथ धाम में सतयुग के प्रारंभ में जगत कल्याण की कामना से भगवान प्रत्यक्ष रूप से मूर्तिमान होकर यहां स्वयं तप करते थे. सतयुग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से यह पावन धाम मुक्तिप्रदा के नाम से विख्यात हुआ. त्रेता में इसे योगी सिद्धदा नाम से जाना गया. द्वापर में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की आशा में बहुजन संकुल होने के नाते विशाला के नाम से जाना गया. कलियुग में यह धाम बद्रिकाश्रम-बद्रीनाथ के नाम से विख्यात है.

बौद्धधर्म के हीनयन-महायान समुदायों के आपसी संघर्ष ने बद्रिकाश्रम को भी प्रभावित किया. आक्रमण एवं विनाश की आशंका के चलते असमर्थ-असहाय पुजारी भगवान श्री की मूर्ति नारद कुंड में डालकर इस धाम से पलायन कर गए. जब भगवान श्री की प्रतिमा के दर्शन नहीं हुए तो देव मानव भगवान शिव से कारण जानने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे. भगवान शिव ने बताया कि मूर्ति नारद कुंड में है, परंतु तुम लोग वर्तमान में शक्तिहीन हो, नारायण मेरे भी आराध्य हैं, अत: मैं स्वयं अवतार लेकर मूर्ति का

उद्धार करके जगत के कल्याणार्थ उसकी स्थापना करूंगा. कालांतर में भगवान आशुतोष शिव ही दक्षिण भारत के कालड़ीसीन में ब्राह्मण भैरव दत्त उर्फ शिव गुरु के घर जन्म लेकर जगतगुरु आदि शंकराचार्य के नाम से विश्वविख्यात हुए. शंकराचार्य द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष के अव्यवस्थित तीर्थों का सुदृढ़ीकरण, बौद्ध मत का खंडन और सनातन वैदिक मत का मंडन सर्वविदित है. शंकराचार्य ग्यारह वर्ष की अवस्था में बद्रिकाश्रम पहुंचे और उन्होंने नारद कुंड से भगवान श्री की दिव्य मूर्ति निकाल कर उसे पुन: स्थापित किया.

आज भी उसी परंपरा के अनुसार उन्हीं के वंशज भगवान बद्रीनाथ की पूजा-अर्चना करते हैं. मंदिर के कपाट अप्रैल के अंत अथवा मई के प्रथम पखवारे में खुलते हैं और नवंबर के दूसरे सप्ताह में बंद हो जाते हैं. भगवान श्री की शीतकालीन पूजा पाड्यकेश्वर मंदिर में होती है. बद्रीनाथ जी की दिव्य मूर्ति की प्रतिष्ठा का काल द्वापर युग माना जाता है. बद्रीनाथ जी की यह तीसरी प्रतिष्ठा है. भगवान श्री की दिव्य मूर्ति हरित वर्ण की पाषाण शिला में निर्मित है, जिसकी ऊंचाई लगभग डेढ़ फुट है. भगवान श्री पद्मासन में योग मुद्रा में विराजमान हैं. यहां भगवान श्री का दर्शन साधक को गांभीर्य प्रदान करता है, जिससे मन की चपलता स्वयं समाप्त हो जाती है. नाभि के ऊपर भगवान श्री के विशाल वक्षस्थल के बाएं भाग में भृगुलता और दाएं भाग में श्री वत्स चिन्ह स्पष्ट दिखते हैं. भृगुलता भगवान श्री की सहिष्णुता एवं क्षमाशीलता का प्रतीक है और श्रीवत्स भक्त वत्सलता का.

पुराण इसका स्वयं साक्षी है कि त्रिदेवों में महान कौन के परीक्षण के दौरान भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया तो क्षमादान के साथ भगवान ने अपने महान होने का परिचय दिया. श्रीवत्स चिन्ह बाणासुर की रक्षा हेतु भगवान शिव द्वारा फेंके गए त्रिशूल का घाव है. इससे ऊपर भगवान की दिव्य कंबुग्रीवा के दर्शन होते हैं, जो जीव मात्र को जन्म-मृत्यु के बंधन से मुक्त करते हैं. देवर्षि नारद भगवान बद्रीनाथ के बाएं भाग में ताम्र वर्ण की छोटी सी मूर्ति के रूप में स्थित हैं. नारद जी के पृष्ठ भाग में चांदी की दिव्य मूर्ति उद्धव जी की है.

द्वापर में भगवान नारायण के सखा उद्धव यहां पधारे थे. शीतकाल में देव पूजा के समय उद्धव जी की ही पूजा होती है. भगवान नारायण के बाएं स्कंध भाग में लीलादेवी, उर भाग में उर्वशी, मुखारविंद के पास श्रीदेवी और कटि भाग के पास भूदेवी विराजमान हैं. स्वयं भगवान नारायण योग मुद्रा में तपस्या में लीन हैं. गरुण जी भगवान बद्रीनाथ के दाएं भाग में हाथ जोड़े ध्यान मुद्रा में खड़े हैं. वह भगवान विष्णु के वाहन हैं. तीस हज़ार वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें नारायण दरबार में स्थान मिला था. यहीं कुबेर जी हैं, जो भगवान के कोषाध्यक्ष हैं और यक्षों के राजा भी.

feedback@chauthiduniya.com

स्कोडा भारत में 2012 में अपनी छोटी कार भी लांच करेगी, जिसकी क़ीमत 3-5 लाख रुपये के बीच होगी.

नई बाइक नया अंदाज़

वर्ष 2011 के स्मार्ट राइडर के लिए कावासाकी वलकैन 17000 वकीरो एक उपयुक्त बाइक है. भारतीय बाज़ार में स्टाइलिश स्पोर्ट्स बाइक्स की धूम को देखते हुए कावासाकी ने अपनी नई बाइक वलकैन वकीरो लांच की है. 1700 सीसी क्षमता वाले इंजन से लैस इस मोटरसाइकिल के छह स्पीड ट्रांसमिशन, फोर स्ट्रोक, फोर वाल्व पर सिलेंडर और लिक्विड कूल्ड इंजन जैसी ख़ूबियां इसे खास बनाती हैं. साथ ही इसमें फ्रंट ब्रेक डुअल 300 एमएम डिस्क, डुअल ट्विन पिस्टन कैलिपर्स, रीयर ब्रेक सिंगल 300 एमएम डिस्क एवं ट्विन पिस्टन कैलिपर्स का बेजोड़ संगम है. ये राइडर्स को परेशानी में अक्सर बचा लेते हैं. कावासाकी वलकैन 1700 वकीरो का वी ट्विन टॉर्क पर पड़ने वाले दबाव को बेहद कम कर बाइक चलाना आसान बना देता है. इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल लंबी यात्रा में भी एक स्पीड मेंटेन कर बाइक चलाना आरामदायक बनाता है. इस बाइक में खास ऑडियो सिस्टम है, जो एफएम, एएम के साथ डब्ल्यू एक्स रेडियो फ्रिक्वेंसी और आईपॉड, एक्स एम ट्यूनर और सीबी रेडियो को सपोर्ट करता है. 2,750 आरपीएम पर 108 फुट पाउंड का टॉर्क ड्राइव को स्मूथ बनाता है. इसका इग्नीशन टीसीबीआई के साथ डिजिटली एडवांस है. इस बाइक के ईंधन टैंक की क्षमता 21 लीटर है. इसके साथ मिलने वाली वारंटी तीन साल की है. यह स्पेशल बाइक इबॉनी और कैंडी फायर रेड कलर्स में उपलब्ध है. इन दोनों रंगों की बाइक में बॉडी पर ग्लॉसी पेंटवर्क के साथ अन्य ख़ूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है.

बोझ नहीं लगेगा लगेज

आपकी यात्रा अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए वीआईपी कंपनी ने लगेज उत्पादों की नई सीरीज़ लांच की है. अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली नामक यह नई सीरीज़ मज़बूती एवं सुविधा का बेजोड़ संगम है और ग्राहकों को ठोस लगेज जैसी सुरक्षा प्रदान करेगी. इसमें शॉर्ट लगेज ट्रॉली जैसी सुविधा भी हैं. कंपनी की इस अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली सीरीज़ को ओलंपिक पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज़ विजेंद्र सिंह ने लांच किया. उच्च गुणवत्ता वाले पॉली प्रोपलीन से बनी अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली सीरीज मज़बूत और टिकाऊ है. इसमें अलग से धातु से बनी एक ट्रॉली भी संलग्न है, जो इसकी उपयोगिता बढ़ाती है और इसका इस्तेमाल आसान बनाती है. इस स्ट्रॉली में लगे पहियों की वजह से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक होगा और आपकी यात्रा सुखदायी रहेगी. वर्तमान समय में बाज़ार में इस प्रकार का यह अकेला उत्पाद है, जो आकर्षक, सस्ता और अच्छे ब्रांड का है. अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली की क़ीमत 1400 रुपये से 1700 रुपये तक है. कंपनी अपनी इस सीरीज़ पर 7 साल की वारंटी भी दे रही है.

अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली जैसे अनूठे उत्पाद के लांच के अवसर पर वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग मनीष व्यास ने कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं के बीच अपना नया उत्पाद लांच करते समय कंपनी ने उनकी संतुष्टि का खास ध्यान रखा है. यही वजह है कि आधुनिक भारतीय यात्रियों की आवश्यकताओं के मद्देनज़र कंपनी ने अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली की पेशकश की है. यह एक ऐसा उत्पाद है, जो यात्रियों को बोझ उठाने के झंझट से आज़ाद करके सुखद एहसास देगा. अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली दो आकारों 57 सेमी एवं 63 सेमी और तीन रंगों ग्रे, रेड एवं ब्लू में उपलब्ध है. इसकी डीलक्स श्रेणी में अंदर विभाजन भी है, जो पैकिंग को सुविधाजनक बनाता है. इसके शीर्ष में एक हैंडल भी लगा है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना आरामदायक एवं सुविधाजनक है. अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली की डीलक्स श्रेणी हरे एवं पीले रंग में भी उपलब्ध है, जिसकी क़ीमत 1600 एवं 1900 रुपये है. स्ट्रॉली की मज़बूती और सुरक्षा की जांच विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग तरीक़े से की गई है. वीआईपी ने सुपर लाइट स्ट्रॉली भी लांच की है. यह सभी विशेषताओं से युक्त केबिन के आकार की विश्व की सबसे हल्की स्ट्रॉली है. वीआईपी ने पानी और खरोंच से सुरक्षित बैग भी लांच किया है, जिसके निर्माण में टेफलॉन का उपयोग किया गया है. इसमें दो खंड हैं, जिनमें उपभोक्ता व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक सामान अलग-अलग व्यवस्थित तरीक़े से रख सकते हैं. बाज़ार में कंपनी के इन सभी उत्पादों को उपभोक्ताओं द्वारा पसंद किया जा रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

युवाओं के लिए नई एक्सेसरीज

फास्ट्रैक के हिपहॉप धूप चश्मों में सफेद एवं लाल रंगों का समायोजन प्रस्तुत किया गया है और इन्हें ढेर सारे ब्लिंग के साथ बड़े आकार के फ्रेम्स में पेश किया गया है.

भारत के तेजी से विकसित होने वाले युवा फैशन ब्रांड फास्ट्रैक ने अब हिपहॉप घड़ियों एवं सनग्लासेज का नया कलेक्शन लांच किया है. हिपहॉप, चतुर, चपल और तेजतर्रार नई पीढ़ी से प्रेरित होकर कंपनी ने पार्टी घड़ियों एवं चश्मों का नवीनतम कलेक्शन बाज़ार में उतारा है. यह कलेक्शन डॉलर साइन, टर्नटेबल एवं ब्लिंग जैसे परंपरागत हिपहॉप प्रतीक को प्रतिबिंबित करता है. ये घड़ियां आकर्षक एवं स्टोन डस्ट, पेटेंट लेदर स्ट्रैप एवं क्रिस्टल्स से युक्त हैं. इनमें स्कल केस वॉच, ग़ैर परंपरागत एलपी वॉच (रिकार्ड द्वारा प्रेरित) एवं अद्वितीय गैंग्स्टा मेडालियन वॉच जैसी खास डिज़ाइनें हैं. मेडालियन वॉच घड़ी होने के अतिरिक्त गले में पहनी जाने वाली एक बेहतरीन फैशन एक्सेसरी भी है. इन घड़ियों की क़ीमत 1295 रुपये से शुरू होती है और ये 26 विभिन्न डिज़ाइनों में उपलब्ध हैं.

फास्ट्रैक के हिपहॉप धूप चश्मों में सफेद एवं लाल रंगों का समायोजन प्रस्तुत किया गया है और इन्हें ढेर सारे ब्लिंग के साथ बड़े आकार के फ्रेम्स में पेश किया गया है. कनपटी की बनावट के अनुकूल पिरामिड आकार की उभरी हुई सतह और स्टोन डस्ट फील्ड पैटर्न से सुसज्जित शैलीबद्धता के प्रतीक इन चश्मों का प्रत्येक जोड़ा अनूठा है. धूप चश्मों की क़ीमत 895 रुपये से शुरू होकर 1895 रुपये तक है और इसमें 28 विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं. उक्त घड़ियां और सनग्लासेज फास्ट्रैक के एक्सक्लूसिव स्टोर्स, सभी शहरों में वर्ल्ड ऑफ टाइटन शोरूम्स, टाइटन आईप्लस आउटलेट्स, लार्ज फॉर्मेट चेन स्टोर्स मसलन-शॉपर्स स्टॉप, सेंट्रल, लाइफ स्टाइल, पैंटालूंस, वेस्टसाइड, ब्रांड फैक्ट्री और सभी शहरों में अग्रणी मल्टी ब्रांड वॉच, आप्टिकल एवं एक्सेसरीज के आउटलेट्स में उपलब्ध हैं. तो तैयार हैं आप अपनी चमक बिखेरने के लिए?

स्कोडा की नई कार

स्कोडा ने अपनी क्रॉस ओवर फैमिली स्पोर्ट्स कार येती भारतीय बाज़ार में उतारी है. 2.0 लीटर टीडीआई सीआर इंजन वाली येती 4,200 आरपीएम पर 140 बीएचपी का अधिकतम पावर देती है. येती की ख़ासियत है इसका माइलेज, जो डीजल पर 17.67 किमी प्रति लीटर है. कंपनी ने येती के एंबिएंट मॉडल की कीमत 15,40,324 रुपये और एलीगेंस की क़ीमत 16,62,721 रुपये निर्धारित की है. कंपनी को येती लांच करने से पहले ही तक़रीबन 1,000 कारों की बुकिंग मिल चुकी है. कंपनी को उम्मीद है कि लांच के बाद शुरुआती दौर में ही वह हर महीने 400-500 येती बाज़ार में बेच लेगी. येती को कंपनी औरंगाबाद स्थित अपने प्लांट में यूरोप से कलपुर्जे लाकर एसेंबल कर रही है. स्कोडा ऑटो इंडिया बोर्ड के सदस्य एवं डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग थॉमस क्यूल ने बताया कि कंपनी 2011 की शुरुआत में एक एंट्री लेवल सेडान भी लांच करेगी. यह सेडान बेहद प्रतिस्पर्धी क़ीमत पर उपलब्ध होगी.

क्यूल ने बताया कि स्कोडा भारत में 2012 में अपनी छोटी कार भी लांच करेगी, जिसकी क़ीमत 3-5 लाख रुपये के बीच होगी. कंपनी छोटे डीजल और पेट्रोल इंजन बनाने पर काफी ध्यान दे रही है. इसकेअलावा वह अपनी कारों में स्थानीयकरण पर भी जोर दे रही है, जिससे क़ीमतों को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके. कंपनी ने मध्य अक्टूबर के दौरान फाबिया के पेट्रोल वर्जन के एंट्री लेवल मॉडल की क़ीमत 5.02 लाख रुपये से घटाकर 4.35 लाख रुपये कर दी थी. यह छोटी एसयूवी है, जिसकी क़ीमत दूसरी एसयूवी से काफी कम है. यह कार इनोवा, स्कॉर्पियो, जाइलो एवं टवेरा को टक्कर देगी. स्कोडा येती उन लोगों के लिए है, जो शहर के साथ वीकएंड में लांग रूट पर जाते हैं. इसमें बहुत सारे फीचर्स सेडा रूमेस्टर और वीडब्ल्यू गोल्फ बेस्ड टिगुआन एसयूवी से लिए गए हैं. इसके ट्रांसमिशन और ब्रेक रूमेस्टर के हैं और सस्पेंशन स्कोडा फाबिया के. बेहतरीन पैकेजिंग सहित कई अन्य ख़ूबियों वाली यह स्कोडा की एक बेहतर कार है. इसे उन लोगों को लक्ष्य करके लांच किया गया है, जो एसयूवी के एडवेंचर के साथ-साथ लग्जरी कंफर्ट भी चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ ज़्यादा पैसे ख़र्च करने पड़ें.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

एशियाई खेलों के लिए कोरियाई गणतंत्र की चेस टीम में शामिल किम त्ये-गेयोंग की उम्र केवल 11 साल थी, जबकि चाइनीज ताइपे की पेंग जू-आन ने खेलों के आख़िरी दिन 27 नवंबर को अपना 12वां जन्मदिन मनाया.

16वें एशियाई खेल

सबसे बड़ा आयोजन

भव्य उद्घाटन समारोह

12 नवंबर को 16वें एशियाई खेलों की शुरुआत चीन के ग्वांगझू शहर में एक विशाल रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई. देश के दक्षिणी हिस्से में बसे इस शहर में समारोह के दौरान वहां की समृद्ध विरासत का नज़ारा देखने को मिला. पर्ल नदी की लहरों पर कलाकारों के करतब और जगमग रोशनी के अद्भुत दृश्यों ने सबका मन मोह लिया. इस दौरान नदी, नदियों के जल, जल तरंग, नौका विहार एवं रंगबिरंगी पोशाक के साथ झिलमिल रोशनी और संगीत का अनोखा संगम दिखाया गया, जो खेलों के इतिहास में अविस्मरणीय बनकर रह गया.

साढ़े चार घंटे तक चले इस भव्य समारोह के बाद चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने 16वें एशियाई खेलों की शुरुआत की औपचारिक घोषणा की. इस मौके पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष जैक्स रोग्स, एशियन ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष शेख अल सबाह, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी और खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष लिउ पेंग सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं. इस दौरान क़रीब 1,00,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे. इनमें करीब 40,000 सुरक्षाकर्मी उद्घाटन स्थल पर मौजूद थे, जबकि तक़रीबन 60,000 कर्मचारी ग्वांगझू प्रांत के विभिन्न हिस्सों में तैनात थे, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो. इसके अलावा खेलों के सफल आयोजन के लिए 60,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक भी मौजूद थे.

सबसे बड़ा आयोजन

16वें एशियाई खेलों में 42 खेलों की 476 स्पर्द्धाएं आयोजित की गईं, जिनमें 45 एशियाई देशों के कुल 9,704 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इस लिहाज से यह खेलों के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन था, क्योंकि ओलंपिक में भी केवल 28 खेलों की विभिन्न स्पर्द्धाओं का ही आयोजन किया जाता है. टी-20 क्रिकेट को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया, जबकि डांस स्पोर्ट, ड्रैगन बोट, वीकी और रोलर स्पोर्ट भी पहली बार ही इन खेलों का हिस्सा बने. हालांकि 2006 एशियन गेम्स के दौरान जजों के बीच हुए मतभेद के चलते बॉडी बिल्डिंग को इस बार शामिल नहीं किया गया.

उम्र कोई बाधा नहीं

एशियाई खेलों के लिए कोरियाई गणतंत्र की चेस टीम में शामिल किम त्ये-गेयोंग की उम्र केवल 11 साल थी, जबकि चाइनीज ताइपे की पेंग जू-आन ने खेलों के आख़िरी दिन 27 नवंबर को अपना 12वां जन्मदिन मनाया. दूसरी ओर मलेशिया के 66 वर्षीय ले कैम हॉक का जन्म 1944 में हुआ था और 1951 में पहले एशियाई खेलों के आयोजन के समय वह सात साल के थे, लेकिन इस आयोजन में शामिल होने वाले वह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी नहीं थे. बांग्लादेश की शतरंज खिलाड़ी रानी हमीद का जन्म कैम हॉक से भी एक महीने पहले हुआ था. तैराकी और जिम्नास्टिक्स जैसे खेलों में युवा खिलाड़ियों का वर्चस्व एक आम बात है. शतरंज और जियांगी में खिलाड़ियों के बीच उम्र का सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिला.

विवाद

तमाम बड़े आयोजनों की तरह ग्वांगझू में हुआ 16वें एशियाई खेल भी विवादों से बच नहीं पाए. 17 नवंबर को चाइनीज ताइपे की यांग शू-सून को ताइक्वांडो के पहले राउंड के बीच में ही अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के मुक़ाबले 9-0 से आगे चल रही थीं. शू-सून को उनकी जुराबों में अवैध सेंसर लगाने का दोषी पाया गया, जबकि मुक़ाबले से पहले निरीक्षण में उन्हें योग्य घोषित किया गया था. घटना के बाद चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया. इससे पूर्व खेल के पहले ही दिन भारत के अभिनव बिंद्रा शूटिंग रेंज में गड़बड़ी के चलते निशानेबाज़ी की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्द्धा में उम्मीदों के मुताबिक़ प्रदर्शन करने में नाकामयाब रहे. भारतीय निशानेबाज़ी टीम के कोच स्टानिसलाव लेपिडस ने दावा किया कि बिंद्रा का स्कोर 9 था, लेकिन उन्हें 7 अंक ही दिए गए. हालांकि भारतीय टीम ने इसकी औपचारिक शिक़ायत दर्ज नहीं कराई.

19वें राष्ट्रमंडल खेलों के साथ एक तुलना

एक अनुमान के मुताबिक़, 16वें एशियाई खेलों के आयोजन में कुल 420 मिलियन डॉलर ख़र्च किए गए. ग्वांगझू के मेयर वान किंग्लियांग के मुताबिक़, एशियन गेम्स और पारा एशियन गेम्स के आयोजन में सरकार ने कुल 17 बिलियन डॉलर ख़र्च किए, जबकि दिल्ली में आयोजित हुए 19वें राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान 6.8 बिलियन डॉलर ख़र्च किए गए थे.

आदित्य पूजन
aditya@chauthiduntya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

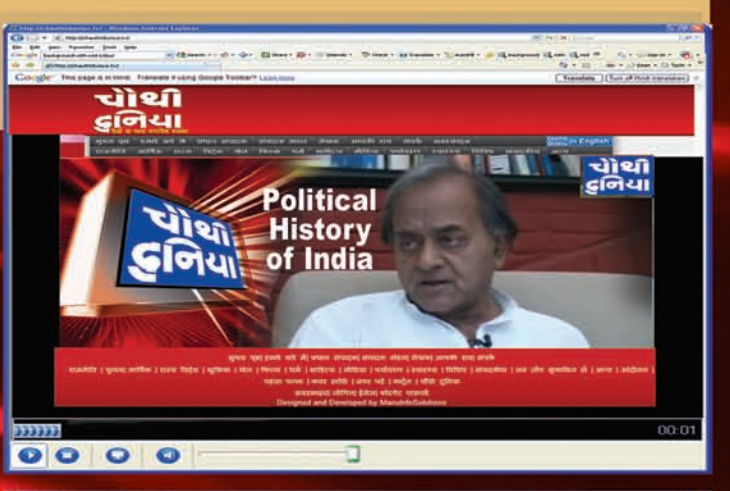

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 29 नवंबर–05 दिसंबर 2010

श्वेता से तलाक का फ़ैसला ख़ुद महेश का था और जब महेश ने उन्हें प्रपोज किया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया.

लारा की शादी

लारा दत्ता आजकल मीडिया की सुर्ख़ियों में हैं. वजह, वह जाने- माने टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति के साथ शादी कर रही हैं. पिछले दिनों लारा और महेश ने न्यूयॉर्क में सगाई की रस्म पूरी की, पर दु:ख की बात यह है कि महेश भूपति की पत्नी श्वेता लारा को उनका घर तोड़ने के लिए ज़िम्मेदार बता रही हैं. इस संबंध में लारा का कहना है कि वह पिछले एक साल से महेश से मिलीं ही नहीं, फिर घर भला कैसे तोड़ सकती हैं. श्वेता से तलाक का फ़ैसला ख़ुद महेश का था और जब महेश ने उन्हें प्रपोज किया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया. जो भी हो लारा, खिलाड़ियों पर हीरोइनों का जादू सिर चढ़कर बोलता है. आपसे पहले भी कई अभिनेत्रियां कई घर तोड़ चुकी हैं. रिकॉर्ड तो यही कहता है, आप किस-किस को सफाई देंगी?

दीया की हताशा

दीया मिर्ज़ा की पहली फिल्म थी रहना है तेरे दिल में, हीरो थे आर माधवन. इसमें दीया रीना मल्होत्रा नामक सीधी-सादी लड़की की भूमिका में थीं, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. दीया के प्रशंसकों की संख्या ख़ासी है, पर उन्हें बॉलीवुड में वह कामयाबी नहीं मिली, जिसकी उम्मीद थी. दीया ने 16 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने मॉडलिंग से की थी. फिर उन्हें फेमिना मिस इंडिया चुना गया, लेकिन यहां तक आने के लिए दीया ने कड़ी मेहनत और संघर्ष किया. उनके पिता फ्रैंक हैंडरिच जर्मन थे. उनकी मां का नाम दीपा है और पेशे से वह इंटीरियर डिजाइनर हैं. छह साल की उम्र में ही उनके माता-पिता का तलाक़ हो गया. फिर उनकी मां ने अहमद मिर्ज़ा से शादी कर ली. दीया ने अपने सौतेले पिता का सरनेम अपनाया, पर उनके सिर पर सौतेले पिता का साया भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा. उनकी मां से शादी के कुछ ही सालों बाद अहमद मिर्ज़ा का निधन हो गया. कई फिल्मों में काम करने के बाद भी बॉलीवुड में अपनी जगह न बना पाने के कारण दीया को कभी-कभी बेहद निराशा होती है. वह कहती हैं, अपने रोल के साथ मैं पूरा न्याय करना चाहती हूं और इसके लिए कड़ी मेहनत भी करती हूं, पर मुझे प्रशंसा नहीं मिलती.

प्रीव्यू

खेलें हम जी जान से

लगान, स्वदेश एवं जोधा अकबर जैसी फिल्मों के निर्माता-निर्देशक आशुतोष गोवरिकर की नई फिल्म खेलें हम जी जान से आगामी 3 दिसंबर को रिलीज होगी. आशुतोष ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं. उनकी यह फिल्म भी स्वाधीनता संग्राम पर आधारित है और आशुतोष गोवरिकर प्रोडक्शन एवं पीवीआर पिक्चर्स के बैनर तले बनी है. इसे प्रोड्यूस किया है आशुतोष गोवरिकर की पत्नी सुनीता गोवरिकर, अजय बीजली एवं संजीव के बीजली ने. फिल्म के निर्देशन के साथ ही आशुतोष ने पटकथा लेखन की भी ज़िम्मेदारी संभाली है. सह निर्देशक हैं लारेंस डिसूजा. संगीत सोहेल सेन का है और गीतकार हैं जावेद अख्तर. संवाद लिखे हैं विलय मिश्रा ने. कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की ज़िम्मेदारी संभाली है नीता लूला ने. गीतों को अपनी आवाज़ से सजाया है सोहेल सेन, पामेला जैन, रंजीनी जोश एवं सुरेश वाडेकर ने. मुख्य भूमिका में हैं अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, विशाखा सिंह, सिकंदर खेर, अमीन गज़ी एवं विजय मौर्या.

फिल्म की कहानी मानिनी चटर्जी की किताब डू एंड डाई पर आधारित है. इसमें 1930-34 के मध्य हुए स्वाधीनता संग्राम को दिखाया गया है. अभिषेक बच्चन शिक्षक सूर्ज्या सेन और दीपिका कल्पना दत्ता की भूमिका में हैं. सूर्ज्या सेन (अभिषेक बच्चन) मास्टर माइंड हैं और ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं. उनका साथ देती हैं कल्पना दत्ता (दीपिका पादुकोण). एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी हैं तो दूसरी ओर किशोरवय बच्चों का एक समूह है, जो ब्रिटिश हुकूमत से इसलिए टक्कर लेना चाहता हैं, क्योंकि उसे अपना प्ले ग्राउंड चाहिए. बच्चे सूर्ज्या सेन के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुना है कि आप देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, देश आज़ाद कराने के साथ-साथ आप हमें हमारा खेल का मैदान दिला दें. दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन की एक साथ यह पहली फिल्म है. आशुतोष ने यह फिल्म बनाने में काफी मेहनत की है, लेकिन इसे दर्शक कितना महत्व देंगे, यह तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा.

अनुष्का को विविध भूमिकाओं की चाह

बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपनी अगली फिल्म बैंड बाजा बारात को लेकर काफी उत्साहित हैं. इस फिल्म में उनका रोल वेडिंग प्लानर का है. इसमें उनके हीरो रणवीर सिंह हैं. फिल्म को प्रोड्यूस किया है यश चोपड़ा ने. अनुष्का ने अपने करियर की शुरुआत यशराज प्रोडक्शन के बैनर तले ही की थी. उनकी पहली फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी. इसमें उनके अपोजिट शाहरुख खान थे और इस फिल्म में अनुष्का ने शादी से नाखुश लड़की की भूमिका की थी. इस फिल्म के बाद वह यश कैंप की पसंदीदा अभिनेत्रियों में शुमार हो गई. यशराज प्रोडक्शन की अगली फिल्म बैंड बाजा बारात में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा की भूमिका अदा की है, जो कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वेडिंग प्लानर का काम शुरू करती है. इसके लिए वह दिल्ली का जनकपुरी क्षेत्र चुनती है. अनुष्का कहती हैं कि यह उनके द्वारा अब तक निभाई गई सभी भूमिकाओं में श्रेष्ठ है. कम समय में अनुष्का ने कई तरह के रोल किए हैं.

वह एक ही प्रकार के रोल में बंधना नहीं चाहती. अनुष्का ने फिल्मों में विविध प्रकार के रोल किए हैं. सीधी सादी घरेलू लडकी के किरदार से लेकर बेहद ग्लैमरस भूमिकाएं भी की है. यही वजह है कि वो आज की अच्छी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी हैं. जहां इंडस्ट्री में एक तरफ परिवारवाद का बोलबाला है, वहां अनुष्का का यह मानना है कि स्टार परिवार का ना होने से उन्हें फायदा ही मिला है. इस बात बात से उन्हें बेइंतहा खुशी होती है कि वो आज जहां भी हैं, अपने बलबूते पर पहुंची हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 29 नवंबर-05 दिसंबर 2010

www.chauthiduniya.com

आतंकियों का ट्रांजिट रूट बना उत्तर प्रदेश

ख़ुफ़िया तंत्र की मानें तो नेपाल में जारी राजनीतिक अनिश्चितता का फ़ायदा पाकिस्तान आतंकी संगठनों को मजबूती और ट्रेनिंग देने में उठा रहा है. माओवादियों के साथ आतंकियों के रिश्तों का पहले ही ख़ुलासा हो चुका है. नेपाल में पाक दूतावास इनके लिए कई सुविधाओं के साथ ही ट्रेनिंग के लिए सुरक्षित ठिकाने भी मुहैया कराता है. आतंकी वारदातों को अंजाम देने का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आतंकवादियों की खेप को नेपाल के रास्ते ही वाया उत्तर प्रदेश होते हुए भारत के विभिन्न इलाक़ों में पहुंचा दिया जाता है.

शत्रुंजय कुमार सिंह

नेपाल में जारी राजनीतिक अनिश्चितता पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही नहीं चेती, तो भारत एक बार फिर से सिख आतंकवाद से दहल उठेगा. जम्मू-कश्मीर समेत देश के कई राज्य पहले से ही पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की विभीषिका से जूझ रहे हैं. अब पाकिस्तान से सिख आतंकवादियों को पूरी मदद मिल रही है और इन्हें नेपाल होते हुए भारत भेजा जा रहा है. ख़ुफ़िया अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान उत्तर प्रदेश को ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है. भारत-नेपाल की 550 किलोमीटर लंबी खुली सीमा आतंकियों के नापाक मंसूबों में मददगार साबित हो रही है. नेपाल की सीमा से आतंकियों को उत्तर प्रदेश में घुसाकर उन्हें तराई के इलाक़ों में शरण दिलाई जाती है. यहां से आतंकवादियों को देश के विभिन्न हिस्सों में वारदातों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है. पाकिस्तान की यह साज़िश इस लिहाज़ से भी ख़तरनाक है कि अब सिख और मुस्लिम आतंकवादी संगठन एक साथ काम कर रहे हैं. नेपाल में पाक दूतावास से इन आतंकियों को हर तरह की मदद मिल रही है. सिद्धार्थ नगर के बढ़नी बॉर्डर से सिख आतंकवादी माखन सिंह उर्फ दयाल सिंह की गिरफ्तारी से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का ख़ुलासा होता है. माखन सिंह से मिली जानकारी के अनुसार आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल पाकिस्तान की मदद से अपने संगठन को मजबूत करने में लगा है. माखन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सेकेंड लेफ्टिनेंट है, जो दर्जनों सिख युवकों को आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग दिलाकर उन्हें नेपाल के रास्ते भारत भेज चुका है. उसके काठमांडू में सक्रिय आईएसआई एजेंटों से अच्छे संबंध हैं. नेपाल में वह अपनी सारी गतिविधियों को पाकिस्तानी दूतावास के संरक्षण में अंजाम दे रहा था. माखन ने जो चौंकाने वाला ख़ुलासा किया है, वह और भी ज़्यादा चिंताजनक और संवेदनशील है. इसके मुताबिक़ आईएसआई के संरक्षण में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के खालिस्तानी मूवमेंट को अमेरिका के कुछ सिखों से आर्थिक मदद मिल रही है. सिद्धार्थनगर व उसके पड़ोसी महराजगंज ज़िले की सीमा नेपाल से सटी है. इस इलाक़े से अब तक क़रीब एक दर्जन से अधिक दुर्दांत सिख आतंकी पकड़े जा चुके हैं.

वर्ष 1997 में बढ़नी बॉर्डर पर सबसे पहले सिख आतंकवादियों भाग सिंह और अजमेर सिंह को बॉर्डर पुलिस फोर्स ने गिरफ्तार किया था. दोनों ही आतंकी पंजाब में हत्या व लूट की दर्जनों वारदातों के आरोपी थे. चार माह पहले एटीएस प्रभारी अभय प्रताप मल्ल ने बटला हाउस कांड के आरोपी और पांच लाख के इनामी आतंकवादी सलमान को गिरफ्तार किया था. सलमान आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य है. बढ़नी सीमा पर ही पांच साल पहले शकील नामक आतंकवादी को एके-47 के साथ गिरफ्तार किया गया था. इसके पूर्व महराजगंज के सोनौली बॉर्डर पर मुंबई बमकांड के मास्टर माइंड याकूब मेनन, हार्डकोर आतंकी राजू खन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मेनन वर्ष 1992 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट का न केवल मास्टर माइंड था बल्कि उसने धमाके कराने के लिए आतंकियों को धन भी मुहैया कराया था. भारत-नेपाल की 550 किमी लंबी सीमा पूरी तरह से खुली है. यह आतंकवादियों के लिए काफ़ी सुरक्षित है. मुख्य मार्गों पर ही बैरियर लगाकर चेकिंग होती है, खुले कच्चे रास्तों पर चेकिंग कर पाना मुमकिन भी नहीं है. माखन सिंह की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने ख़ुलासा किया कि कैलीफोर्निया में तारा सिंह ने माखन सिंह की बातचीत बधावा सिंह उर्फ चाचा से कराई थी. बाधवा सिंह आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मुखिया है, जिसने पाकिस्तान में शरण ले रखी है. माखन सिंह ने पाकिस्तान में आरडीएक्स युक्त बम बनाने में महारत हासिल की. नवंबर 2009 में वह पाकिस्तान से पांच अन्य आतंकियों के साथ नदी के रास्ते गुरदासपुर सीमा से भारत में घुसा. ये लोग अपने साथ तीन एके-47, तीन पिस्टल, दो हैंड ग्रेनेड और चार सौ कारतूस लाए थे. माखन ने कर्णवीर के साथ मिलकर पंजाब में मैयादास डेरा के महंत की हत्या की थी. इन दोनों ने ही पंजाब में माछीवाड़ा पुल उड़ाने का भी प्रयास किया था.

ख़ुफ़िया तंत्र की मानें तो नेपाल में जारी राजनीतिक अनिश्चितता का फ़ायदा पाकिस्तान आतंकी संगठनों को मजबूती और ट्रेनिंग देने में उठा रहा है. माओवादियों के साथ आतंकियों के रिश्तों का पहले ही ख़ुलासा हो चुका है. नेपाल में पाक दूतावास इनके लिए कई सुविधाओं के साथ ही ट्रेनिंग के लिए सुरक्षित ठिकाने भी मुहैया कराता है. आतंकी वारदातों को अंजाम देने का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, आतंकवादियों की खेप को नेपाल के रास्ते ही वाया उत्तर प्रदेश होते हुए भारत के विभिन्न इलाक़ों में पहुंचा दिया जाता है. नेपाल के रास्ते पाकिस्तान ने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का अभियान चला रखा है. जाली नोटों की लंबी खेप वाया नेपाल भारत पंहुचाई जा रही है. पिछले तीन माह में जाली नोट तस्करों को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है. यहां आतंकवादियों और जाली नोटों के तस्करों की गिरफ्तारी एटीएस करती है.

लोकल पुलिस को इनकी गतिविधियों की भनक नहीं लग पाती, वजह क्या है, यह तो पुलिस विभाग के आला अधिकारी ही जानें. नेपाल से सटे भारतीय इलाक़ों में पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसियों की पकड़ से लोकल पुलिस, ख़ुफ़िया तंत्र और प्रशासन भले ही इनकार करे लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान उत्तर प्रदेश को ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है. नेपाल के सरहदी ज़िलों से अब तक क़रीब साढ़े तीन सौ लोगों की गिरफ्तारी इस बात की पुष्टि करती है. वह भी उन हालात में जब इन गिरफ्तार लोगों में अधिकतर की पहचान जैश-ए-मोहम्मद और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के सदस्य के रूप में की जा चुकी है. 550 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा पूरी तरह से खुली है और दोनों देशों के लोग बेरोक-टोक एक-दूसरे के यहां आते जाते रहते हैं. इसी का फ़ायदा उठाने में लगी है पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई. इंडो-नेपाल बॉर्डर से आतंकियों की घुसपैठ की पुष्टि गृह मंत्रालय के उस आदेश से भी होती है, जिसमें सशस्त्र सीमा बल को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बात की पक्की सूचना मिली है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन नेपाल की सीमा के जरिए भारत में घुसने की फिराक में है. नेपाल के रूपनदेह, विराटनगर, परसा, मकवानपुर, झांपा, सुनसरी, इलाम, मेची आदि इलाक़ों में पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगी है. काठमांडू पुलिस प्रवक्ता हरेकृष्ण खनाल के मुताबिक़ वर्ष 2009 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल आने वाले क़रीब डेढ़ सौ पाकिस्तानी नागरिकों को नेपाल के विभिन्न ज़िलों से गिरफ्तार किया गया था. इस वर्ष अभी तक साढ़े तीन सौ पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. कुछ दिन पहले झांपा ज़िले से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को सुरक्षाकर्मियों ने गिरफ्तार किया था, जिसके पास फ़र्ज़ी नेपाली पासपोर्ट मिला. नेपाली भाषा का एक भी शब्द न बोल पाने वाला यह शख्स खुद को नेपाल का नागरिक बता रहा था. बाद में ख़ुलासा हुआ कि वह पाकिस्तानी नागरिक है और उसका नाम अशरफ है. अशरफ की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने भी एलर्ट जारी कर रखा था. मार्च महीने में भारत-नेपाल सीमा पर एक पाकिस्तानी, एक इसराइली व एक जर्मन नागरिक को बिना उचित दस्तावेजों के भारत में घुसते हुए सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पकड़ा था. पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी के साथ मिलकर देशद्रोह की गतिविधियों में शामिल कई लोग रातों-रात धनवान हो गए, जिन पर प्रशासन की नज़र तो है. लेकिन वह इन पर सीधे तौर पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है.

ख़ुफ़िया तंत्र की मानें तो प्रतिबंधित संगठन का एक सदस्य इलाक़े की शैक्षणिक संस्था में अध्यापन का कार्य कर रहा है. इससे साफ़ है कि आईएसआई ने भारत-नेपाल सीमा पर अपनी जड़े कितनी गहराई तक जमा ली है. एसएसबी के डीआईजी ब्रजसोम का कहना है कि सीमा पर एसएसबी के जवानों की सतर्क नज़र है. चेकिंग की जा रही है. नेपाल से सटी सरहद पर आतंकियों की बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय है.

अब वाहन से गश्त कर सकेंगे जवान

भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सुरक्षा बल के जवानों को अब झाड़-झंखाड़ के बीच पैदल गश्त करने की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. अब वह सीमा के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने वाहन से आराम से गश्त कर सकेंगे. केंद्र सरकार ने लोक निर्माण विभाग को भारत-नेपाल सीमा पर सात मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार कर उसे भेजने का निर्देश दिया है. इस योजना को मूर्तरूप देने के लिए लखनऊ में केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक में सहमति बन चुकी है. सड़क सीमा बिंदु से सौ गज पहले बनेगी जिसका विस्तार नेपाल से सटने वाले प्रत्येक ज़िले तक होगा. यह सड़क ख़ासतौर पर एसएसबी के लिए रिजर्व रहेगी. सड़क पर हाईपावर के प्रकाशबिंदु और निगरानी के लिए विशेष उपकरण लगाए जाएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद अमर सिंह ने अराजनीतिक संगठन लोकमंच का गठन किया था.

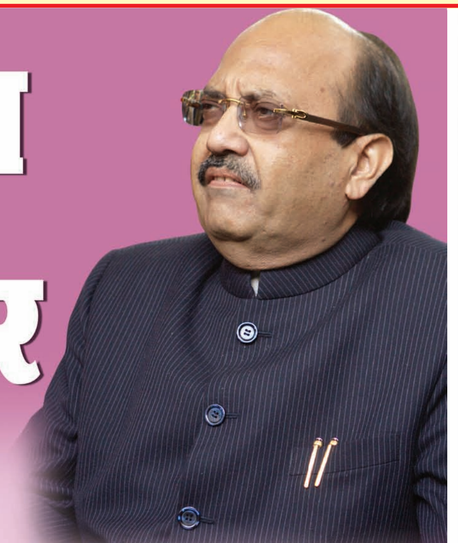

अमर सिंह का सियासी सफ़र

विजय यादव

पंचायत चुनाव ख़त्म होने के बाद बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में ज़ुबानी जंग छिड़ी है. दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि चुनाव में उनके समर्थक सबसे अधिक संख्या में जीते हैं. अब असलियत क्या है, यह तो इन पार्टियों के नेता ही जानें. इन दावों के बीच एक राजनीतिक शख़्सियत ऐसी भी है जिसने कोई दावा नहीं किया. फिर भी यह जता दिया कि पंचायत चुनावों में उसने अपने लिए ज़मीनी आधार तैयार किया है. इसका गवाह बना लखनऊ के गन्ना संस्थान सभागार में आयोजित एक समारोह. इस मौक़े पर पंचायत चुनावों में जीत हासिल करने वाले प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ज़िला पंचायत सदस्यों को शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया. हज़ार से अधिक संख्या में पंचायत प्रतिनिधि जुटे. जनता की ओर से निर्वाचित इन सभी प्रतिनिधियों के हाथों में जीत का प्रमाणपत्र भी था. मतलब साफ़ कि यह जनप्रतिनिधि फ़र्ज़ी नहीं बल्कि असली हैं. इनके समर्थकों को मिला लें तो कार्यक्रम में पांच हज़ार से अधिक लोग शामिल होते हैं. यह सभी लोक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह को अपना नेता मानते हुए संघर्ष करने का ऐलान करते हैं. यह वही अमर सिंह हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद हवा-हवाई नेता तक क़रार दिया गया था. यहां तक कहा गया कि अमर सिंह का अपना कोई जनाधार नहीं है. सपा नेताओं के इन बड़बोले दावों को अमर सिंह ने बगैर कुछ कहे पंचायत प्रतिनिधियों के इस सम्मान समारोह के ज़रिए फुस्स कर दिया. इसके साथ ही अमर सिंह ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत भी कर दी. पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में बनारस, गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, इलाहाबाद, बलिया, आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के सभी ज़िलों से भागीदारी रही. इसमें केवल राजपूत समुदाय के पंचायत प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी नहीं रही बल्कि कुशवाहा, यादव, ब्राह्मण, कुर्मी समेत सभी जातियों के प्रधान, बीडीसी व ज़िला पंचायत सदस्य शामिल हुए. गाजीपुर से आए उमेश यादव की पत्नी रीता प्रधानी का चुनाव जीती हैं. इसी तरह रमाकांत यादव ने क्षेत्र पंचायत सदस्य और छविनाथ कुशवाहा ने प्रधान का चुनाव जीता और वह अमर सिंह को अपना नेता मानते हैं. यह दोनों कहते हैं कि जाति के आधार पर समर्थन करने से प्रदेश का विकास नहीं होगा. इसके लिए समग्र सोच वाला नेता चाहिए, अमर सिंह इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं. अमर सिंह अब पैदल यात्रा पर निकलेंगे. आम जनता के दुख, दर्द, उनकी समस्याओं, युवाओं की बेरोज़गारी, शिक्षा समेत तमाम मुद्दों को वह पैदल यात्रा में महसूस करेंगे. यह पृथक पूर्वांचल राज्य आंदोलन का श्रीगणेश भी होगा.

समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद अमर सिंह ने अराजनीतिक संगठन लोक मंच का गठन किया था. अमर सिंह इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए जबकि ओबेदुल्ला आज़मी कार्यकारी अध्यक्ष, सिने अभिनेता संजय दत्त राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सदस्य जया प्रदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुईं. लोक मंच के गठन के साथ ही अमर सिंह ने छोटे राज्यों की वकालत करते हुए अपने लिए आधार तैयार करने का काम शुरू कर दिया था. अब एक दिसंबर से इलाहाबाद से प्रारंभ होने वाली पद यात्रा इसी मिशन का एक हिस्सा है, जो गोरखपुर पहुंचकर समाप्त होगी. बकौल अमर सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 ज़िले आते हैं. यहां से 147 विधायक और 28 सांसद चुने जाते हैं. बात जब विकास की आती है तो पूर्वांचल सबसे पिछड़ा नज़र आता है. वह आरोप लगाते हैं कि पूर्वांचल के विकास के लिए आने वाला धन सैफ़ई और मायावती के क्षेत्र में ख़र्च कर दिया जाता है. पूर्वांचल विकास यात्रा में संजय दत्त और जया प्रदा स्वाभाविक तौर पर उनके हमराह होंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से चर्चा में रहने वाले अमर सिंह इस आयोजन में भाग लेने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी समेत अन्य राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों को भी ख़ुद पत्र लिखेंगे. अब यह नेता लोक मंच की यात्रा का हिस्सा बनते हैं या नहीं, यह अलग मुद्दा है, इसके बीच अहम यह है कि अमर सिंह का आमंत्रण उन्हें पृथक पूर्वांचल राज्य पर अपने पत्ते जनता के बीच खोलने के लिए मजबूर करेगा. पदयात्रा के दौरान अमर सिंह जब यह सवाल उठाएंगे तो इन दलों के लिए यह साफ़ करना ज़रूरी हो जाएगा कि वह अलग पूर्वांचल राज्य चाहते हैं या नहीं. अगर उत्तर हां में होगा तो फिर यह परोक्ष रूप से अमर सिंह के आंदोलन का समर्थन करना होगा और लोक मंच यही चाहता है. पृथक पूर्वांचल राज्य के साथ ही अमर सिंह हरित प्रदेश और बुंदेलखंड राज्य की मुहिम भी चलाएंगे. इस आंदोलन में वह रालोद नेता अजित सिंह को भी अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. गांवों में ज़मीनी आधार तैयार करने वाले अमर सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए उन्हें यह संदेश भी दिया कि अंग्रेजी पढ़ो, कंप्यूटर सीखो और ट्रैक्टर से खेती करो. ऐसा करके अमर सिंह ने गांव-गलियारे में रहने वाले मतदाताओं के मन में जीवन स्तर ऊंचा करने, नई सोच विकसित करने का जज्बा पैदा करने की कोशिश भी की.

> सपा नेताओं के इन बड़बोले दावों को अमर सिंह ने बगैर कुछ कहे पंचायत प्रतिनिधियों के इस सम्मान समारोह के ज़रिए फुस्स कर दिया. इसके साथ ही अमर सिंह ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत भी कर दी. पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में बनारस, गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, इलाहाबाद, बलिया, आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के सभी ज़िलों की भागीदारी रही. इसमें केवल राजपूत समुदाय के पंचायत प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी नहीं रही, बल्कि कुशवाहा, यादव, ब्राह्मण, कुर्मी समेत सभी जातियों के प्रधान, बीडीसी व ज़िला पंचायत सदस्य शामिल हुए.

वह सवाल करते हैं कि अंग्रेजी और कंप्यूटर का विरोध करने वाले मुलायम सिंह यादव के एक बेटे अखिलेश पढ़ाई पूरी करने ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और दूसरे पुत्र प्रतीक भी विदेश में पढ़ाई पूरी करते हैं. अपने बेटे अंग्रेजी सीखें तो अच्छा और गांव के आदमी का लड़का अंग्रेजी में बात करे तो मुलायम सिंह को यह पसंद नहीं. अमर सिंह कहते हैं कि यह दोहरा मापदंड और सोच अब चलने वाली नहीं है. उत्तर प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटने के समर्थन में अमर सिंह और लोक मंच के अपने तर्क भी हैं. अमर सिंह कहते हैं कि किसी भी बड़े प्रदेश का विभाजन हो जाने के बाद उसकी तरक्की के कई रास्ते खुल जाते हैं. अपनी राजनीतिक मुहिम में अमर सिंह ने कई छोटे दलों को हमराह बनाया है. इनमें वंचित जमात पार्टी, आवामी समता पार्टी, वंचित उदय, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, जनसत्ता पार्टी, जय भारत समानता पार्टी, जनवादी पार्टी शामिल है. राज्य सभा की सदस्यता के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अमर सिंह के तेवर देखकर तो यही लगता है कि वह उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर अब खुलकर बैटिंग करेंगे. इलाहाबाद से गोरखपुर की यात्रा के बाद वर्ष 2011 में नए राजनीतिक दल का ऐलान करेंगे. लक्ष्य होगा वर्ष 2012 में होने वाला विधानसभा चुनाव.

feedback@chauthiduniya.com

SETH CHANNURAM BAJAJ MEMORIAL SR.SEC.PUB.SCHOOL NARAYAN NAGAR, PUNJABI COLONY, MAINPURI

चौथी दुनिया के उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल संस्करण के प्रकाशन पर सीआरबी पब्लिक स्कूल के परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं

विशेषताएं : यह विद्यालय नारायण नगर शिक्षा समिति, सेवा सदन नारायण नगर मैनपुरी द्वारा संचालित है. विद्यालय का एक विशाल भवन है. जिसमें इंटर विज्ञान, वाणिज्य, कला, कंप्यूटर की कक्षाएं संचालित हैं. विद्यालय में समय-समय पर साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कला आदि प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं.

सदस्यगण : धर्मचंद्र निझारा, नरेश बजाज, सतीश सेठी, नारायण कालरा, हरिकिशन बजाज, अनिल कुमार छिब

भारतीय कपिलमुनि स्नातकोत्तर महाविद्यालय
करीमगंज बेवर (मैनपुरी)

चौथी दुनिया उ.प्र./उ.खंड संस्करण के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएं
नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोगांव-मैनपुरी

AMETHYST TOWN PLANNERS PVT. LTD. SPN.
चौथी दुनिया
चौथी दुनिया के उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल संस्करण के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं
दिनेश सिंह "बिश्नोई" रजनीश राज सक्सेना
शराब कंपनी
मोहनगंज, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश

दो सरकारी विभागों के अलग-अलग आंकड़े हक़ीक़त का ख़ुलासा कर रहे हैं.

भूख से ख़त्म होती ज़िंदगी

कमला प्रसाद गुप्त

इधर सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ रहा है उधर कुपोषण के शिकार बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. इस भयावह तस्वीर के बीच शासन-प्रशासन के अधिकारी ख़ूब फल-फूल रहे हैं. इन अफसरों की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी हैं कि उन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर भी नहीं होता. कुपोषण से बच्चों की मौत को ये अधिकारी आंकड़ों की बाज़ीगरी से छिपाने में शर्म महसूस नहीं करते हैं. यहां सवाल महज़ उन नौनिहालों के कुपोषण का नहीं है जो कल को देश का भविष्य बनेंगे, बल्कि उनकी शिक्षा का भी है जिसे अफसरशाही का भ्रष्टाचार निगलता जा रहा है. अकेले आजमगढ़ जनपद की यह तस्वीर ही समूचे उत्तर प्रदेश की हक़ीक़त बयां करने के लिए काफ़ी है. यहां कुपोषण से बच्चों की मौत की हक़ीक़त छिपाने के लिए घिनौना खेल प्रशासनिक मशीनरी ने खेला वह सभी को शर्मसार कर देने वाला है. यह बच्चे कुपोषण से तब मरे जबकि उनके गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं. यहां उनके लिए पुष्टाहार की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है. झूठ की हद देखिए, एक विकासखंड के केवल दो गांवों में मिले चौदह कुपोषित बच्चों की सर्वे रिपोर्ट को नकारते हुए स्वास्थ्य विभाग ने महज़ दो और ज़िला बाल विकास विभाग ने पूरे ब्लॉक में केवल नौ नौनिहालों को कुपोषित माना है. दो सरकारी विभागों के यह अलग-अलग आंकड़े हक़ीक़त का ख़ुलासा कर रहे हैं. असल में दोनों ही विभाग झूठ बोल रहे हैं. कुपोषण से बच्चों की हो रही मौतों को छिपाने के लिए सरकारी अमला आंकड़ों के खेल में उलझा हुआ है. अधिकारी आंकड़ों के खेल में उलझे रहे और तरवां विकासखंड के ढाटा गांव निवासी गुड्डू वनवासी की बेटी व बेटा सूरज मौत के आगोश में समा गए. कुपोषण से बच्चों की मौत से गुड्डू और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पर नौकरशाहों को कुपोषित बच्चों की सही गिनती से इतना गुरेज है कि वे आंकड़ेबाज़ी करने से बाज़ नहीं आ रहे हैं. सच स्वीकार करने के बजाय स्वास्थ्य विभाग कुछ आंकड़ा दे रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीम मौक़े पर पहुंचकर कुछ कहती है तो बाल विकास परियोजना विभाग का सर्वे कुछ और ही बताता है. सरकारी विभागों के विपरीत निजी संस्था का सर्वे बहुत चौंकाने वाला है. यह सर्वे सीधे तौर पर दर्शाता है कि सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करना बेमानी है. तरवां विकासखंड के ढाटा गांव निवासी घुरहू के तीन बच्चों शंभू (8), छोटू (5) व रीना (3) की दो माह पहले कुपोषण से मौत हो चुकी है. एक महीने पहले ही बीबीपुर गांव निवासी नीलम की कुपोषण के चलते मौत हुई थी. 16 सितंबर को ढाटा गांव निवासी गुड्डू वनवासी की एक वर्षीय पुत्री चंदा भी मौत के मुंह में समा गई. अभी गुड्डू का परिवार सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि चंदा का जुड़वां भाई सूरज भी 23 सितंबर को चल बसा. बीबीपुर गांव निवासी सहादुर का डेढ़ वर्षीय पुत्र सोनू तथा ढाटा गांव निवासी मंजू का तीन वर्षीय पुत्र भी गंभीर अवस्था में ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है. मज़ेदार बात तो यह है कि तरवां विकासखंड में 18 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हैं. रोजा संस्था के सर्वे में जिन 11 गांवों में कुपोषण की बात सामने आई है, वहां भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं. नज़दीकी गांव बीबीपुर में अस्पताल भी है. ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आरती सिंह का कहना है कि तरवां ब्लॉक के कुल 38,245 बच्चों में मात्र नौ बच्चे ही कुपोषण के शिकार हैं. वहीं 25 सितंबर को आजमगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. बी.बी. सिंह जब वहां पहुंचे तो उन्हें वहां पर मनोज (3) पुत्र बहादुर तथा छट्ठू (3) पुत्र मंजू कुपोषण के शिकार मिले. यदि निजी संस्था रोजा की सर्वे रिपोर्ट पर नज़र डालें तो अकेले बीबीपुर और ढाटा गांव की वनवासी बस्तियों में पहले ही नौ बच्चे कुपोषित पाए गए हैं. जबकि 26 सितंबर को संस्था के सचिव मुश्ताक अहमद ने बताया कि पांच और बच्चों को उन्हीं गांवों में कुपोषित पाया गया है. अगर रोजा की रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए तो सवाल यह उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग को दो गांवों में दो ही बच्चे कुपोषण के शिकार मिले? जबकि बाल विकास परियोजना विभाग ने पूरे तरवां विकासखंड में केवल नौ बच्चों को कुपोषण का शिकार बताया है.

इतना ही नहीं, वनवासी गांवों के बच्चे अब तक शिक्षा के दर्शन भी नहीं कर पाए हैं. जबकि सरकार की ओर से सर्व शिक्षा अभियान का ढिंढ़ोरा पीटा जा रहा है. अब देखना है कि कुपोषण से लगातार हो रही मौतों पर शासन और प्रशासन आंकड़ेबाज़ी का खेल खेलने में ही मशगूल रहेगा या बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए ज़मीनी कवायद भी करेगा.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया के उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड संस्करण के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई
अग्रवाल नर्सिंग एवं मैटरनिटी होम
नई तहसील के सामने, कचहरी रोड, मैनपुरी

चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड संस्करण के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएं
मनीष वर्मा — सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड
अमित रस्तोगी — लोक निर्माण विभाग, उन्नाव
विजय शंकर द्विवेदी — अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
राम औतार — थानाध्यक्ष, बारा सगवर, उन्नाव
मो. ज़ुबैर — जिलाध्यक्ष, मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन, सिंचाई खंड, उन्नाव
जगदीप बाजपेई — सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव
एस.पी. राजपूत — सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड
ई. दरबारी लाल — अवर अभियंता, विद्युत वितरण खंड-उन्नाव
संजय सिंह — अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ, मियागंज, उन्नाव
सुनील सिंह
महेन्द्र सिंह
आलोक प्रसाद
गुड्डू सिंह
संदेश पटेल
धर्मेश सिंह उर्फ आशू
कानपुर गन हाउस
डी.एस. बीयर शॉप, डी.एस. वाइन शॉप
राना ऑटोमोबाइल्स
कार्यालय नगर पंचायत, बीघापुर उन्नाव
कार्यालय नगर पालिका परिषद लखीमपुर-खीरी (उ.प्र.) 262701
मनोज श्रीवास्तव, गवर्नमेंट कान्ट्रेक्टर एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर
सोनू सिंह, बाबा मेडिकल स्टोर
चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड संस्करण के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएं — दीपक कुमार, सपा विधायक सदर; संजय सिंह, युवा सपा नेता
चौथी दुनिया उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड संस्करण के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएं — एसएच रिज़वी, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उन्नाव
चौथी दुनिया के उ.प्र./उ.खंड संस्करण के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएं
राष्ट्रीय साप्ताहिक चौथी दुनिया के उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड संस्करण के उद्घाटन के अवसर पर आजमगढ़ खनिज तेल उपभोक्ता संघ अपनी शुभकामनाएं देता है तथा चौथी दुनिया के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।
कार्यालय ज़िला सहकारी बैंक लि., लखीमपुर-खीरी
सस्ता गल्ला विक्रेता संघ, आजमगढ़
राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र चौथी दुनिया के उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड संस्करण प्रकाशित किए जाने पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता है और चौथी दुनिया के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।
महामंत्री त्रिभुवन यादव; उपाध्यक्ष केदार नाथ; अध्यक्ष शंकर राम यादव; कोषाध्यक्ष जीवन प्रकाश सिंह; संरक्षक छन्नी राम; पूर्व संरक्षक श्याम नरायन

नवाब रामपुर की नाट्य शाला से संस्था ने क़ीमती पर्दे भी हासिल किए. जिनका प्रयोग लगातार फारसी शैली के नाटकों में देखा गया.

कई रंगों से सजा है शाहजहांपुर रंगमंच

- यहां के पानी में कुछ तो बात है जिससे रंगमंच दिन-ब-दिन समृद्ध हो रहा है
- हिंदी एकांकीकार भुवनेश्वर ने जन्म लेकर असंगत नाटकों में पहचान बनाई
- वर्तमान में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की भी यह धरती है
- कई रंगकर्मी एन.एस.डी. और बी.एन.ए. से पूर्ण कालिक डिप्लोमा पा चुके हैं

ज़रीफ मलिक

दिल्ली और लखनऊ के बीचों-बीच बसे शाहजहांपुर ज़िले के सांस्कृतिक परिदृश्य पर दृष्टि डाली जाए तो यहां रंगमंच एक समृद्ध विधा के रूप में स्थापित दिखाई देता है. यहां के रंगकर्मी राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाट्य मंचनों से पहचान स्थापित करते दिखाई देंगे. रंगमंचीय इतिहास देखें तो लगभग 100 वर्ष की जानकारी स्पष्ट मिलती है. 20वीं सदी के शुरुआती सालों में प्राचीन कथाओं, धार्मिक महाकाव्यों और ऐतिहासिक विषय वस्तु व कथानकों पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां होती थीं. सन 1918-20 में हनुमंत परिषद नाम की संस्था की विधिवत स्थापना हुई, जिसमें पुवायां के राजा साहब फतेह सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी. उस दौरान परिषद द्वारा मंचित प्रमुख नाटक भक्त प्रहलाद, राजा हरिश्चंद्र, सिकंदर और पोरस, सुल्ताना डाकू, हमीर हठ, राजा मोरध्वज, राजा विक्रमादित्य आदि थे. सन 1930 से 40 के दौर में मुख्य रूप से दो संस्थाएं सामने आईं, कृष्णा क्लब और रामा क्लब. इस संस्था द्वारा मंचित प्रमुख नाटक सिकंदर और पोरस तथा राजा हरिश्चंद्र थे. इसी दौरान शंकर ड्रामेटिक क्लब की स्थापना हुई. कुछ समय बाद रामा क्लब और शंकर क्लब आपस में मिल गए और रामाशंकर ड्रामेटिक क्लब की स्थापना हुई. जिसे निरंकार सहाय मस्त, डॉ. मलिक आदि ने संवारा. यह वह दौर था जब पारसी और नौटंकी शैली का वर्चस्व था. सन 1945 में भगवती सहाय और बाबू निरंकार सहाय मस्त उर्फ़ मस्त बाबू ने आर्डनेंस ड्रामेटिक क्लब का गठन किया. इसमें मोहम्मद सिद्दीकी, रघुवंश नारायण, फजल अहमद, बाबूराम तिवारी आदि के सहयोग से नाटक वीर अभिमन्यु, हमीर हठ, दुर्गादास राठौर, शिव पार्वती, छीन लो रोटी आदि के मंचन किए.

इतना ही नहीं नवाब रामपुर की नाट्य शाला से संस्था ने क़ीमती पर्दे भी हासिल किए. इनका प्रयोग लगातार फारसी शैली के नाटकों में देखा गया. वर्ष 1965 में आनंद सक्सेना, पीके मुखर्जी, एलएन शर्मा बाल किशन, चंद्र मोहन महेंद्रू, सुशील शर्मा, महेश सक्सेना आदि ने जय नाट्यम नाट्य संस्था का गठन कर कई वर्षों तक पुजारी, ज़माना, फ़ैसला, अंडर सेक्रेट्री, रक्तरेखा एवं चर्चित नाटक नेफा की एक शाम मंचन किया. इन्हें काफ़ी सराहा गया. सन 1969 में साहू अशोक कुमार बेढ़ब ने युगांतर बाल सेना नाम की एक सांस्कृतिक संस्था बनाई, जिसने शुरूआत में नन्हें बालकों में देशभक्ति, सद्भाव, भाईचारा की विचारधारा विकसित करने के कार्यक्रम किए. बाद में यह संस्था युवाओं के बीच भी आई और संस्था का नाम हो गया युगांतर सांस्कृतिक परिषद. इसमें कलाकार थे- श्रीमती मीना श्रीवास्तव, रामेंद्र मिश्र, गोपाल मेहता, मनोज मंजुल आदि. सन 1980 के दौर में एक पुरानी और मूलरूप से साहित्यकारों की संस्था अनामिका ने आधुनिक रंग मंच से शहर के नाट्यकर्मियों को जोड़ा. इसमें चर्चित कथाकार हृदयेश, आफताब अख्तर, आचार्य नित्यानंद मुग्दल, राजेश्वर सहाय बेदार, मोहिनी मोहन सक्सेना, अचल बाजपेई, राजेंद्र च्यवन, श्याम किशोर सेठ, चंद्र मोहन दिनेश, सुधीर विद्यार्थी, डा. इजहार सहबाई आदि शामिल थे. सन 1980 में अनामिका द्वारा लखनऊ के रंगकर्मी कमल वरिष्ठ के निर्देशन में रंगमंच प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें अभिनय प्रशिक्षण के साथ-साथ डॉ. असगर वजाहत कृत नाटक इन्ना की आवाज़ और अन्तोन चेखव कृत नाटक गिरगिट तैयार करवाया गया. सन 1984 में लखनऊ से अमरेंद्र सहाय कमर के निर्देशन में अगली कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें महिलाओं ने भी पहली बार प्रशिक्षण प्राप्त किया. इस कार्यशाला में जगदीश चंद्र माथुर कृत नाटक कोणार्क तैयार किया गया. जिसका सफ़ल मंचन शाहजहांपुर और वाराणसी में हुआ. सन 1985 में संस्था ने लखनऊ के रंग निर्देशक पीडी वर्मा के निर्देशन में शरद जोशी कृत नाटक एक था गधा... का मंचन किया. इस नाटक को देखने के लिए टिकट ब्लैक में भी बिके. वर्ष 1990 में अनामिका ने जबलपुर से निर्देशक डॉ. विश्वभावन देवलिया के निर्देशन में डॉ. धर्मवीर भारती कृत प्रसिद्ध नाटक अंधा युग का मंचन किया.

अनामिका की इस यात्रा में चंद्रमोहन दिनेश, महेश सक्सेना, असद उल्ला खां, चंद्र मोहन महेंद्रू, राधेश्याम श्रीवास्तव, राजकुमार शर्मा, सुशील शर्मा, खादिम शाहपुरे, मनोज कुमार मंजुल, प्रमोद प्रमिल, सतीश चंद्र सक्सेना, वीएस त्रिवेदी, राधेश्याम सक्सेना, रचना शर्मा, बबिता शुक्ला, वंदना अग्रवाल, सुदर्शन वर्मा, अनिल कक्कड़, ओपी वर्मा, विकास चावला आदि साथ रहे. 1986 में अनामिका के कुछ रंगकर्मियों वीएस त्रिवेदी, चंद्र मोहन महेंद्रू आदि ने मिलकर कोरोनेशन आर्ट थियेटर संस्था की स्थापना की और चंद्र मोहन महेंद्रू के निर्देशन में प्रमोशन नाटक का मंचन किया. 1987 में संस्था ने अनवर सादिक के निर्देशन में रवि वर्मा कृत नाटक दीमक का मंचन किया. बाद में टीम बिखरी और आनंद ने संगीत नाटक अकादमी लखनऊ से बी.एम. शाह से निर्देशन का प्रशिक्षण लेकर अपने निर्देशन में दीमक नाटक का मंचन किया. जिसने पहली बार अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ नाटक के साथ-साथ कई अन्य पुरस्कार भी जीते. दीमक नाटक के अब तक 30 से भी अधिक मंचन हो चुके हैं. कोरोनेशन ने तरुण राज के निर्देशन में इतिहास चक्र, विजय शुक्ला के निर्देशन में आला अफसर, राजपाल यादव के निर्देशन में आगा हश्र कश्मीरी कृत पारसी नाटक यहूदी की लड़की का सफलतम मंचन किया. इस संस्था ने इकतारे की आंख, बैंच शहंशाह इडिपस, गोदान, रामलीला, आह-रे हिंदुस्तान, त्रिशंकु, गज-फुट-इंच, सज़ा-ए-मौत, होली आदि मंचन किए. अभिनेता राजपाल यादव ने इसी संस्था से रंगमंचीय सफ़र शुरू किया. सतीश त्रिवेदी, जुनैद खां के अलावा कई अन्य अभिनेता इस संस्था से निकलकर बॉलीवुड में संघर्ष कर रहे हैं. शाहजहांपुर के रंगकर्म को इप्टा की संबद्ध इकाई कोरोनेशन आर्ट थियेटर ने बहुत समृद्ध किया. निर्देशक आनंद ने रंग परंपरा को गति दिया. नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी जनता में जागरूकता फैलाने का काम किया. देश में आई विपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी आदि को लेकर आर्थिक सहायता भी प्रदेश के राज्यपाल को भेजी. एक मौक़े पर संस्था के वालंटियर स्वयं लगभग 100 नग रेलवे से बुक कराकर ज़िलाधिकारी का पत्र लेकर भुज, गुजरात पहुंचे और राहत सामग्री का स्वयं वितरण किया. संस्था से जुड़े रंगकर्मियों की संख्या सैकड़ों में है, पर मुख्य रूप से रचना शर्मा, दिलीप आनंद, राजपाल यादव, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, शमीम आज़ाद, आजम खां, राजेंद्र बघेला, आसिफ सलीम, शाहशुजा खां, आशीष शुक्ला, अजय अवस्थी, गौरव खन्ना, आशुतोश मिश्र, स्व. अजय दीक्षित, संध्या पांडेय, सतीश त्रिवेदी, रमापति द्विवेदी सोती, बबिता बख्श, सोनी राजवंशी, प्रिया सिंह, अभिलाषा, वंदना शर्मा, सुरभि खुराना, शिखा राजवंशी, संगीता यादव, प्रमोद यादव, महेश वर्मा, दीपक तिवारी, अखिलेश रोहरा, सुरेंद्र शर्मा उर्फ़ सोनू, तारिक खान, सूरज राणा, कुलदीप तिवारी, जुनैद खां उर्फ राजा, दामोदर पाल, सचिन श्रीवास्तव, सर्वेंदर राज भदौरिया आदि उल्लेखनीय हैं. सन 1989 में रंगकर्मी वीएस त्रिवेदी ने नव ज्योति नाट्य कला मंदिर की स्थापना कर बिखरती पंखुड़ियां, तमाशा, स्वांग, अरे शरीफ लोग आदि नाटकों के मंचन किए. प्रमोद प्रमिल संस्थापित परिक्रमा द्वारा तमाशा, सिहासन खाली है, एक कुंवारा शादी का मारा, हमें बोलने दो, बकरी, कुणाल, और अग्नि शिखा के मंचन किए गए. मनोज मंजुल संस्थापित अनुभूति द्वारा मेरा नाम मथुरा है, कसाई बाड़ा, एक और द्रोणाचार्य आदि नाटक थे. रामेंद्र मिश्रा संस्थापित सुरभि नाट्य संस्था द्वारा अयोध्या, अब ग़रीबी हटाओ, दहेज आदि नाटक थे. गोपाल मेहता संस्थापित अभिनव संस्था द्वारा इंतकाम, सोपान कला परिषद द्वारा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, पांच पैर का सिक्का, सीढ़ियां आदि नाटक थे.

सन 1995 तक शाहजहांपुर के रंगकर्म में एक बड़ा बदलाव आया. जब बिहार प्रांत के नाट्य लेखक राजेश कुमार सरकारी नौकरी के दौरान इस ज़िले में आए. उन्होंने स्थानीय प्रतिभावान युवा रंगकर्मियों को एकत्रित कर स्वयं लिखित नाटकों के मंचन शुरू किए. राजेश के साथ आए रंगकर्मियों में कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, शमीम आजाद, आलोक सक्सेना, आजम खां, अरविंद चोला आदि ने मिलकर 15 अगस्त 1996 को एक नई संस्था अभिव्यक्ति की स्थापना की. इस संस्था ने अधिकांशतः राजेश के ही नाटक मंचित किए. जिन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए. उदाहरणतः आख़िरी सलाम, अंतिम युद्ध, गांधी ने कहा था, घर वापसी, हवन कुंड, कह रैदास, के साथ-साथ नुक्कड़ नाटक भ्रष्टाचार का अचार, एकल नाटक रसप्रिया, पूस की रात, टोबा टेक सिंह, भेड़िए, वैष्णव की फिसलन, राम की शक्ति पूजा, एक क्लर्क की मौत, पेशावर एक्सप्रेस, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी वगैरह के मंचन किए. पिछले दिनों तौकीर वारसी के निर्देशन में रुस्तम सोहराब और मोहन राकेश लिखित आलोक सक्सेना निर्देशित नाटक आषाढ़ का एक दिन, बूथ नं. 51, चंद्र मोहन महेंद्रू निर्देशत सिहासन खाली है, राकेश श्रीवास्तव निर्देशित महाभोज, ज़रूरत है श्रीमती की, मोअज्जम बेग निर्देशित डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.लड़की.काम, बबिता पांडेय के निर्देशन में दो कौड़ी का खेल, गुलिस्तां के निर्देशन में रोमियो जुलिएट, शमीम आज़ाद के निर्देशन में जाति ही पूछो साधु की के मंचन किए. अभिव्यक्ति से जुड़े प्रमुख रंगकर्मी हैं- कृष्ण कुमार कृष्णा, शमीम आज़ाद, आलोक सक्सेना, मो. आजम खां, अरविंद चोला, मोअज्जम बेग, कु. गुलिस्तां, रुचि दीक्षित, मधुमिता डे, संजीव सारांश, रफी खान, संजय सक्सेना, तौकीर वारसी, शाहनवाज खां, रौनक अली, मनीष मुनि, सुरेंद्र संभव, कप्तान कर्णधार, विनती सिंह, मजहर ख़ान, इकराम वारसी, राकेश राज, शाहिद अली, इजलाल खां, शाश्वत दीप, महताब, आमिर, शरीफ आदि. शाहजहांपुर में कुछ अन्य संस्थाएं बनी जिसमें कांस्टेलेशन आर्ट थियेटर, न्यू स्टार थियेटर, जिज्ञासा नाट्य परिषद, ढाई आखर रंगमंडल, आर्डनेंस ड्रामेटिक क्लब समिति, द्वारा कुछ नाट्य प्रस्तुतियां की गई जो कि क्रमशः अंधा कुआं, कोर्ट मार्शल, सूरज का सातवां घोड़ा, सत्य हरिश्चंद्र, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक आदि थी. बाद में बनी विमर्श संस्था द्वारा मेरा राजहंस घर वापसी आदि नाटकों के मंचन किए गए. इसमें आर्डनेंस ड्रामेटिक क्लब समिति और विमर्श लगातार सक्रिय हैं. चंद्र मोहन महेंद्रू की सरपरस्ती में अनामिका, एक बार फिर सक्रिय हो गई है- चंद्र मोहन महेंद्रू के निर्देशन में एक अधिकारी की मौत, भुवनेश्वर-दर-भुवनेश्वर आदि नाटकों के मंचन किए. वर्ष 2002 में शहर के युवा नाट्य निर्देशक आलोक सक्सेना ने एक नई संस्था संस्कृति की स्थापना की और अपने उस्ताद राजेश कुमार की तर्ज पर रंगकर्म की अलग शुरुआत की. राजेश कुमार के निर्देशन में मार पराजय, आलोक सक्सेना के निर्देशन में विजय तेंदुलकर कृत नाटक घासीराम कोतवाल डा. गिरीश कारनाड कृत अग्नि और बरखा राजेश कुमार कृत घर वापसी इंदुशेखर मिश्रा के निर्देशन में कमबख्त इश्क आदि नाटकों के सफ़ल मंचन किए. संस्था के रंगकर्मियों में मो. आजम खां, सौरभ अग्निहोत्री, मनोज यादव, आशीष द्विवेदी, स्नेहा संतोषी, गुलिस्तां, आरती सैनी, कप्तान कर्णधार, आलोक पांडेय, रवि सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सुदीप शुक्ला, नवल सक्सेना, आरएन त्यागी, आशा सोम, मनोज कार्तिक, रौनक अली, इंदुशेखर मिश्र, नवीन गुप्ता आदि के नाम जुड़ते हैं. शाहजहांपुर अब तक काकोरी कांड के अमर बलिदानी डा. रौशन सिंह, पं. राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां के नामों से जाना जाता था, पर अब रंगमंच के राष्ट्रीय मानचित्र पर भी अपना नाम दर्ज़ करा रहा है. पर इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि आर्थिक विपन्नता यहां के सैकड़ों रंगकर्मियों को निरंतर अखरती है. सरकार को चाहिए कि इस शहर में एक रंगमंडल की स्थापना करे, ताकि रंगकर्म इन रंगकर्मियों की रोज़ी-रोटी का साधन भी बन सके.

सन 1995 तक शाहजहांपुर के रंगकर्म में एक बड़ा बदलाव आया. जब बिहार प्रांत के नाट्य लेखक राजेश कुमार सरकारी नौकरी के दौरान इस ज़िले में आए. उन्होंने स्थानीय प्रतिभावान युवा रंगकर्मियों को एकत्रित कर स्वयं लिखित नाटकों के मंचन शुरू किए. राजेश के साथ आए रंगकर्मियों में कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, शमीम आज़ाद, आलोक सक्सेना, आजम खां, अरविंद चोला आदि ने मिलकर 15 अगस्त 1996 को एक नई संस्था अभिव्यक्ति की स्थापना की.

feedback@chauthiduniya.com

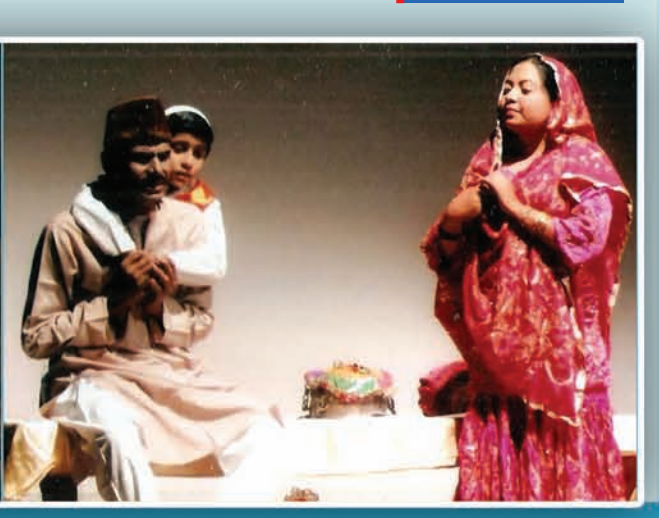

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 29 नवंबर-05 दिसंबर 2010

www.chauthiduniya.com

डंडा चला तो होगा संग्राम

फोटो-प्रभात पाण्डेय

जदयू के नाराज़ सांसदों ने आपस में ही एक-दूसरे का दिल टटोलने का काम शुरू कर दिया है. सूत्रों पर भरोसा करें तो इस मिशन में परस्पर विरोधी ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा भी साथ आ सकते हैं. इन दोनों के बीच की कड़ी ने बताया कि दोनों नेताओं से बात चल रही है और उचित समय पर आप चौंकाने वाली ख़बर सुनेंगे.

सरोज सिंह

चुनाव परिणाम आने के बाद अब नीतीश कुमार से नाराज़ जदयू सांसदों पर अनुशासन का डंडा चलाने की तैयारी तेज़ हो गई है. चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान पार्टी के ख़िलाफ़ काम करने वाले सांसदों, मंत्रियों और नेताओं को सबक सिखाने के लिए होमवर्क लगभग पूरा कर लिया गया है.

रणनीति यह है कि सभी विरोधियों को एक-एक करके सज़ा दी जाए ताकि विरोध का स्वर तेज़ न हो सके. दूसरी तरफ़ कुछ नाराज़ सांसदों का कहना है कि जदयू को बनाने में उनका योगदान किसी से कम नहीं है, इसलिए बिना वजह अगर कोई कार्रवाई हुई तो उसका ख़ामियाज़ा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा. कुछ सांसदों की नाराज़गी तो जगज़ाहिर थी, पर कुछ के चेहरे विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे और चुनाव प्रचार के दौरान साफ़ हो गए. इसमें सबसे बड़ा नाम उभरा उपेंद्र कुशवाहा का. राजगीर में कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान को लेकर जब उन्होंने ज़ुबान खोली तो उसी समय तय हो गया था उनकी राह अलग हो गई है. नाराज़गी में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अपना ज़्यादातर समय दिल्ली में गुज़ारा. उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार में खुलकर न आने से पार्टी को कई इलाक़ों में नुक़सान भी हुआ, पर नीतीश कुमार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी. अपने चाहने वालों को टिकट दिला पाने के कारण मोनाज़िर हसन, अर्जुन राय, पूर्णमासी राम, कैप्टन जयनारायण निषाद और मंगनीलाल मंडल ने मुंह फुला लिया. मोनाज़िर हसन ने तो अपनी पत्नी को राजद के टिकट पर चुनाव लड़वा दिया. ललन सिंह ने कई क्षेत्रों में अपने लोगों को कांग्रेस के टिकट दिलवाए और खुलकर कांग्रेस के लिए प्रचार किया. सांसद महाबली सिंह और सुशील कुमार सिंह भी जदयू के प्रचार अभियान से दूर ही रहे. इसी तरह अपने कुछ मंत्रियों और नेताओं की भी पार्टी विरोधी कामों की ख़बर नीतीश कुमार तक पहुंची है. जदयू की समझ है कि ऐसे लोगों ने पार्टी को लाभ की जगह नुक़सान ही पहुंचाया. नीतीश कुमार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और ऐसे लोगों को सज़ा देने की बात तय कर दी है. जदयू आलाकमान को लग रहा है कि दल विरोधी लोगों के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई पार्टी हित में है. इस कार्रवाई से जाने वाला संदेश जदयू की सेहत को मज़बूत करेगा. लेकिन कुछ नाराज़ सांसदों ने साफ़- साफ़ कहा कि जदयू केवल नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है. इस पार्टी को बनाने में नीतीश कुमार से ज़्यादा पसीना हम लोगों ने बहाया है. इसलिए कोई इस मुग़ालते में न रहे कि कोई हमें आसानी से पार्टी से बेदख़ल कर देगा. इन लोगों का दावा किया कि अगर नीतीश कुमार उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो फिर संग्राम होगा. चंपारण के एक नाराज़ सांसद बताते हैं कि परिवारवाद के ख़िलाफ़ नीतीश कुमार लंबा-लंबा भाषण देते थे, क्या हुआ इन भाषणों का? विधानसभा चुनाव में परिवारवाद खुलकर दिखाई दिया. जगदीश शर्मा पर कार्रवाई हुई, फिर क्यों कदम वापस खींच लिया गया. उनके बेटे को टिकट क्यों दिया गया. नीतीश कुमार मुंहदेखी काम करते हैं. दरअसल इन नाराज़ सांसदों के तेवर इन दिनों इसलिए भी तेज़ हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली में कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं ने एक बार फिर इन सांसदों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है. डीएमके प्रकरण को लेकर इन सांसदों की पूछ एक बार फिर बढ़ गई है. इन सांसदों ने कांग्रेसी नेताओं को भरोसा दिलाया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 14 सांसदों का समर्थन सरकार को दिला सकते हैं. जदयू सांसदों ने आपस में ही एक दूसरे का दिल टटोलने का काम शुरू कर दिया है. सूत्रों पर भरोसा करें तो इस मिशन में एक दूसरे के विरोधी ललन सिंह व उपेंद्र कुशवाहा भी साथ आ सकते हैं. इन दोनों की बीच की कड़ी ने बताया कि दोनों नेताओं से बात चल रही है और उचित समय पर आप चौंकाने वाली ख़बर सुनेंगे. दरअसल नाराज़ सांसद इतना दबाव बना देना चाहते हैं कि जदयू नेतृत्व चाहकर भी कार्रवाई का फ़ैसला नहीं ले सके. दूसरी तरफ़ जदयू हाईकमान हर हाल में कार्रवाई चाहता है ताकि पार्टी विरोधी कामों पर लगाम लगाई जा सके. नीतीश खेमे का मानना है कि पानी अब सिर के उपर से बह रहा है और ज़रा सी देरी भारी नुक़सान हो सकता है.

अब बात राजद के सांसदों की भी कर लेते हैं. लालू प्रसाद के लिए उनके सांसद भी संकट का सबब बन चुके हैं. उमाशंकर सिंह तो खुलकर लालू को फरिया लेने का न्योता दे चुके हैं. उन्होंने अपने समर्थकों को कांग्रेस का टिकट दिलाया और राजद के चुनाव प्रचार से दूर रहे. बताया जाता है कि उमाशंकर सिंह इतने आगे निकल चुके हैं कि उनका पीछे लौटना संभव नहीं दिखता. इसी तरह रघुवंश सिंह तो राजद के प्रचार में तो थे पर उनके भाई रघुपति ने कांग्रेस से चुनाव लड़कर लालू के साथ रिश्तों में खटास पैदा कर दी. लालू ने रघुवंश सिंह पर रघुपति के नाम वापसी के लिए पूरा दबाव बनाया, लेकिन बताया जाता है कि रघुपति ने बात नहीं मानी. सांसद जगदानंद के बेटे ने भाजपा से चुनाव लड़कर लालू व जगदानंद के लंबे दोस्ताने में दरार पैदा कर दी. हालांकि जगदानंद बार बार कह रहे कि मैं पूरी तरह राजद के साथ हूं पर क्षेत्र में जो संदेश चला गया उसे नहीं रोक पाए. राजद के चार सांसद हैं और तीन की कहानी उपर लिखी जा चुकी है. लालू चाहकर भी इन सांसदों पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह दिल्ली में अपनी गिनती और कम नहीं करना चाहते. इसलिए कोशिश है कि इन सांसदों से बात कर उनकी भावनाओं को समझा जाए और पूरी तरह राजद की घारा के साथ शामिल कर लिया जाए. देखा जाए तो सांसदों का संकट राजद से कहीं ज़्यादा जदयू में दिख रहा है. जदयू में यह संकट इस मोड़ पर है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं है. सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि कार्रवाई किस तरह और कितने चरण में होती है. जदयू हाईकमान का साहस यह तय करेगा कि वह संभावित वार को झेलने के लिए कितना तैयार है, क्योंकि कार्रवाई के घेरे में आने वाले सांसद पार्टी के फ़ैसले का स्वागत तो करने वाले नहीं है. जवाबी कार्रवाई के लिए यह नाराज़ सांसद भी अपना दिमाग़ लगाए हुए हैं .

इसलिए इतना तो तय है कि जदयू में घमासान होगा और इसमें किसको कितना नुक़सान होगा यह नाराज़ सांसदों पर चलने वाले आनुशासनिक डंडे के प्रहार से तय हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

कुछ नाराज़ सांसदों ने साफ़ कहा है कि जदयू केवल नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है. इसलिए कोई हमें आसानी से पार्टी से बेदख़ल नहीं कर सकता. इनका दावा है कि अगर नीतीश कुमार उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा क़दम उठाते हैं तो फिर संग्राम होगा.

ग्रामीणों का भी मानना है कि ज़िले में इन दिनों बच्चों पर मौत का साया मंडरा रहा है. एक के बाद एक कर बच्चे मौत की देहरी तक पहुंच रहे हैं.

ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लेकर कोई राजनीति नहीं होती, यही वजह है कि बिहार में ग़रीबी और विसंगतियां कुछ ज़्यादा ही हैं.

एक नज़र इधर भी

दादा, आप कहां गुम हो गए

दिग्विजय बाबू की जयंती पर पूरे प्रदेश के लोगों ने उन्हें नम आंखों से याद किया. जमुई स्थित उनके पैतृक गांव नया गांव स्थित समाधि स्थल पर लगी दादा की तस्वीर पर सैकड़ों लोगों ने पुष्प चढ़ाकर अपने प्रिय नेता को दिल से याद किया. गीता पाठ हुआ और ग़रीबों को खाना खिलाया गया. उन्हें याद करते हुए लोगों ने कहा का कि देश का सपूत समय से पहले न जाने कहां गुम हो गया. इस मौक़े पर डॉ. मनोज कुमार सिंह , प्रमोद सिंह , मुख्तार अंसारी, अशोक सिंह, मनोज सिंह, अजित सिंह, बलराम सिंह सहित बड़ी संख्या में दादा को चाहने वाले मौजूद थे.

पार परैया की समस्या बरक़रार

गया से परैया जाने वाले मार्ग पर नदी में वर्षों से अपेक्षित पड़े पुल के बन जाने के बावजूद भी पार परैया के लोगों की यातायात की समस्या का सामाधान नही हो पाया है. कारण है कि नदियों के बीच टापू के रूप में बसे पार परैया पंचायत मुख्यालय के लोगों को परैया बाज़ार जाने में आज भी नदी पार करना पड़ती है. इस बरसाती नदी में यदि पानी आ गया तो लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है और नदी पर बने रेल पुल से जान ज़ोखिम में डाल कर आना-जाना पड़ता है. इस बार के चुनाव में किसी दल के लोगों ने इस समस्या को मुद्दा नहीं बनाया. चुनाव समाप्त हो गया लेकिन यहां के लोगों को उम्मीद है कि नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि पार परैया के एक दर्जन से अधिक गांवों की इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान देगें और नदी में पुल बनेगा. *–शैलेंद्र कुमार मिश्रा*

शराबबंदी के लिए सड़क पर उतरे

महनार अनुमंडल क्षेत्र में ज़हरीली शराब से हुई मौत को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है. विरोध जताने के लिए पूर्व मंत्री मुंशीलाल राय अपने हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे. सुल्तानपुर से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक मौन जुलूस निकाला गया. मुंशीलाल राय ने मृतक के परिजनों को दस-दस लाख मुआवजा देने की मांग जताकर ऐलान किया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वह चुप नहीं बैठेंगें. राय के साथ वार्ड पार्षद जवाहर साह, अशोक राय, देवी पासवान आदि भी थे. *– अंजुम परवेज*

कलयुग के अवतार

वर्षों से आयोजित हो रहे गोपाष्टमी मेले में राम और श्याम नाम के दो जुड़वा भाई लोगों के आकर्षण का विषय बने रहे. दोनों की जान तो अलग-अलग हैं लेकिन जिस्म एक ही है. दरअसल गया निवासी ये जुड़वा भाई जन्म से ही इस कदर एक दूसरे से चिपके हुए हैं कि उन्हें सभी दैनिक कार्य साथ-साथ करने पड़ते है. हालांकि खाना अलग-अलग खाते हैं. भगवान की लीला के कारण यह दोनों भाई कलयुग का अवतार कहलाते हैं. देखने वाले लोग दोनों भाई के पीछे खड़ा होकर लुटाते हैं. दोनों भाइयों का भी मानना है कि भगवान ने उन्हें साथ-साथ जीने मरने के लिए पैदा किया है. जबकि इनकी मां का कहना है कि रुपए के अभाव में इनका ऑपरेशन नहीं हो सका. पिता इस बात की रहती है कि अगर एक भाई की मौत हुई तो फिर दूसरा क्या करेगा. बहरहाल, उनकी मां पैसे जमा करने के लिए मेले में दोनों बच्चों को लेकर जगह-जगह जाती है. *–सूर्यनारायण भारती*

ग़म में डूब गया सहरसा

दिल्ली के लक्ष्मीनगर की ललिता पार्क इमारत हादसे में सहरसा ज़िले के भटपुरा, भौरा और दिवारी गांव की कई महिलाओं की गोद सूनी हो गई तो कई के सुहाग उजड़ गए. ग़ौरतलब है कि सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के भटपुरा व भौरा गांव के अधिकांश परिवारों का चूल्हा दिल्ली की मज़दूरी से ही जलता है. इस गांव के क़रीब 500 से ज़्यादा लोग दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में भवन निर्माण से लेकर कई और कार्यों से जुड़े हैं. सोमवार 15 नवंबर की रात 8 बजे दिल्ली लक्ष्मीनगर से एक फोन आया कि सरदार अमृत सिंह की इमारत ढह गयी. ख़बर सुनते ही गांव में एक पल के लिए कोहराम मच गया. पर्व की वजह से इस इमारत में 5 दर्जन से कम लोग ही तत्काल ठहरे हुए थे. घटना की शाम भी करीब दो दर्जन मज़दूर किसी अन्य ठेकेदार के साथ मज़दूरी करने सरदार अमृत सिंह के होटल से बाहर निकल गये थे. वैसे इस हादसे में भटपुरा के जागो यादव, आदित्य यादव, लालजी यादव, हीरा यादव, बाल्मिकी यादव एवं दिवारी के मिथिलेश यादव का नाम शामिल है. जबकि भटपुरा के फूल झा यादव व भौरा के फोनटेन यादव लापता है. इसके अलावा भटपुरा के टुनटुन यादव व रविंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हैं. भटपुरा निवासी, भौरा निवासी परमजीत यादव व रविंद्र यादव व दिवारी निवासी भूपो यादव के पुत्र मिथिलेश यादव की मौत हो गयी. मौत से जहां पूरे गांव में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है, वहीं इस बात का मलाल भी है कि अगर मनरेगा योजना चलती रहती तो ऐसी नौबत नहीं आती. गांव के निवासियों का कहना है कि इस गांव में एक छटाक भी मनरेगा योजना कार्य जॉब कार्डधारी मज़दूरों से नहीं करवाया गया है. जिसके कारण गांव के यहां को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है. मृतकों, घायलों व लापता लोगों की सूची दिल्ली की सामाजिक संस्था पूर्वांचल युवा मंच के संस्थापक रितेश रंजन ने गांव भेजी है. *–रुपम सोनी*

फोटो–प्रभात पाण्डेय

अब हमारा काम बोलेगा-अर्जुन मुंडा

राजनैतिक अस्थिरता और विपरीत परिस्थितियों के कारण ही झारखंड का समुचित विकास नहीं हो पाया. दुनियावी समस्याओं का पूरा तरह निराकरण नहीं हो सका. यहां विकास की रफ्तार उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की तुलना में धीमी रही. एक पूरा दशक बीत गया और हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई. लेकिन अब और प्रतीक्षा नहीं करेंगे. यदि अब हम नया झारखंड बनाने की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए तो समय की धारा में बहुत पीछे छूट जाएंगे. आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी. झारखंड स्थापना दिवस समारोह के बाद चौथी दुनिया के साथ एक विशेष बातचीत के क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने यह बातें कहीं.

वह काफ़ी उत्साहित और आत्मविश्वास से लबरेज़ दिख रहे थे. अपनी सरकार की उम्र के संदर्भ में विपक्ष की टिप्पणियों पर उन्होंने कहा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और इसका प्रदर्शन अब तक की तमाम सरकारों से बेहतर होगा. उनके मुताबिक झारखंड के चहुंमुखी विकास का ब्लूप्रिंट तैयार है और इसे अमली जामा पहनाने के लिए कार्यपालिका सक्रिय है. सहयोगी दलों की भूमिका काफ़ी सकारात्मक है. कुछ कर गुजरने का जज़्बा सभी के अंदर है. सभी विकास की गति तेज़ करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं. सरकार में रचनात्मक प्रवृत्ति का संचार होने के कारण ही आपसी खींचातानी, राजनीतिक सौदेबाज़ी या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की घटनाएं कहीं नहीं दिख रही हैं. पूर्व की सरकारों में यह दृश्य आम थे.

भ्रष्टाचार और घोटालों के संबंध में पूछे जाने पर कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, उसकी गहन जांच कराई जा रही है. जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं. उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है. मैंने शपथ ग्रहण के दौरान ही कहा था कि भ्रष्ट लोगों को बख़्शा नहीं जाएगा. आप देखिए, एसएस फंड दुरुपयोग मामले की सीबीआई जांच के लिए नोटिफिकेशन करने का निर्देश आया तो हमने उसे किया. जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. जो दोषी होंगे, चाहे जितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हों, ज़रूर दंडित किए जाएंगे. राज्य में अधिक संपत्ति मामले के आरोपी मंत्रियों की संपत्ति ज़ब्त की जा रही है. भ्रष्ट लोगों को कहीं पनाह नहीं मिल रही है.

सरकार के गठन के पीछे पूंजीपतियों का हाथ होने के आरोपों से संबंधित प्रश्न पर प्रतिप्रश्न दाग़ते हुए मुंडा पूछते हैं कि क्या बीपीएल परिवारों को एक रुपया प्रति किलो अनाज देने की योजना, समाज के सबसे निचले तबके की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने का प्रयास पूंजीपतियों के इशारे पर किया जा सकता है. हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे किसी पूंजीपति का हित सधता हो. हम तो आम लोगों की समस्याओं को दूर करने, उन्हें बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं. पलायन को रोकने, रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने, कृषि और उद्योग को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं. पूंजीपतियों के सहयोग से बनी सरकारों का क्या यही एजेंडा होता है?

> मैंने शपथ ग्रहण के दौरान ही कहा था कि भ्रष्ट लोगों को बख़्शा नहीं जाएगा. आप देखिए, एसएस फंड दुरुपयोग मामले की सीबीआई जांच के लिए नोटिफिकेशन करने का निर्देश आया तो हमने उसे किया. जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. जो दोषी होंगे, चाहे जितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हों, ज़रूर दंडित किए जाएंगे.

चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागों की योजनाओं की राशि का 40 प्रतिशत भी ख़र्च नहीं हो पाने और मात्र तीन चार महीने का समय शेष रहने पर उनका उपयोग हो पाने की संभावनाओं के संबंध में मुंडा ने कहा कि चार महीने में भी कम से कम डेढ़ महीने पंचायत चुनाव के कारण लगी आचार संहिता की बंदिश में गुज़र जाएंगे. उसके बावजूद आवंटित राशि का पूरा उपयोग होगा. इसीलिए, मैं और हमारे मुख्य सचिव एक-एक सिंह लगातार सभी विभागों की समीक्षा बैठक कर योजनाओं को मूर्त रूप देने के काम में तेज़ी लाने की रणनीति तैयार करने में लगे हैं. सभी विभागों के अधिकारी कामकाज की गति तेज़ करने को चुनौती के रूप में ले रहे हैं. आप देखेंगे कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक किस रफ्तार से काम होता है.

माओवादी हिंसा में इज़ाफ़ा और अपराधिक वारदातों में बढ़ोत्तरी के कारण विधि व्यवस्था की गंभीर स्थिति के संबंध में मुंडा कहते हैं कि माओवादी नेता लगातार आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में आने का प्रयास कर रहे हैं. ऑपरेशन ग्रीन हंट सही ढंग से चल रहा है. क़ानून-व्यवस्था के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है. पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उसे जनता का सहयोग मिल रहा है. अपराधियों पर लगाम कसने का काम भी बख़ूबी हो रहा है. रंगदारी वसूली और अपहरण तथा फिरौती की मांग की घटनाओं में कमी आई है. अपराधियों के अंदर क़ानून का भय बढ़ा है. झारखंड को उग्रवाद और अपराध से मुक्त प्रदेश बनाने की कोशिश पूरी ईमानदारी और गंभीरता से की जा रही है. अभी इसमें थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन इस दिशा में अच्छी प्रगति है.

हम निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने में लगे हुए हैं. इसके लिए आधारभूत संरचना को विकसित करने का काम किया जा रहा है. हम दुरस्थ गांवों तक सड़कों का जाल बिछाने में लगे हैं. विद्युत उत्पादन को जीरो पावर कट की स्थिति तक पहुंचाने और झारखंड को पावर हब बनाने के लिए हम बंद थर्मल पावर प्लांटों को चालू कराने, उनकी क्षमता बढ़ाने और नए प्लांट लगाने का काम प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं. खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए कृषि क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है. इस वर्ष के सूखे और अकाल की स्थिति को देखते हुए हमने लंबित सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने, लघु सिंचाई योजनाओं को धरातल पर लाने, किसानों को समय पर उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक उपलब्ध कराने और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश तेज़ कर दी है. ग्रामीण इलाक़ों में पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, कुटीर उद्योग जैसे स्वरोज़गार प्रदायी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं. हमें विकास और ख़ुशहाली के मामले में झारखंड देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा. आख़िर में मुंडा कहते हैं कि हम काम में विश्वास करते हैं, विरोधियों की आलोचना पर ध्यान नहीं देते. अब हम नहीं हमारा काम बोलेगा.

नवल किशोर सिंह
feedback@chauthiduniya.com

रहस्यमय बीमारी का क़हर और...

राजेश सिन्हा

कोसी के दियारा इलाक़े में एक रहस्यमय बीमारी ने बच्चों को लीलना शुरू कर दिया है. स्वास्थ्य महकमे के लोगों ने भी अभी तक रहस्यमय बीमारी को या तो जानने का प्रयास नहीं किया है या इसके प्रति उदासीन रवैया अपनाया है. इतना ही नहीं अपना दामन दाग़दार होने से बचाने के लिए बच्चों की मौत के बाद दैवीय प्रकोप का हवाला देकर बच्चों के परिजनों को इस क़दर ख़ौफ़ज़दा करना शुरू का दिया है कि बच्चों के शवों का पोस्मार्टम कराने से भी परिजन न केवल कन्नी काटने लगे हैं बल्कि आनन फानन में शवों का दाह संस्कार भी करना शुरू कर दिया है. यह घटना तब सामने आई जब खगड़िया ज़िले के मुफसिल थाना अंतर्गत नन्हकू मंडल टोला में पिछले दिनों तीन बच्चों पर एक साथ कयामत आई, जब तक उनके माता-पिता कुछ समझ पाते तब तक तीनों की मौत हो चुकी थे. लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आख़िर बच्चों की मौत का कारण क्या था. बच्चे सामान्य बीमारी से भी ग्रसित होते हैं तो उनके माता पिता इलाज कराने के बजाए ओझा गुणी की शरण में जाने को विवश हो जाते हैं. ग्रामीणों का भी मानना है कि ज़िले में इन दिनों बच्चों पर मौत का साया मंडरा रहा है. एक के बाद एक कर बच्चे मौत की देहरी तक पहुंच रहे हैं. जब तक इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल लाया जाता है तब तक उनकी मौत हो जाती है. अभी तक उन तीन बच्चों की मौत का राज़ खुल भी नहीं पाया था कि अगले ही दिन एक और बच्चे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई. हालांकि इस बार बच्चे की मौत का कारण सर्पदंश बताया गया. स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि दियारा इलाक़े के डरे सहमे लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए भी घर से बाहर नहीं भेज रहे हैं.

हालांकि ऐसा होने की वजह भी है. स्थानीय सदर अस्पताल में बच्चों के दम तोड़ने के बाद भी ज़िला प्रशासन या स्वास्थ्य महकमे के लोगों ने उनका पोस्टमार्टम कराना तक गंवारा नहीं समझा. इतना ही नहीं उनकी मौत का कारण दैवीय प्रकोप बताकर चिकित्सकों ने उनके शवों को परिजनों के हाथों सौंप दिया और परिजनों ने आनन-फानन में शवों का दाह संस्कार कर दिया. हालांकि मीडिया में ख़बर आने के बाद ज़िलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक एक मेडिकल टीम के साथ हांफते-हांफते नन्हकू मंडल टोला पहुंचे और बच्चों की मौत का कारण समझने की ज़रूरत समझी. तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मृत बच्चों के परिजनों ने शवों का दाह संस्कार कर दिया था.

अभी भी यह सवाल सुलग रहा है कि आख़िर पोस्टमार्टम न करने के पीछे क्या राज था! क्या स्वास्थ्य महकमे और ज़िला प्रशासन के अधिकारियों के पांव शवों का पोस्टमार्टम करने के नाम पर थरथराने लगे थे, या कोई अन्य कारण था! कारण चाहे जो जो भी रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि क़ानून को ताक पर रखने के मामले में ज़िले के अधिकारियों ने एक अनोखा रिकार्ड कायम कर लिया है. यह बात ज़ाहिल से ज़ाहिल लोगों को भी पता है कि अगर किसी भी इंसान की मौत रहस्मय तरीके से होती है तो मौत का कारण जानने के लिए उनके शवों का पोस्टमार्टम किया जाता है. इसमें भी तब जब किसी तीन बच्चों की मौत सदर अस्पताल में हो तो फिर चिकित्सकों का कर्तव्य बन जाता है कि शवों का पोस्टमार्टम करे. दरअसल नन्हकू मंडल टोले के मुरली यादव का छह वर्षीय पुत्र नितेश कुमार और चार वर्षीय पुत्री कंचन कुमारी के साथ महेश्वरी यादव की तीन वर्षीय पुत्री मुस्कान सहित अन्य बच्चे सड़क किनारे खेल रहे थे. तभी इन तीनों के सिर में अचानक ज़ोर का दर्द उठा. दर्द की कराह सुनकर ग्रामीण भागे-भागे बच्चों के पास पहुंचे. कारण जानने के बाद जब तक बच्चों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी. बच्चों की हालत ख़राब होने के बाद मुफसिल थानाध्यक्ष राजेश रंजन भी अस्पताल पहुंचे लेकिन महज पंचनामा बनाकर बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराने की ज़हमत नहीं उठाई. इस संदर्भ में जब अस्पताल उपाधीक्षक जयदेव मंडल से बात की गई तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि बच्चों की मौत का कारण प्रथम दृष्टया कोई रहस्मय बीमारी लगती है, लेकिन बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है इसलिए मौत का स्पष्ट कारण बता पाना मुश्किल लगता है. जब उनसे पोस्टमार्टम के बारे पूछा तो उन्होंने तल्खी के साथ कह दिया कि किसी भी शव का पोस्टमार्टम कराना पुलिस का दायित्व है. इस संदर्भ में मुफसिल थानाध्यक्ष रंजन कुछ भी बताने से परहेज कर गए. लेकिन जब अनुमंडल पदाधिकारी सुशील कुमार से बात की गई तो उन्होंने माना कि पुलिस से चूक हुई है. नियम के मुताबिक़ मृत पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए. दोषी लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी.

वैसे एक बात सामने आई है कि पुलिस कप्तान सुधांशु कुमार ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष रंजन से जवाब मांगा है. ऐसा समझा जाता है कि अगर पुलिस कप्तान रंजन के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उन पर गाज भी गिर सकती है. बहरहाल, इस मामले में चूक किससे हुई, यह बहस का विषय नहीं है. बहस इस बात पर होनी चाहिए कि क्या ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा अपने कर्तव्य के प्रति वाकई गंभीर है.

feedback@chauthiduniya.com

कोहरे में लिपटी परदेसियों की उम्मीद

वतन से दूर, बीवी बच्चों से अलग, मां बहनों की नज़रों से ओझल एक परदेसी के लिए अपनी मिट्टी पर त्यौहार मनाने की ख़ुशी कुछ और ही होती है. वह भी ऐसे समय पर जब लोकतंत्र का महान पर्व यानी चुनाव साथ-साथ हो. नवंबर का महीना आख़िरी पड़ाव पर है. शबनम गिरना शुरू हो गई है, दिसंबर के कोहरे ने दस्तक दे दी है. दीवाली, छठ पूजा और बक़रीद का जश्न एक के बाद ख़त्म हो चुका है. बिहार विधानसभा चुनाव की धूल भी बैठ चुकी है. परिणाम भी साफ़ हो चुके हैं. इससे पहले तक हर शस्स अपनी पसन्द की सरकार बनाने में लगा था. सवाल पर सवाल हो रहे थे, लेकिन उन परदेसियों के मन को भी टटोलिए जो बहुत बड़ी संख्या में एक नए संकल्प और उत्साह के साथ वोट देने और त्यौहार मनाने के लिये घर आए थे. उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या लालू प्रसाद यादव. वह तो अपना निर्णय सुना चुके हैं, चुनावी परीक्षा में प्रत्याशियों को अंक दे चुके हैं. उनके सामने भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उनके प्रवासन और पलायन को कौन रोकेगा, उन्हें अपनी धरती पर रोज़गार कौन देगा? पढ़े लिखे को काग़ज़ के टुकड़े पर दो वक़्त की रोटी कौन मुहैया करायेगा, त्यौहार और चुनाव से पूर्व जिस जोश और भावना के साथ वह घर लौटे थे वह मायूसी में बदल गई है.

बेरोज़गारों की यह खेप अब रूख़स्त-ए-सफ़र बांध रही है. रेलों में भर-भर कर यह कोच कर रहे हैं. उन्हें फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई की उन्हीं अंधेरी गलियों में जाना है, जहां वह अपना सब कुछ न्यौछावर करके दूसरों के मुकद्दर चमकाने में लगे हैं. परदेसियों ने तो 45 साला कांग्रेस की सत्ता भी देखी है, राबड़ी के 15 सालों की सत्ता से भी वास्ता रहा है और सुशासन बाबू नीतीश कुमार की 5 साल में किए गए कार्य भी उनके सामने है. अतीत की रोशनी में एक बार फिर उन्हें अपना भविष्य कोहरों में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है. परदेसियों की उम्मीदों पर लगा यह कुहासा कौन साफ़ करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता. कहने को तो सभी ने चुनावी घोषणा पत्र में रोज़गार उपलब्ध कराने की गारंटी दी और चुनावी रैलियों में चीख़-चीख़ कर पलायन रोकने की बात कही लेकिन यह तो सियासी वादे हैं. वादा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया था कि सरकार बनते ही बेरोज़गार का पलायन रोकने के लिए बंद पड़ी चीनी मिलें दोबारा खोलेंगे, फैक्टरी, कारखाने लगाएंगे, नए उद्योग स्थापित करेंगे, लेकिन पूरे बिहार में घूमिए कहीं भी आपको चिमनियों से धुंआ निकलता हुआ नज़र नहीं आएगा. हां, सड़कों के किनारे शराब के नशे में धुत नौजवानों के हाथों में बीड़ी का धुआं ज़रूर दिखाई देगा. मैं यह नहीं कहती कि नीतीश कुमार ने नए बिहार के निर्माण के लिये कुछ नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना और बिहार के आतंकित माहौल को बदलने में उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है वह तारीफ़ के लायक़ है. हां, रिश्वतख़ोरी और अफसरशाहों पर नकेल कसने में वह पूरी तरह नाकाम रहे.

शांति किसे पसंद नहीं, ख़ुशहाली कौन नहीं चाहता, विकास से किसको इंकार है. उच्चशिक्षा, खूबसूरत सड़कें, बिजली की रोशनी, इलाज की व्यवस्था, रोज़गार के अवसर, इंसाफ़ और क़ानून, ख़ौफ़ से पाक माहौल और दो वक़्त की रोटी सब को चाहिए. जिंदगी की उन्हीं बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बिहार की जनता दिल्ली, पंजाब और मुंबई की अंधेरी गलियों में अपना खून पसीना बहाकर दूसरों का मुक़द्दर चमका रहे हैं. विकास को कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी या धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. सड़कें बनती हैं तो इस पर गाड़ी चलाने वालों की निजी पहचान नहीं पूछी जाती, रोज़गार के अवसर घर के पास निकलते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें ही होता है जो रोज़ी-रोटी के लिए अपनी मिट्टी से कोसों दूर हैं. गुंडाराज बंद होता है तो हर कोई चैन की नींद सोता है. इंसाफ और कानूनी व्यवस्था की स्थापना, उचित रोज़गार, जनता का अधिकार यह सभी शब्द बिहार से ग़ायब हो गए हैं. बिहार के बारे में दूसरे राज्यों का नज़रिया कुछ और ही है, वह बिहार के नाम से नफ़रत करते हैं, पढ़े लिखे लोग अपनी पहचान छुपाते हैं, बिहारियों से दोस्ती करने से लोग कतराते हैं. उनका मानना है कि बिहार जाओगे तो लूट लिए जाओगे, अपहरण होगा, 10 किलोमीटर सफ़र तय करने में घंटों लगेंगे. पुलिस अफ़सर भ्रष्ट, रिश्वतख़ोर और राजनीतिज्ञ मुफ़ादपरस्त हैं.

त्योहार और चुनाव के ख़त्म होने के साथ ही एक बार फिर रोज़ी-रोटी कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, बिहार से जाने वाली हर ट्रेन मज़दूरों और बेरोज़गार नौजवानों से भरी पड़ी है. सीमांचल से सुरजापुर गांव से एक नौजवान रूस्तम अली परदेस कमाने के लिए जा रहा है, सबकी आंखें नम हैं कि आज फिर एक और जवान गांव में कम हो जायेगा. मैंने जब पूछा बूढ़े मां बाप को छोड़कर क्यों जा रहे हो तो वह बोला कि यहां रहकर तो हम भूखे मर जाएंगे, बाहर जाकर कमाएंगे और घरवालों को पैसा देंगे, ताकि जिंदगी तो चलती रहे. हालांकि यह बिहार की संस्कृति है कि आने वालों का स्वागत और जाने वालों की विदाई यादगार तरीके से होती है, लेकिन आज की तारीख़ में पलायन इस सांस्कृतिक परंपरा पर भारी पड़ रहा है. रोज़ी-रोटी के लिए परदेस जाने का दर्द पूरे उत्तरी बिहार का है. क्या पूर्निया, किशनगंज, अररिया, गया, बेगूसराय, भागलपुर, मधुबनी. सड़कों और गांवों के चौक चौराहों पर इन दिनों परदेसियों को विदा करने का दर्द भरा मंज़र आम हो गया है. गांव के बूढ़े, बुजुर्ग बिहार सरकारों को कोसते हैं, जो उनके जिगर के टुकड़े को रोज़गार उपलब्ध कराने में नाकाम हैं.

ग़ौरतलब है कि यहां के लोगों में मानवशक्ति, सोच और क्षमता की कमी नहीं, ज़मीन का सीना चीरकर अपनी तक़दीर बदलने का हुनर ख़ूब आता है. दुनिया में मशहूर है कि एक बिहारी सब पर भारी. इसकी मिसाल देखनी हो तो देश के बड़े शहरों में जाकर देखिए जहां अपना सब कुछ खोकर बिहारी किसी का मुकद्दर संवारने में लगे हुए हैं. कुछ सालों पहले दिसंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश का सफ़र हुआ था, बर्फबारी शबाब पर थी, वहां मैंने देखा 10 से 20 लोग सिर्फ़ एक सूती चादर ओढ़े सड़कों के निर्माण में लगे हैं, पूछा तो पता चला कि यह सब बिहारी हैं. पेट की आग की तपिश के सामने बर्फानी तूफ़ान और सर्दी उनके लिए बेमाने थी. 17 प्रतिशत आबादी वाले मुस्लिम मतदाता इस बार भी उलझन में हैं, क्योंकि वह भी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं बन सके. राजनीतिक पार्टियों ने फिर इन्हें बड़ी आसानी से मूर्ख बनाकर बिखराब का शिकार बना लिया. मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जहां ज़रा सूझ-बूझ से काम लिया जाता तो अधिकतर सीटों पर नका क़ब्ज़ा होता और मुस्लिम विधायकों की संख्या में भी इज़ाफ़ा होता लेकिन ऐसा नहीं हो सका, उनके बिखराब का राज़ धीरे-धीरे खुलता जा रहा है.

हालात जो भी हों, लेकिन परदेसी नम आंखों से मन मारकर चले गए. सर्दी बढ़ने के साथ उनकी उम्मीदें कोहरों में धुंधलाती जाएंगी.

फरजाना परवीन
feedback@chauthiduniya.com

रोज़ी-रोटी के मुद्दे बेकार उड़नखटोले की महिमा अपरंपार

इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में याद किया जाएगा. आर्थिक व शैक्षणिक रूप से देश के सबसे पिछड़े हुए इस राज्य में अबतक हुए पांच चरणों के चुनाव में कई ऐसे आयाम नज़र आए, जिससे लोकतंत्र शर्मसार होता दिखा. भुखमरी, ग़रीबी, बेरोज़गारी और अशिक्षा का दंश झेल रहे इस राज्य का चुनावी जंग आसमान से लड़ा गया. देश के सबसे ग़रीब राज्य की राजनीति करने वाले राजनेता सड़कों से चलकर नहीं आसमान में उड़कर जनता तक अपनी बात कहने पहुंचे. यही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की मूलभूत समस्याओं की जगह व्यक्तिगत छींटाकशी ही ज़्यादा हावी रही. यह एक कड़वी सच्चाई है कि राज्य की एक बड़ी आबादी आज भी एक वक़्त रोटी पर गुज़ारने पर मजबूर है. उत्तरी बिहार की जनता बाढ़ से तबाह है तो दक्षिणी बिहार सूखे से त्रस्त. लेकिन राजनेताओं के लिए यह विशेष महत्व नहीं रखता. फ़िलहाल जो हो, इस चुनाव में राज्य की जनता ने अबतक जिन अभिनेता और अभिनेत्रियों के केवल नाम सुने थे, इस बार इनका दीदार भी करने का मौक़ा मिल रहा है. भले ही नेता धरती पर विकास को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहें हों पर आसमान में अपने विकास से यहां की जनता को रूबरू करा रहे हैं. जनता को अपने नेताओं का यह अहसान मान लेना चाहिए कि रोटी के लिए जारी जंग के दिनों में उन्हें आसमान में रंगबिरंगे उड़नखटोलों की बारात के दर्शन हो रहे हैं. राज्य में इन दिनों ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लेकर कोई राजनीति नहीं होती यही वजह है कि बिहार में ग़रीबी और विसंगतियां कुछ ज़्यादा ही है. ऐसे में विकास, रोजी-रोटी की समस्या, बिजली की स्थिति, उद्योग धंधों का न लगना इन सभी मुद्दों को छोड़ कर कोई भी पार्टी अपने चुनावी भाषण में जिक्र करने के बजाए एक दूसरे पर छींटाकशी करने में लगे हैं. लेकिन एक बात साफ़ है कि 15 वर्षों के शासन काल के बाद बिहार में नीतीश सरकार में कुछ तो विकास हुआ है. हालांकि इसे सभी पार्टियां झुठला रहीं है. वह भी जनता से अपील कर रही हैं कि अगर एक मौक़ा दें तो बिहार को चमका दूंगा. समझने वाली बात यह है कि बिहार में 4 प्रतिशत लोग ग़रीबी रेखा से नीचे गुज़र-बसर करते हैं. ऐसी स्थिति में नेता हवा में उड़ान भर कर करोड़ों रुपया बहा रहे हैं. बिहार के चुनाव प्रचार में जहां प्रतिदिन हेलीकॉप्टर पर 16 लाख रुपया ख़र्च हो रहे हैं. यहां पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सभी पार्टियों ने उड़न खटोले का भरपूर इस्तेमाल किया है. कांग्रेस -4, बीजेपी-3, जेडीयू-3, राजद-2, लोजपा-1, एनसीपी-1, बीएसपी-1, जेडीएस-1 इसके यदि ख़र्च पर नज़र डाली जाए तो दस हज़ार प्रति घंटा रहा है. यदि इन ख़र्चों का अंदाज़ा लगाया जाए तो यह ख़र्च लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में आएगा. इससे तो साफ़ ज़ाहिर होता है कि बिहार के चुनाव प्रचार में जिस तरह छोटे-छोटे नेताओं ने भी हेलीकॉप्टरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया. एक बात उल्लेखनीय है कि कुछ जानी-मानी पार्टियों के विधायकों के पास करोड़ों से अधिक संपत्ति है. इसके बावजूद बिहार में लोग ग़रीबी और भुखमरी से मरते हैं. बताया जाता है कि इस बार भी बिहार के कई भ्रष्ट व्यापारियों, ठेकेदारों व अपराधियों ने पैसे देकर प्रमुख दलों से टिकट ख़रीदे. ऐसी स्थिति में बिहार की जनता को यह तय करना होगा कि कौन सा ऐसा नेता होगा जो कि मनोदशा की स्थिति को समझ सके. फ़िलहाल तो हम यही जानने को उत्सुक हैं कि हवा में उड़ने का किसको क्या लाभ मिलेगा.

संदीप कुमार
feedback@chauthiduniya.com

Mr. Manoj Jayaswal
Chairman

हर कदम पर हो विकास
यही है हमारा विश्वास...

Mr. Arun Gupta
CEO

झारखण्ड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर झारखंडवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

Abhijeet group, an emerging and fast growing conglomerate in India having significant presence in the State of Jharkhand, West Bengal, Bihar & Andhrapradesh. It is a well diversified business entity, primarily engaged in the core sector of

- Power - Mining - Steel
- Ferro Alloys - Roads - Cement

ABHIJEET
Vision Unlimited • Growth Infinite

NAGPUR OFFICE :
Landmark Building, Level 5, Wardha Road, Ramdaspeth, Nagpur - 440010.
Ph.: +91 712 664 1400, Fax : +91 712 663 9416

RANCHI OFFICE :
8th & 9th Floor, Mahabir Tower, Main Road, Ranchi - 834 001, Jharkhand
Ph.: +91 651 233 1113, Fax : +91 651 233 1113 / 18

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

बाबा वैद्यनाथ की श्रंगार पूजा हेतु नागपुष्प मुकुट निर्मित करने की व्यवस्था की गई, तभी से जेल में क़ैदियों के हाथ से बने नागपुष्प मुकुट को चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई.

मिथिलांचल सामा चकेबा की धूम

विकास कुमार

मिथिलांचल में छठ पर्व की समाप्ति के बाद भाई–बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक लोकपर्व सामा चकेबा मनाने की पुरानी परंपरा आज भी कायम है. कार्तिक पूर्णिमा तक सामा चकेबा के सुमधुर गीतों से मिथिलांचल का चप्पा–चप्पा गूंजने लगता है. इस पर्व को लेकर महिलाओं और युवतियों में ग़ज़ब का उत्साह देखा जाता है. बहनें अपने भाईयों के लिए दीर्घ एवं सुखमय जीवन की मंगलकामना करती हैं. संध्या ढलने के बाद बहनें सामा चकेबा, सतभईया, चुगला, वृंदावन, चौकीदार, झाझी कुकुर, सांभ आदि की मूर्तियां बांस की बनी चंगेरी में रखती हैं. इसके बाद जोते हुए खेतों में जुटकर पारंपरिक सामा चकेबा गीतों को गाने के लिए बैठती हैं. फूस एवं खड़ से निर्मित वृंदावन में आग लगाने और बुझाने की रश्म अदा की जाती है. इस दौरान महिलाएं और युवतियां पूरे उत्साह में वृंदावन में आग लागल कोई न बुझावै हो... हमरो से बड़का भैया दौड़ल चले आवई है... हाय सुवर्ण लोटा वृंदावन बुझावै है..... आदि गीत गाती हैं. तत्पश्चात बहनें संठी से चुगला को गाली देते हुए उसकी दाढ़ी में आग लगाती हैं और गाती हैं चुगला करे चुगली बिलैया करे म्यांव–म्यांव. इसके अलावा सामा खेलय गेलहुं भैया के आंगन भौजी लेलनि ललुआय...., साम–चक सामचक अईह हे–जोतला खेत में बैसिह हे–बैसिह हे आदि सामा चकेबा के कुछ प्रचलित लोक गीत हैं. इन रस्मों की अदायगी के बाद देर रात सामा चकेबा की मूर्ति का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है. उसे खाने के लिए हरे–हरे धान की बालियां दी जाती हैं और रात्रि में इसे ओस (शीत) में छोड़ दिया जाता है. सुबह होने पर फिर से मूर्ति को घर के अंदर रखा जाता है.

कार्तिक पूर्णिमा के दिन सामा चकेबा लोक पर्व का विधिवत एवं पारंपरिक रूप से समापन होता है, जिसमें महिलाएं एवं युवतियां अपने–अपने चंगेरी में सामा को सजा–धजाकर चकेबा के साथ विवाह की रस्म अदा कराती हैं. फिर नियत स्थानों पर कोहबर करती हैं. सामा खेलने वाली बहनें अपने भाईयों के घुटने पर मिट्टी से निर्मित चकेबा की मूर्ति को तोड़कर नदी–सरोवरों में बैंड–बाजों के साथ केला के थंब से बने बेड़ों में रखकर प्रवाहित कर देती हैं. केले के थंब से बनी बेड़ें कमल का फूल, नाव, हंस, दो मंजिला–तीन मंजिला घर आदि स्वरूपों में बनी होती हैं. इसके बाद बहनें अपने भाईयों को सामा का भेजा हुआ संदेश चूड़ा, मुरही, बताशा, गुड़ आदि से फांड़ा (जेब) भरती हैं. विसर्जन या नदी में प्रवाहित करने के दौरान महिलाएं और युवतियां सामा चकेबा से पुन: अगले साल आने का अनुरोध करती हैं.

इस लोक पर्व से संबंधित कई प्रकार की दंतकथाएं भी प्रचलित हैं. ऐसी ही कथा में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण की पुत्री श्यामा ऋषि कुमार चारूदत्त से ब्याही गईं. श्यामा ऋषि–मुनियों की सेवा करने उनके आश्रम में हमेशा जाया करती थीं. यह बात दुष्ट स्वभाव के मंत्री चुरक को पसंद नहीं आई. उसने श्रीकृष्ण के कान श्यामा के ख़िलाफ़ भरने प्रारंभ कर दिए. क्रोधित होकर श्रीकृष्ण ने श्यामा को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया. श्यामा के पति चारूदत्त ने महादेव की पूजा अराधना के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर स्वयं भी पक्षी का रूप ले लिया. श्यामा के भाई ने अपनी बहन–बहनोई की इस दशा से दुखी होकर अपने पिता की ही अराधना प्रारंभ की, जिससे प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उससे वर मांगने को कहा. तब उसने अपने बहन–बहनोई को मानव रूप में वापस लाने का वरदान मांगा. श्रीकृष्ण को जब पूरी सच्चाई का पता चला तो उन्होंने श्राप से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा कि सामा पक्षी रूपी श्यामा एवं चकेबा रूपी चारूदत्त की मूर्ति बनाकर उनके गीत गाएं और चुरक की कारगुजारियों को उजागर करें तो दोनों पुन: अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे. सामा चकेबा पक्षी की जोड़ियां तब तक मिथिला प्रवास करने पहुंच गईं थीं. भाई शांभ उसे खोजते–खोजते मिथिलांचल पहुंचे और वहां की महिलाओं से अपने बहन–बहनोई को श्रापमुक्त करने के लिए सामा चकेबा खेलने का आग्रह किया. बताया जाता है कि तभी से ही मिथिलांचल में इस लोक पर्व का आयोजन श्रद्धा एवं उल्लासपूर्वक हो रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

बाबा वैद्यनाथ का मुकुट क़ैदी बनाते हैं

द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ की महिमा से अंग्रेज भी अभिभूत थे. कई अंग्रेज अफसरों ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा–अर्चना के साथ–साथ शिवभक्ति की कई मिशालें पेश कीं. ऐसी ही एक मिशाल है बाबा वैद्यनाथ पर प्रतिदिन संध्या समय श्रंगार पूजा में चढ़ने वाले पुष्प से बने नाग मुकुट की. इस मुकुट को अंग्रेजों के शासन काल से ही प्रतिदिन जेल के क़ैदी बनाकर बाबा मंदिर ले जाते हैं और बाबा वैद्यनाथ पर चढ़ाते हैं. विद्वानों के अनुसार देवघर जेल से नागमुकुट पुष्प बनाकर बाबा पर चढ़ाने की परंपरा सरदार पंडा सदुपाध्याय शैलजानंद ओझा के समय में प्रारंभ हुई है. सिद्धपुरुष व त्रिपुर सुंदरी मां दुर्गा के अनन्य उपासक सर्वानंद ओझाजी को भक्तजन बाबा वैद्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में मानते थे. सन 1888 ईसवी के अगस्त में अंग्रेज अफसर लेफ्टीनेंट गवर्नर स्टुआर्ट वेले सर्वानंद ओझाजी की प्रसिद्धि सुनकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आए थे. कहते हैं कि वेले का इकलौता पुत्र किसी युद्ध में लापता हो गया था. तब वेले ने अपने पुत्र की सकुशल वापसी का आशीर्वाद मठाधीश से मांगा था. कुछ ही दिनों के बाद वेले का पुत्र सकुशल वापस आ गया. इस घटना से वह काफ़ी प्रभावित हुआ. उसी समय से ही वायसराय के आदेश से प्रतिदिन जेल से नागमुकुट पुष्प क़ैदियों के द्वारा बनाकर बाबा मंदिर लाया जाता है. सर्वानंद ओझाजी से आशीर्वाद प्राप्त करने वालों में अंग्रेज अफसर विलियम स्मिथ और भागलपुर कमिश्नर अलेक्जेंडर भी थे.

इस संबंध में एक और जनश्रुति है कि सन 1823 से 1837 के मध्य में देवघर जेल के एक अधिकारी का पुत्र अंग्रेज फौज़ में कैप्टन था. एक बार वह किसी लड़ाई में ब्रिटिश सेना की ओर से जहाज से दक्षिण अफ्रीका गया. युद्ध के बाद जहाज वापस नहीं आया. अफ़वाह फैली की जहाज डूब गया है. जेल अधिकारी को चिंतित देख जेल के सिपाहियों ने उसे तत्कालीन मठाधीश सर्वानंद ओझा के पास जाकर पुत्र वापसी का आशीर्वाद लेने की सलाह दी. प्रसिद्ध तांत्रिक व मठाधीश सर्वानंद ओझा ने जेल अधिकारी को बाबा वैद्यनाथ की उपासना करने को कहा और आशीर्वाद भी दिया. जेल अधिकारी ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की. शीघ्र ही उसका पुत्र वापस आ गया और उसने बताया कि भयंकर तूफ़ान से वह किसी ईश्वरीय चमत्कार की वजह से ही बच पाया. उस अधिकारी के मन में बाबा वैद्यनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ी. उस दिन बाबा वैद्यनाथ की श्रंगार पूजा हेतु नागपुष्प मुकुट निर्मित करने की व्यवस्था की गई. और तभी से ही जेल में क़ैदियों के हाथ से बने नागपुष्प मुकुट को चढ़ाने की परंपरा शुरु हो गई.

देवघर जेल में क़ैदी नागपुष्प मुकुट बनाने का काम बड़ी श्रद्धापूर्वक करते हैं. एक साफ़ सुथरे कमरे में चारों ओर धार्मिक पवित्रता झलकती है. प्रात:काल से ही चार पांच क़ैदी फूल तोड़ने में लग जाते हैं. शहर के कई लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक फूल प्रदान करते हैं. दोपहर में मुकुट निर्माण के पश्चात शाम 4 बजे बम भोले के जयकारों के साथ दो क़ैदी नागपुष्प मुकुट उठाकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर ले जाते हैं जहां यह मुकुट श्रंगार पूजा में चढ़ाया जाता है. ग़ौरतलब है कि देश के किसी भी ज्योतिर्लिंग में इस तरह की अनूठी परंपरा नहीं है.

रणजीत झा
feedback@chauthiduniya.com